चिंतन

विजय के लिए चुनावी वादे निभाना बड़ी चुनौती

तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय थलापति (सी. जोसेफ विजय) का उदय केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि राज्य की पारंपरिक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। उन्होंने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। दो साल पुरानी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि जनता अब पुराने राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़कर नए विकल्प तलाश रही है, लेकिन अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता से किए गए भारी-भरकम वादों को पूरा करने की है। तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है। डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियों ने राज्य की सत्ता को लगभग अपने बीच ही सीमित रखा। ऐसे में विजय का मुख्यमंत्री बनना ऐतिहासिक माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में लोकप्रियता जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से जनता उम्मीदें भी पाल लेती है। यही उम्मीदें अब विजय सरकार की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली हैं। टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल जैसे दलों का समर्थन लेना पड़ा। फिलहाल सरकार संख्या बल पर सुरक्षित दिखाई देती है, लेकिन गठबंधन सरकारों में स्थिरता हमेशा एक चुनौती होती है। इससे भी बड़ी चुनौती उनकी चुनावी घोषणाएं हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता, प्रत्येक परिवार को छह मुफ्त गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी जैसी योजनाएं सुनने में आकर्षक जरूर लगती हैं, लेकिन इनके लिए भारी बजट की आवश्यकता होगी। तमिलनाडु पहले से ही घाटे और कर्ज के दबाव से गुजर रहा है। ऐसे में यदि सरकार केवल लोकलुभावन योजनाओं पर अधिक ध्यान देती है तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक विजय को केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल रखने की सलाह दे रहे हैं। उसे बुनियादी ढांचे, निवेश, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, शिक्षा नीति और रोजगार परियोजनाओं के लिए केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है। यदि विजय केंद्र के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखते हैं तो राज्य को आर्थिक सहायता और नई परियोजनाओं का लाभ मिल सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह संबंध महत्वपूर्ण होंगे। अल्पमत जैसी स्थिति में किसी भी सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए दिल्ली से अच्छे रिश्ते अप्रत्यक्ष रूप से मददगार साबित होते हैं। इसलिए विजय को भावनात्मक राजनीति के बजाय व्यावहारिक और संतुलित राजनीति अपनानी होगी। दूसरी तरफ, प्रशासनिक अनुभव की कमी भी विजय के सामने बड़ी चुनौती है। फिल्मों में नायक बनना और वास्तविक शासन चलाना दो अलग-अलग बातें हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार की कार्यशैली जल्द ही परखी जाएगी। यदि सरकार वादों को समय पर पूरा नहीं कर पाई तो जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। तमिलनाडु की जनता ने विजय को केवल अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव के प्रतीक के रूप में सत्ता सौंपी है, लेकिन राजनीति में असली पहचान लोकप्रियता से नहीं, बल्कि शासन क्षमता से बनती है। विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों, आर्थिक संतुलन, गठबंधन की मजबूरियों और प्रशासनिक अनुभव की कमी के बीच सही रास्ता चुनने की है।

चुनावी हिंसा से कब मिलेगी मुक्ति?

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

पचहत्तर बरस पुराना भारतीय लोकतंत्र तमाम सुधारों के बावजूद आज भी चुनावी हिंसा जैसे बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लेकिन बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद एक बार फिर से चुनावी हिंसा और अराजकता भड़क उठी। बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस 'टीएमसी' के करारी हार के बाद भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की अनेक घटनाएं हुई है। हिंसा के बीच भाजपा के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हिंसा में अभी तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है तथा पुलिस सहित अनेक लोग घायल हुए हैं। हिंसा के दौरान घरों और पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़, आगजनी तथा बमबाजी की घटनाएं हुई है। राज्य में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा के 200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है वहीं 1100 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। बंगाल की नयी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता इस चुनावी हिंसा पर काबू पाना होगा। हालांकि सरकार ने इस दिशा में ताबड़तोड़ प्रयास शुरू कर दिया है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल देश विभाजन के बाद से ही हिंसा के लंबे दौर का गवाह रहा है। इस राज्य में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। राज्य में लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगरीय प्रशासन और पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा आम बात है। साल 1967 में नक्सलबाड़ी में किसानों के शोषण के विरोध में पैदा हुआ नक्सलवादी आंदोलन ने पूरे देश में हिंसा को एक नया स्वरूप दे दिया था जिससे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य भी प्रभावित रहे। 1971 में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ा लेकिन इसके बाद राज्य में राजनीतिक हत्याओं और हिंसा का दौर शुरू हो गया। सत्तर के दशक में राज्य में वामपंथ की जड़ें मजबूत होने के बाद लेफ्ट पार्टियों ने चुनावी नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए हिंसा को बढ़ावा दिया। बंगाल की सत्ता में वाम मोर्चा के काबिज होने के बाद 1977 से 2011 तक कोई भी चुनाव हिंसा मुक्त नहीं रहा बल्कि इन 34 सालों के दौरान राजनीतिक हत्याएं और झड़पें आम थी। इस दौर में सत्तारूढ़ पार्टी पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के आरोप लगातार लगते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1977 से 1996 तक राज्य में 28 हजार लोगों की मौत राजनीतिक हिंसा में हुई। एक अन्य जानकारी के मुताबिक 2016 से 2026 तक बंगाल में चुनावी हिंसा का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ा है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में 172 मामले दर्ज हुए तो 2021 के चुनाव में बढ़कर 278 हो गई। चुनावी हिंसा में बढ़ोतरी पंचायत चुनावों में भी देखी गई।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक पटल पर साल 1998 में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ। साल 2011 में सत्ता में 'टीएमसी' के काबिज होने के बाद भी राज्य में राजनीतिक और चुनावी हिंसा का पैटर्न नहीं बदला बल्कि इस पार्टी ने भी राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हिंसा को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो ममता बनर्जी की पार्टी ने विभिन्न चुनावों के दौरान और इसके बाद भी विरोधियों को धमकाने के लिए हिंसा की सारी हदें लांघ दी। टीएमसी सरकार के दौरान राज्य में घटित राजनीतिक और गैर राजनीतिक हिंसा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जबरिया जमीन हथियाने की घटनाओं में सीधे तौर पर 'टीएमसी' नेताओं और कार्यकर्ताओं की संलिप्तता उजागर हुई। इधर हिंसा और अनाचार के आरोपितों को सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार संरक्षण मिलते रहा जो राजनीति के अपराधीकरण का अदद उदाहरण है।राजनीतिक पंडितों के अनुसार बंगाल का हालिया चुनाव परिणाम 'टीएमसी' के भय, आतंक और अत्याचार का ही प्रतिकार है।

बीते दशकों में पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा पर गौर करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 लोग मारे गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राज्य में व्यापक पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुई थी। इस दौरान हुई हत्या, बलात्कार, आगजनी और तोड़फोड़ ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। इस दौरान राज्य में चुनावी हिंसा के 300 मामले दर्ज किए गए। इस हिंसा में में 58 लोगों की मौत हुई थी वहीं किशोरियों और महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले भी सामने आए थे।इसी राज्य में 2023 के पंचायत चुनाव में भीषण हिंसा हुई थी जिसमें 45 लोगों की मौत हुई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 लोगों की मौत हुई। आर्म्ड कॉन्फिलक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट 'एसीएलईडी' के मुताबिक साल 2020 से अब तक चुनावी हिंसा के कुल घटनाओं के लगभग 35 फीसदी मामले और 51 फीसदी मौतें बंगाल में दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान चुनावी हिंसा के कुल 2593 मामले दर्ज हुए जिसमें 904 घटनाएं अकेले बंगाल में दाखिल हुए। इसी प्रकार उक्त हिंसा में 329 लोगों की जान गई जिसमें 168 लोग बंगाल के थे। बहरहाल बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद सत्ता हस्तांतरण के दौरान जिस पैमाने पर हिंसा हुई और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पद छोड़ने पर उहापोह की परिस्थितियां निर्मित की गई वह लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरनाक संकेत है।

अलबत्ता केवल बंगाल ही नहीं बल्कि उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, असम, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में भी चुनावों के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा होते रही है। लोकसभा से लेकर पंचायत चुनावों के दौरान माओवाद प्रभावित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा में नक्सलियों ने अनेक राजनीतिक हिंसा को अंजाम दिया था। इस हिंसा में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों सहित सुरक्षा बलों और मतदान दलों के सदस्यों के मारे जाने या घायल होने की घटनाएं घटित हुई है।बिलाशक देश में बढ़ रहे चुनावी और राजनीतिक हिंसा के लिए सीधे तौर पर हमारी राजनीतिक व्यवस्था ही जवाबदेह है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जतन और चिंताओं के बावजूद राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

ऐनकेन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के हनक के चलते देश में धर्म और जाति आधारित वोटबैंक की राजनीति उफान पर है। विडंबना है कि अब राजनीति के निशाने पर धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयता होने लगा है। हिंसा के हालिया दौर पर गौर करें तो राजनीतिक हिंसा अब केवल राजनीतिक विचारधारा का परस्पर टकराव न होकर सांप्रदायिक और जातिगत स्वरूप में सामने आने लगा है। इसका असर देश की एकता -अखंडता और सौहार्द के ताने-बाने पर दृष्टिगोचर हो रहा है।

गौरतलब है कि चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है लेकिन चुनावी हिंसा के चलते चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। देश में कालांतर में चुनावों के दौरान वोटरों को धमकाने,मतदान केंद्रों पर हिंसा और बमबारी, मतदान दलों को धमकाकर जबरिया वोट डालना, मतपेटियों को लूटने जैसी घटनाएं होते रही हैं लेकिन ईवीएम तथा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के चलते ऐसे अपराधों पर काफी अंकुश लगा है। अलबत्ता चुनावी हिंसा से जहां नागरिकों के राजनीतिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वहीं इससे अनेक अयोग्य व अपराधी संसद और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं जिससे लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा खंडित हो रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 'एडीआर' के मुताबिक 18 वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 46 फीसदी यानि 251सांसद हैं। इनमें से 31 फीसदी पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे आरोप हैं यह आंकड़ा साल 2009 के बाद सबसे अधिक है। इसी प्रकार देश भर के विधानसभाओं के 45 फीसदी विधायकों ने अपने उपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बंगाल में संपन्न हालिया चुनाव के बाद नवीन विधानसभा के 65 फीसदी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 2021 के विधानसभा में यह आंकड़ा 49 फीसदी था। अन्य राज्यों में भी दागी विधायकों की संख्या सोचनीय है। गौरतलब है कि राजनीतिक हिंसा से देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता का भी खतरा बढ़ता है जिसके चलते महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। लिहाजा आजादी के अमृतकाल में देश के राजनीतिक व्यवस्था को हिंसा और भयमुक्त करने की जरूरत है ताकि आम जनता का भरोसा चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कायम रहे। इस दिशा में राजनीतिक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है आखिरकार यह लोकतंत्र के अक्षुण्णता से जुड़ा मुद्दा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

आर्थिकी

सतीश सिंह

महंगाई की मार से धीमी पड़ती विकास की रफ्तार

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं विकास की गति पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने महंगाई को फिर वैश्विक चिंता के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसका सीधा असर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार वैश्विक खाद्य कीमतें पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अप्रैल महीने में फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष है, जिसने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ईरान युद्ध को दस सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। यह वही सामरिक समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इस मार्ग में व्यवधान आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है। ईंधन, उर्वरक, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिसके कारण उनकी कीमतों में तेज उछाल आया है। सबसे अधिक प्रभाव खाद्य तेलों पर दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बायो-फ्यूल की मांग बढ़ा दी है, जिसके कारण वेजिटेबल ऑयल की कीमतें मार्च की तुलना में अप्रैल महीने में लगभग 6 प्रतिशत बढ़ गई हैं। यह जुलाई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अनाज की कीमतों में भी लगातार तेजी बनी हुई है। यदि यह संकट लंबा खिंचता है, तो आने वाले समय में वैश्विक खाद्य संकट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

भारत में भी महंगाई के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। अप्रैल महीने में दैनिक उपयोग की 20 में से 16 वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। खाने के तेल, टमाटर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने खुदरा महंगाई को लगभग 4 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दिया है। महंगाई का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करता है। पैकेजिंग सामग्री, ऊर्जा और परिवहन लागत बढ़ने से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ गई है। आने वाले महीनों में साबुन, तेल, बिस्किट और अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यूरिया, एल्युमीनियम, सोया तेल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। इसका असर उद्योगों, निर्माण क्षेत्र और कृषि लागत पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कृषि क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उर्वरक, डीजल और परिवहन महंगे होने से खेती की लागत बढ़ रही है। इससे खाद्य कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि लोगों की आय का बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और रोजमर्रा के खर्चों में निकल जाता है, जिससे बचत घट जाती है। बचत कम होने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास निवेश के लिए पूंजी भी कम होती है। परिणामस्वरूप उद्योगों का विस्तार धीमा पड़ने लगता है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों को यथावत रखा है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है, लेकिन ऊंची ब्याज दरों का असर निवेश और उपभोग दोनों पर पड़ता है। कर्ज महंगा होने से उद्योगों के विस्तार की गति धीमी होती है और नए निवेश प्रभावित होते हैं। इससे रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ता है। विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर पर इसका दबाव अधिक दिखाई दे रहा है। छोटे और मध्यम उद्योग पहले ही ऊंची लागत और सीमित पूंजी से जूझ रहे हैं। अब ऊर्जा, परिवहन और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने उनकी चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। यदि स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो उत्पादन में गिरावट और रोजगार संकट गहरा सकता है। दरअसल, महंगाई केवल कीमतों में वृद्धि नहीं है; यह आर्थिक संतुलन को प्रभावित करने वाली वह प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे विकास की गति को कमजोर कर देती है। जब आम आदमी की क्रय शक्ति घटती है, उद्योगों की लागत बढ़ती है, निवेश धीमा पड़ता है और रोजगार के अवसर कम होते हैं, तब आर्थिक विकास की रफ्तार स्वतः कम हो जाती है।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

चेतना का मूल आधार है अस्तित्व का ज्ञान

संकलित

दर्शन

जब हम दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण विश्व एक है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा प्राण-जगत भिन्न-भिन्न नहीं हैं। समस्त विश्व, यहां से वहां तक, एक है। बात इतनी ही है कि अलग-अलग दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण वह विभिन्न प्रतीत होता है। 'मैं शरीर हूं, इस भावना से जब तुम अपनी ओर देखते हो तो यह भूल जाते हो कि मैं मन भी हूं'। और, जब तुम अपने को मनोरूप में देखने लगते हो, तो तुम्हें अपने शरीरत्व की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु केवल एक है और वह तुम हो। वह तुम्हें जड़ या शरीर के रूप में अथवा मन या आत्मा के रूप में दिख सकती है। जन्म, जीवन, मरण ये सब भ्रम मात्र हैं। न कोई कभी मरता है और ना कोई कभी जन्म लेता है। होता इतना ही है कि मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। लोगों को मृत्यु से इतना भय पाते देख मुझे बहुत दुख होता है। वे मानो जीवन को पकड़ कर रखने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमें जीवन दो। हमें मरणोत्तर जीवन दो। यदि कोई आए और उन्हें बताए कि मृत्यु के बाद भी वे विद्यमान रखेंगे, तो वे कितने आनंदित होते हैं? वस्तुतः मनुष्य के अमरत्व में मैं अविश्वास ही किस तरह कर सकता हूं? मैं मृत हूं, यह कल्पना ही मैं किस प्रकार कर सकता हूं? तुम यदि अपने को मृत सोचने की कोशिश करो तो देखोगे कि तुम अपने मृत शरीर को देखने के लिए वर्तमान हो ही। जीवन का अस्तित्व एक ऐसा आश्चर्यमय सत्य है कि तुम एक क्षण भी उसका विस्मरण नहीं कर सकते।

राजा हैं, फिर भी घमंडी ना बनें

संकलित

प्रेरणा

एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आस पास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची।साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोला- ये क्या उदण्डता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया- मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूं। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी वो बोला- महात्मा जी ये मेरा राज महल है कोई सराय नहीं, कहीं और जाइये। साधु ने कहा- हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा- मेरे पिताजी का, साधु- तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा- मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्करा कर कहा- हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते है वैसे ही ये तुम्हारा राज महल भी है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है ये एक सराय ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट, मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी।

पहिए बनने शुरू

पुरीः 'महाराणा सेवायत' (पुश्तैनी बढ़ई) के नाम से जाने जाने वाले कारीगर, सालाना रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए रथों के लकड़ी के पहिए बना रहे हैं। पहिए बनाने की प्रक्रिया ओडिशा के पुरी में बुधवार से शुरू हुई।

आज की पाती

सोच और कार्य व्यवहार बदलने ही चाहिए

जरूरत से ज्यादा विनम्र होना और किसी को अधिक सम्मान देना भी आज के समय में कई बार एक बड़ी मूर्खता प्रतीत होती है। वे लोग आपको/हमें लगभग उनका दास ही समझने लगते हैं, विशेषकर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के विषय में। मुख्यत:, यदि कुछ प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार और पूर्णत: संवैधानिक विषयों, कार्यों में भी सहयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध निर्भीक होते हुए कानूनी तरीके से नि:संकोच होकर अवश्य ही अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारे पूर्ण मर्यादा में रहते हुए, उन लोगों को भी कुछ सेंक/आंच महसूस होनी चाहिए। ये हम सभी को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए ही होते हैं, जनमानस-नागरिकों पर राज करने के लिए नहीं। -राजेन्द्र ठाकुर, रायपुर

ट्रेंड

स्वच्छ भारत अभियान

मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले। स्वच्छ भारत अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम इसके प्रमुख उदाहरण है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

गहरी संवेदनाए

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मंत्री डी. सुधाकर के निधन से गहरा दुख हुआ। कांग्रेस विचारधारा के पथप्रदर्शक, उन्होंने अपना पूरा जीवन चित्रदुर्ग और कर्नाटक के गरीबों की सेवा में व्यतीत किया। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

मां कामाख्या के दर्शन

असम का नया विधान भवन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, जहां से दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा दिखाई देता है। जब भी आप मां कामाख्या के दर्शन के लिए आएं, उमानंदा में बाबा के दर्शन अवश्य करें। इससे आपकी यात्रा सफल होगी
- हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

डिजिटल क्रांति

हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बना दिया है। आज बुनियादी ढांचा भी अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है।
- समाट चौधरी, सीएम, बिहार

करंट अफेयर

गड्ढे भरना नेताओं के बस की बात क्यों नहीं?

ब्रिटेन में सड़कों के गड्ढे न सिर्फ सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं, बल्कि ये वाहनों को नुकसान पहुंचाने के साथ लोगों की रोजमर्रा की परेशानी और नाराजगी की बड़ी वजह भी हैं। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान यह मुद्दा और भी उभरकर सामने आता है क्योंकि अधिकांश सड़कों का रखरखाव स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। अप्रैल में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि सात मई के लिए निर्धारित चुनावों में पूरे ब्रिटेन में मतदाताओं के लिए सड़कों की हालत सबसे प्रमुख स्थानीय मुद्दा रही। 'द एस्फाल्ट इंडस्ट्री एलायंस' (एआईए) की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि इंग्लैंड और वेल्स के स्थानीय सड़क नेटवर्क का 17 प्रतिशत हिस्सा खराब हालत में है। रिपोर्ट के अनुसार मरम्मत के लंबित कार्य को पूरा करने में 12 साल लगेंगे और 16.81 अरब पाउंड खर्च होंगे। नेताओं के लिए गड्ढे भरने के आंकड़े गिनाकर वोट बटोरना आसान है, लेकिन इससे समस्या की जड़ नहीं सुलझती। गड्ढे अचानक नहीं बनते, होता यूं है कि सामान्य डामर सड़कों में बिटुमेन समय के साथ पुराना और भुरभुरा हो जाता है। वाहनों के बोझ से सड़क की सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं। इन दरारों में पानी घुस जाता है और सर्दियों में जमने-पिघलने के चक्र तथा वाहनों के दबाव से ये दरारें चौड़ी होती जाती हैं।

ऑफ बीट

आइसक्रीम के स्वादों का अजीब इतिहास

इंग्लिश हेरिटेज अब अपनी 13 साइटों पर ब्राउन ब्रेड आइसक्रीम बेच रहा है, जिसे वह 'ब्रेड के बाद सबसे अच्छी कटी हुई चीज' बताता है, जो जॉर्जियाई रेसिपी से प्रेरित है। स्वाद की घोषणा में ब्राउन ब्रेड आइसक्रीम तक पहुंचने से पहले इंग्लिश हेरिटेज द्वारा परमेसन और ककड़ी जैसे कई और विचित्र जॉर्जियाई स्वादों को आजमाने का उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक व्यंजनों से आगंतुकों को लुभाने के अपने प्रयासों में इंग्लिश हेरिटेज अकेली नहीं है। एडिनबर्ग में, नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड के ग्लैडस्टोन्स लैंड में डेयरी से जुड़ा एक आइसक्रीम पार्लर है, जो 1904 में वहां बना था। यह संपत्ति 1770 की रेसिपी के आधार पर बिगफ्लॉवर और नींबू दही आइसक्रीम बेचती है, और आगंतुक कई अन्य तरह के स्वाद का भी मजा ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड आइसक्रीम, जिसे अपनी कैरेमेल पौष्टिकता के लिए पसंद किया जाता है, समकालीन खाने वालों के लिए अन्य ऐतिहासिक पेशकशों की तुलना में भले ही अधिक परिचित स्वाद हो सकती है, लेकिन पिछली शताब्दियों में ब्रिटेन में खाई जाने वाली आइसक्रीम स्वाद और रूपों की एक विशाल विविधता से गुजरी है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

व्यक्ति के स्वभाव का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है

केरलम में देरी

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिलने के एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर कोई फैसला न हो पाना पार्टी नेतृत्व की दुविधा और कमजोरी को ही बयान करता है। यदि राज्य में मुख्यमंत्री चयन में और अधिक देरी होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच असमंजस बढ़ने के साथ उनके उत्साह में तो कमी आएगी ही, नेताओं और विशेष रूप से विधायकों के बीच गुटबाजी को भी हवा मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला के समर्थकों के बीच एक तरह का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसा शक्ति प्रदर्शन कई बार कलह में तब्दील हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव पूरी पार्टी पर पड़ता है। यह ध्यान रहे कि हाल के विधानसभा चुनावों में केवल केरलम में ही कांग्रेस अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाई है। बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उसे निराशा ही हाथ लगी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं।

कोई भी दल हो, मुख्यमंत्री चयन में आलाकमान को अपनी पसंद थोपने के स्थान पर विधायकों की राय को प्राथमिकता देने के साथ समर्थकों के मूड-मिजाज को भांपना चाहिए। जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, वे राजनीतिक नुकसान ही उठाते हैं। हो सकता है कि केरलम के कुछ विधायक केसी वेणुगोपाल को भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता देखना चाह रहे हों, लेकिन तथ्य यह है कि वे तो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़े थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का यह कोई उचित अथवा लोकतांत्रिक आधार नहीं हो सकता कि वे राहुल गांधी के विश्वासपात्र हैं। यदि मुख्यमंत्री चयन में विधायकों और समर्थकों की राय की अनदेखी करने की कोशिश की जाएगी तो फिर सहयोगी दल भी अपनी राय थोपने की चेष्टा करेंगे। केरलम में मुख्यमंत्री चयन में देरी इसलिए अधिक ध्यान खींच रही है, क्योंकि चुनाव वाले अन्य राज्यों और यहां तक कि त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री तय हो गया। केरलम में मुख्यमंत्री पद के चयन में जितनी अधिक देरी होगी, इस पद के दावेदारों के बीच खींचतान उतनी ही बढ़ेगी। यह खींचतान इस निर्देश से थमने वाली नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के समर्थक किसी तरह की टीका-टिप्पणी अथवा अभद्र व्यवहार न करें। केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में जो देरी हो रही है, उससे यह भी नए सिरे से रेखांकित हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व समय पर फैसले नहीं ले पाता।

आत्मनिर्भर बनाने की पहल

बिहार में पैक्सों को केवल कृषि ऋण वितरण केंद्र के बजाय आत्मनिर्भर और बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करने की पहल स्वागतयोग्य है। नए सहकारिता मंत्री की ओर से एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश इस बात का संकेत है कि सरकार अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता माडल के माध्यम से मजबूत करना चाहती है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो पैक्स किसानों के लिए विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों के प्रचार का बड़ा माध्यम बन सकती है। राज्य के अधिकांश किसान आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पैक्सों को स्थानीय बाजारों, ई-कामर्स और सरकारी खरीद व्यवस्था से जोड़ना उपयोगी कदम होगा। मक्का, मखाना, शहद, फल-सब्जी और दुग्ध उत्पाद जैसे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग कर पैक्सों के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे गांवों में रोजगार भी बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। हालांकि इस योजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं। अधिकांश पैक्सों के पास प्रशिक्षित मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक और पर्याप्त वित्तीय क्षमता का अभाव है। कई जगहों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और पारदर्शिता की कमी भी समस्या रही है। डिजिटल व्यवस्था और पेशेवर प्रबंधन के बिना पैक्सों को उद्यमी संस्था बनाना आसान नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि पैक्स कर्मियों का नियमित प्रशिक्षण हो, लेखा प्रणाली पूरी तरह डिजिटल बने और प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाए।

सहकारिता व्यवस्था तभी सफल होगी, जब पैक्स गांव की आर्थिक शक्ति के केंद्र बन सकें

अटूट आस्था का शाश्वत प्रतीक सोमनाथ

योगी आदित्यनाथ

'नया भारत' आज सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनवी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव-अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है

भारत केवल एक भूभाग नहीं, अपितु हजारों वर्षों की सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत राष्ट्र है। भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा अजर-अमर है, वह केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार भारत की सनातन संस्कृति और उसकी आस्था भी अनश्वर है। इतिहास साक्षी है कि इस चेतना को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, किंतु न इसे झुकाया जा सका, न समाप्त किया जा सका। सौराष्ट्र में समुद्र तट पर अवस्थित श्री सोमनाथ मंदिर उसी अमर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तेजस्वी प्रतीक है। विगत एक हजार वर्षों का कालखंड इसका प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता हर क्षण अडिग रही। आज जब भारतवर्ष 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं, अपितु भारत के आत्मा, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान को पुनः अनुभव करने का पावन अवसर भी है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ने शताब्दियों के असंख्य आक्रमण और विध्वंस देखे, किंतु हर बार वह और अधिक गौरव एवं तेज के साथ पुनः स्थापित हुआ। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक अनेक आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर वे स्वयं इतिहास में विलीन हो गए और सोमनाथ मंदिर अडिग खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जब देश विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितताओं से गुजर रहा था, तब हर भारतवासी यह अनुभव कर रहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, भारत को सांस्कृतिक स्वाधीनता का भी पुनर्स्थापन करना होगा। ऐसे समय में लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह केवल एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं, स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प था। सरदार पटेल जानते थे कि यदि राष्ट्र को आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव से जुड़ना ही होगा। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था कि स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि सरदार पटेल अपने उस स्वप्न को साकार होते नहीं देखे सके, पर प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डा. राजेंद्र प्रसाद का यह निर्णय इसकी उद्घोषणा था कि भारत के सांस्कृतिक आत्मा को किसी वैचारिक आग्रह से दबाया नहीं जा सकता।

अवधेश राजपूत

आज, अमृतकाल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 'स्व' से साक्षात्कार कर रहा है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही कालखंड है। जो कार्य स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल और डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ किया था, वही चेतना आज मोदी जी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी पांच शताब्दियों के संघर्ष, धैर्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान की ऐतिहासिक परिणति है। कभी जिन आक्रांताओं ने श्रीरामजन्मभूमि को अपमानित कर भारत की आस्था पर प्रहार किया था, आज उनका नाम इतिहास के अंधकार में खो चुका है, किंतु प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है।

इसी क्रम में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास काशी की जीवंतता और भारत की सनातन चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज वैश्विक स्तर पर भी भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को नई स्वीकृति प्राप्त हो रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, अध्यात्म और सनातन जीवनदृष्टि के प्रति विश्व का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। यह केवल सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, यह भारत की उस शाश्वत दृष्टि की स्वीकृति है, जो मानवता को संतुलन, सहअस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 'नया भारत' आज 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव-अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है।

सोमनाथ का पुनर्निर्माण इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें स्मरण कराता है कि कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक शक्ति से महान नहीं बनता। उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास और उसकी सभ्यतागत निरंतरता में निहित होती है। जिन राष्ट्रों ने अपनी जड़ों को भुला दिया, वे इतिहास में धीरे-धीरे कमजोर पड़ गए, किंतु भारत ने हर युग में अपने आत्मा को सुरक्षित रखा। आज जब हम पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह अवसर नई पीढ़ी को भारत के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का भी है। यह पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी है। उसे यह समझना होगा कि भारत का उत्थान केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं है। भारत तब पूर्ण रूप से विकसित और शक्तिशाली बनेगा, जब वह अपने आत्मा से जुड़कर आगे बढ़ेगा। श्री सोमनाथ मंदिर हमें यह भी स्मरण कराता है कि पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं होता, वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। जब कोई समाज अपने टूटे हुए प्रतीकों को पुनः स्थापित करता है, तब वह केवल भवन नहीं बनाता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ हमें यही प्रेरणा देती है कि राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। यदि संस्कृति सुरक्षित है, तो राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है।

आइए, इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाएंगे। भावी पीढ़ियों को अपनी सभ्यता का गौरव समझाएंगे और अमृतकाल में भारत को उसके वास्तविक वैश्विक स्वरूप तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जय सोमनाथ!

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)
response@jagran.com

भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा

डा. ऋतु सारस्वत

बंगाल में कलिता माझी, रेखा पात्रा, रत्ना देवनाथ की जीत ही वास्तविक नारी सशक्तीकरण है और ऐसा ही होना चाहिए

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इस बार केवल सत्ता का गणित नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र के अर्थ को भी एक नई सामाजिक व्याख्या दी है। आसग्राम से कलिता माझी, हिंगलगंज से रेखा पात्रा और पनिहाटी से रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत केवल चुनावी सफलता नहीं है। यहां एक घरेलू सहायिका है, एक श्रमिक और वंचित वर्ग से आई महिला है तो एक ऐसी मां भी है जिसने अपनी निजी पीड़ा और सामाजिक अपमान को अपनी शक्ति और दृढ़निश्चय में बदल दिया। इन महिलाओं की उपस्थिति भारतीय राजनीति के उस बदले हुए चेहरे को सामने लाती है, जहां पहली बार हाशिए पर खड़ी दिखाई देने वाली स्त्रियां सत्ता और प्रतिनिधित्व के केंद्र में दिखाई देने लगी हैं। इन महिलाओं की जीत को यदि हम मात्र चुनावी परिणाम के रूप में देखेंगे तो यह हमारी सामाजिक दृष्टि की असफलता होगी। चुनावी आंकड़ों और राजनीतिक विमर्शों से परे इन महिलाओं की जीत नारी सशक्तीकरण का हस्ताक्षर है। यही वह नारी सशक्तीकरण है, जिसका आह्वान स्वतंत्रता के बाद से लगातार किया जाता रहा है और जिसकी चर्चा बौद्धिक वर्ग वर्षों से करता आया है।

कलिता माझी, रेखा पात्रा और रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत के साथ स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि भारत में नारीवादी विचारधारा के समर्थक और उसके मुखर प्रवर्तक खुलकर इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। यह अपेक्षा इसलिए भी थी, क्योंकि वर्षों से स्त्री-प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्वकारी उपस्थिति को लेकर निरंतर आवाज उठाई जाती रही है। किंतु आश्चर्य यह है कि तमाम डिजिटल मीडिया मंचों से लेकर वैचारिक और बौद्धिक विमर्शों तक एक विचित्र-सी चुप्पी दिखाई देती है। वे स्वर, जो सामान्यतः स्त्री-अधिकारों और महिला नेतृत्व के प्रश्न पर अत्यंत मुखर दिखाई देते हैं, आज कहीं खो से गए हैं। नारीवादी चिंतक नैंसी फ्रेजर अपने चर्चित निबंध 'फ्राम रीडिस्ट्रिब्यूशन टू रिकग्निशन?' में इस बात पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं कि यदि नारीवाद केवल कुछ सफल और विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की उपलब्धियों तक सीमित रह जाए तो वह समाज की वास्तविक असमानताओं को नहीं बदल सकता। शायद यही कारण है कि जब साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन से निकली महिलाएं राजनीति और सार्वजनिक नेतृत्व तक पहुंचती हैं तो समाज उन्हें उतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, जितनी सहजता से प्रभावशाली और संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को स्वीकार करता है। बेल हुक्स ने अपनी पुस्तक 'फेमिनिस्ट थ्योरी : फ्राम मार्जिन टू सेंटर' में लिखा है कि मुख्यधारा का नारीवादी विमर्श लंबे समय तक मुख्यतः विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के अनुभवों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। शायद यही कारण है कि श्रम, अभाव और संघर्ष से निकली महिलाओं को वह सहज स्वीकार्यता, प्रशंसा और मान्यता नहीं मिल पाती, जो प्रभावशाली और संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो जाती है।

महिलाओं का बढ़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व ।फाइल

भारत की कोई भी राजनीतिक विचारधारा अथवा दल जब दलित, वंचित और संघर्षशील महिलाओं को मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचाने का अवसर देता है, तब सबसे पहले उन महिलाओं के साहस और संघर्ष को सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें केवल किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखकर मौन हो जाना शायद उस व्यापक सामाजिक उद्देश्य को सीमित कर देना है, जिसकी बात दशकों से की जाती रही है। नारीवाद का उद्देश्य केवल स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिलाना नहीं, बल्कि लैंगिक शोषण और दमन की संरचनाओं को समाप्त करना है। स्त्री संघर्ष को केवल वैचारिक विमर्शों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, उसे उन महिलाओं के जीवनानुभवों, वर्गीय संघर्षों और सामाजिक यथार्थ के साथ भी जोड़कर समझना होगा, जो हाशिए से निकलकर नेतृत्व तक पहुंचती हैं। तब उसका प्रभाव केवल निजी उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। यह स्थिति समाज की लोकतांत्रिक कल्पना, स्त्री आकांक्षाओं और प्रतिनिधित्व की पारंपरिक सीमाओं को भी बदलती है।

विडंबना यह है कि स्त्री-प्रतिनिधित्व और महिला नेतृत्व की चर्चा करने वाले समाजों में भी, जब साधारण, श्रमिक या सामाजिक रूप से उपेक्षित पृष्ठभूमि की महिलाएं राजनीति में पहुंचती हैं तो उनकी उपस्थिति को लेकर एक सूक्ष्म असहजता दिखने लगती है। समस्या केवल स्त्री के राजनीति में आने की नहीं होती, बल्कि इस बात की भी होती है कि वह किस वर्ग और किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आई है। समय आ गया है कि स्वयं को नारीवाद का समर्थक कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह प्रश्न पूछे कि क्या वह कहीं चयनात्मक नारीवाद का शिकार तो नहीं। यदि स्त्री संघर्ष और महिला नेतृत्व को भी पसंद-नापसंद तथा वैचारिक सुविधा के आधार पर स्वीकार किया जाएगा तो वह नारीवाद नहीं, चयनात्मक नारीवाद बनकर रह जाएगा।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संभावनाएं

सृष्टि में सब कुछ अस्थायी है, किंतु जीवनदायी तत्वों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, भले ही वे कभी परिलक्षित नहीं होते। इसीलिए धरती पर जीवन-प्रक्रिया सदा गतिमान रहती है। संभावना ऐसा ही तत्व है, जो आशाएं क्षीण होने पर भी तन-मन में जीवनी शक्ति का संचार करता है और संसाधनों के नष्ट होने पर भी सफलता के नए द्वार खोलता है। संभावनाओं का संसार व्यापक होने से ये जीवन को विस्तार देती हैं। अतः इनके रहते जीवन कभी नहीं मरता। यद्यपि विधाता ने सबको समान अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु फलप्राप्ति खुद के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। धैर्य, साहस एवं पराक्रम विपरीत परिस्थितियों में भी नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। जैसे प्रलयकाल के समय सब कुछ नष्ट हो जाने पर संभावनाएं पुनर्जीवन का इतिहास रचती हैं, उसी प्रकार उम्मीद न रहने पर भी संभावनाएं स्वयं उम्मीद बन जाती हैं। संभावनाएं साकार करने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण आज यही शिक्षा जीवन लेने का कारण बन रही है। असफल होने पर ही नहीं, कुछ कम अंक आने या रोजगार में देरी होने पर बच्चों में बढ़ रही अवसाद की प्रवृत्ति उनके जीवन को निगल रही है। शत-प्रतिशत अंक न ज्ञान में प्रवीणता के प्रमाण हैं, न नौकरी पाने की गारंटी। कम अंक होने पर भी श्रेष्ठतम ज्ञान नवीन संभावनाओं को जन्म देता है, क्योंकि ज्ञान से कुछ भी अलभ्य नहीं।

युवाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, 'आकाश की तरफ देखो, तुम अकेले नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है। इसके अनंत विस्तार में तुम्हें अनंत संभावनाएं नजर आएंगी, जो जीवन को उच्च शिखर पर ले जाएंगी।' अतः असफल होने पर भी इस विषम जीवन-यात्रा में संभावनाओं की डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ नया कानून

सुनीता मिश्रा

विदेश जाने की बढ़ती चाहत ने फर्जी एजेंटों का एक संगठित अवैध कारोबार खड़ा कर दिया है

हरियाणा सरकार ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए नया संशोधित कानून लागू किया है। 'हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ ट्रैवल एजेंट्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026' के तहत अब ट्रैवल एजेंट विदेश में नौकरी, वर्क परमिट, इमिग्रेशन या स्थायी नागरिकता दिलाने का दावा नहीं कर सकेंगे। उनका कार्य केवल यात्रा प्रबंधन और टूर सेवाओं तक ही सीमित रहेगा। यदि कोई एजेंट विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देता है या बिना अधिकृत अनुमति के भर्ती संबंधी गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत सात से 10 साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इससे उन फर्जी एजेंसियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, जो कस्बों और गांवों में लुभावने विज्ञापन देकर युवाओं को फंसाती हैं।

विदेश जाने की बढ़ती चाहत ने फर्जी एजेंटों का एक संगठित अवैध कारोबार खड़ा कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के अनेक गांवों में विदेश बसने को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इसी मानसिकता का फायदा एजेंट उठाते हैं। कई परिवार जमीन बेचकर या कर्ज लेकर बच्चों को विदेश भेजने के लिए लाखों रुपये एजेंटों को दे देते हैं। जब धोखाधड़ी सामने आती है, तब तक परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुका होता है। गत वर्षों में डंकी रूट के जरिये अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भेजे जाने के कई मामले सामने आए हैं। अवैध रास्तों से विदेश पहुंचने के दौरान अनेक युवक महीनों तक दूसरे देशों में फंसे रहे, जबकि कई युवकों की जान तक चली गई। मानव तस्करी का यह नेटवर्क केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक खतरा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हो गए।

युवाओं के सपनों को सुरक्षित और वैध अवसरों से जोड़ना ही इस कानून की वास्तविक सफलता होगी। इसके लिए राज्य सरकार को सभी ट्रैवल एजेंसियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, नियमित आडिट एवं सार्वजनिक सत्यापन व्यवस्था विकसित करनी होगी, ताकि लोग आसानी से पता कर सकें कि कौन-सी एजेंसी अधिकृत है। साइबर निगरानी भी जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फर्जी एजेंट लगातार प्रचार करते हैं। स्कूलों, कालेजों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताया जाना चाहिए कि विदेश में रोजगार पाने के लिए केवल अधिकृत सरकारी चैनलों और मान्यता प्राप्त एजेंसियों पर ही भरोसा करें। विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामलों से जुड़े पोर्टलों की जानकारी गांवों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बंगाल के सामने असली चुनौती

'बंगाल को पटरी पर लाने की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि बंगाल केवल चुनावी नारों और वैचारिक संघर्षों से आगे बढ़कर ही अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त कर सकता है। यह विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व का केंद्र रहा बंगाल आज रोजगार पलायन, राजनीतिक हिंसा और आर्थिक ठहराव जैसी समस्याओं से जूझता दिखाई देता है। वास्तविक समस्या केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक विश्वास की है। कोलकाता, हावड़ा और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पहले जैसी आर्थिक सक्रियता दिखाई नहीं देती। बड़ी संख्या में युवा आज रोजगार के लिए बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक कमजोरी नहीं, बल्कि राज्य के भीतर घटते सामाजिक आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग और ग्रामीण निवेश जैसे बुनियादी मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर सुंदरवन क्षेत्र तक स्थानीय अर्थव्यवस्था आज भी स्थायी विकास की प्रतीक्षा कर रही है। बंगाल को वास्तव में पटरी पर लाना है तो राजनीतिक संघर्ष से अधिक आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देना होगा। केवल वैचारिक बहसें किसी राज्य को आगे नहीं बढ़ातीं। निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन ही किसी प्रदेश की स्थिर प्रगति का आधार बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बंगाल अपनी बौद्धिक विरासत को आधुनिक आर्थिक दृष्टि से जोड़कर विकास की नई दिशा तलाशे।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

संवाद का मंच बने लोकतंत्र

प्रो. मनोज कुमार झा का आलेख ''सरकार और देश में अंतर करना जरूरी'' पढ़ा। इसमें लोकतंत्र, असहमति और आलोचना के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, परंतु असहमति और निरंतर नकारात्मकता में भी स्पष्ट अंतर होता है। यदि हर राष्ट्रीय निर्णय, हर सुरक्षा नीति और हर प्रशासनिक कदम को केवल ''सत्ता बनाम जनता'' के चश्मे से देखा जाएगा, तो इससे लोकतांत्रिक विमर्श संतुलित नहीं, बल्कि पक्षपाती बनता है। एक विश्लेषक का दायित्व केवल प्रश्न उठाना नहीं, बल्कि परिस्थितियों, चुनौतियों और विकल्पों का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करना भी होता है। सरकार की आलोचना होनी चाहिए, परंतु ऐसी आलोचना जो समाधान, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय हित की भावना से प्रेरित हो, न कि केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण से। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता और विपक्ष दोनों राष्ट्रहित को दलगत सीमाओं से ऊपर रखें। यदि हर नीति को वैचारिक युद्धभूमि बना दिया जाएगा, तो लोकतंत्र संवाद का मंच न रहकर केवल टकराव का अखाड़ा बन जाएगा।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

अपहरण की बढ़ती घटनाएं

भारत में अपहरण की घटनाएं पिछले एक दशक में बढ़ी हैं। एनसीआरबी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 70 वर्षों में लगभग 20 लाख अपहरण के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 11 लाख मामले केवल पिछले एक दशक में सामने आए हैं। यानी अपराधों में इसकी हिस्सेदारी लगभग तीन गुना बढ़ गई है। अपराध की यह तेजी निश्चित रूप से चिंतनीय और विचारणीय है। आंकड़ों के अनुसार, कुल अपराधों में अपहरण की हिस्सेदारी 1953-62 के दौरान 1.01 प्रतिशत थी, जो 2013-24 के दौरान बढ़कर 3.04 प्रतिशत हो गई। आखिर सख्त कानून व्यवस्था कहां गुम हो गई है?

योगेश जोशी, बड़वाह

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

शीर्ष-10 में से चार कंपनियों की पूंजी एक लाख करोड़ घटी

नई दिल्ली: बीते सप्ताह बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से चार कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में संयुक्त रूप से एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। इस दौरान एसबीआइ के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 44,722.34 करोड़ रुपये घटा है। इसके अलावा, भारती एयरटेल, टीसीएस और लार्सन एंड टूब्रो का पूंजीकरण भी घटा है। दूसरी ओर, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलआइसी और आइसीआइसीआइ बैंक का पूंजीकरण संयुक्त रूप से 46,685 करोड़ रुपये बढ़ा है। (प्रेट्र)

भू-राजनीतिक तनाव के कारण पश्चिम एशिया को निर्यात पर असर पड़ा है। हमारे कुल एल्युमिनियम निर्यात में इस क्षेत्र की 40-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

- बृजेंद्र प्रताप सिंह, सीएमडी, नालको

महंगा हो सकता है रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान

बढ़ती लागत से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहीं एफएमसीजी कंपनियां

- वैश्विक सप्लाई चेन हुई प्रभावित, कच्चा माल, लाजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत बढ़ी
- लागत में कमी के लिए छूट और प्रचार खर्चों में भी कटौती कर रही हैं कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र: कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन लागत में बढ़ोतरी के बीच साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और पेय उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां बढ़ती लागत से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।

एफएमसीजी कंपनियों ने हालिया तिमाही नतीजों के दौरान इस बात का संकेत दिया था कि वे पहले ही तीन से पांच प्रतिशत तक कीमतें बढ़ा चुकी हैं और लागत का दबाव जारी रहने पर आगे भी मूल्य वृद्धि की जा सकती है। कंपनियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे कच्चे माल, लाजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत बढ़ी है। रुपये में कमजोरी ने भी दबाव बढ़ाया है। इसका असर खाद्य उत्पादों, व्यक्तिगत देखभाल, पेय पदार्थ और घरेलू उपयोग के सामान सहित कई क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। कंपनियां मुनाफा बनाए रखने के लिए कीमतें बढ़ाने के साथ पैकेट बंद उत्पादों में मात्रा कम करने की रणनीति भी अपना रही हैं। हालांकि पांच, 10 और 15 रुपये वाले छोटे पैक बाजार में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है ताकि बिक्री पर असर कम पड़े। कंपनियां लागत कम करने के लिए छूट और प्रचार खर्चों में कटौती, भंडार प्रबंधन को मजबूत करने और सप्लाई चेन को अधिक कुशल बनाने जैसे कदम उठा रही हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं पर बढ़ती लागत का कुछ बोझ पड़ने की संभावना है।

उत्पाद का मूल्य बढ़ाने और पैकेट का वजन घटाने पर कर रहे विचार : ब्रिटानिया

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भी संकेत दिया है कि ईंधन और पैकेजिंग लागत में करीब 20 प्रतिशत वृद्धि के कारण जल्द ही कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ रक्षित हरगेव ने कहा कि कंपनी सीधे दाम बढ़ाने और पैक के वजन में कमी, दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। ब्रिटानिया के पास गुड डे, मेरी गोल्ड, मिल्क बिकीज और टाइगर जैसे ब्रांड हैं।

हमारे ऊपर महंगाई का आठ से 10 प्रतिशत का बोझ पड़ा : हिंदुस्तान यूनिलीवर

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने भी संकेत दिए हैं कि यदि जिंसों की कीमतों में दबाव बना रहा तो कंपनी आगे और कीमतें बढ़ा सकती है। एचयूएल के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) निरंजन गुप्ता ने कहा, 'अभी तक हमारे ऊपर महंगाई का आठ से 10 प्रतिशत का बोझ पड़ा है। हमने पोर्टफोलियो दर पोर्टफोलियो आधार पर कीमतों में दो से पांच प्रतिशत तक की वृद्धि की है।

हमने महंगाई के असर को थोड़ा कम करने के लिए बिजनेस के अलग-अलग हिस्सों में पहले ही चार प्रतिशत कीमत बढ़ा दी है। इसके अलावा, कम कीमत वाले पैकेट का वजन घटाने पर भी विचार किया जा रहा है।

-मोहित मल्होत्रा, सीईओ, डाबर इंडिया ग्लोबल

फेविकोल निर्माता पिडिलाइट ने भी दिए दाम बढ़ाने के संकेत

नई दिल्ली, प्रेट्र : एड्हेसिव और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए एक और बार कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी के पास फेविकोल, डा. फिक्सिट, फेविक्विक और एम-सील जैसे लोकप्रिय ब्रांड हैं। कंपनी ने अप्रैल में कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया था और उसके बाद मई में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई थीं। कंपनी के प्रबंध निदेशक सुधांशु वत्स ने बताया कि कंपनी को जिस तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है, वह काफी हद तक कच्चे तेल से जुड़े हैं। उन्होंने आगाह किया है कि लंबे समय तक चलने वाला भू-राजनीतिक संघर्ष और लगातार बढ़ती महंगाई आखिरकार उपभोक्ता मांग पर असर डालेगी।

एफपीआइ ने मई माह में अब तक शेयरों से 14,231 करोड़ निकाले

ताजा बिकवाली के साथ कैलेंडर वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों की कुल निकासी दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंची

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की भारतीय शेयरों की बिकवाली जारी है और मई में अब तक 14,231 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते एफपीआइ भारतीय शेयरों से निकासी कर रहे हैं।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, इस ताजा बिकवाली के साथ कैलेंडर वर्ष 2026 में एफपीआइ की कुल निकासी दो लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। फरवरी को छोड़कर एफपीआइ इस वर्ष सभी महीनों में शुद्ध विक्रेता रहे हैं।

इस वर्ष जनवरी में एफपीआइ ने 35,962 करोड़ रुपये निकाले। इसके बाद फरवरी में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक प्रवाह था। हालांकि, मार्च में यह प्रवृत्ति पलट गई, जब विदेशी निवेशकों ने रिकार्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाले। अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी के साथ यह बिक्री जारी रही और मई में अब तक 14,231 करोड़ रुपये की निकासी हुई है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि समग्र बिक्री के बावजूद, एफपीआइ ने पावर, निर्माण और पूंजीगत वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में चयनात्मक रूप से निवेश किया है। एफपीआइ अब मिड-कैप और कुछ चुनिंदा स्मालकैप स्टाक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जिनमें वृद्धि की अच्छी संभावना है।

पश्चिम एशिया संकट से घटेगी आर्थिकी

- एशियाई विकास बैंक ने कहा- 0.6 प्रतिशत घटकर 6.3 प्रतिशत रह जाएगी भारत की वृद्धि दर
- बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बोले- महंगाई 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो जाएगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में 0.6 प्रतिशत की कमी आएगी और यह 6.3 प्रतिशत रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल महंगाई 2.4 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो जाएगी। एडीबी ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि मजबूत घरेलू मांग की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत के स्तर पर मजबूत बनी रहेगी। अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.3 प्रतिशत हो जाएगी। महंगाई के मामले में, एडीबी ने मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 4.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था।

एक साक्षात्कार में पार्क ने यह भी आशंका जताई कि पश्चिम एशिया संकट के लंबा खिंचने की स्थिति में कच्चे तेल के दाम फिलहाल ऊंचे स्तर पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने की आशंका के बीच हमारा अनुमान है कि नए परिदृश्य में यह 2026 में औसतन 96 डालर प्रति बैरल के स्तर पर रहेगा। 027 में यह 80 डालर प्रति बैरल के स्तर पर रहेगा।' एडीबी ने 29 अप्रैल को अपनी विशेष रिपोर्ट में 2026 के लिए एशिया प्रशांत के लिए वृद्धि दर के अनुमान को 5.1 प्रतिशत से घटाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया है।

भारत में फसल खराब होने का दूसरे देशों पर पड़ेगा असर

खाद्य उत्पादन पर अल नीनो के असर पर पार्क ने कहा, 'बेशक, यह बहुत अनिश्चित है। जाहिर है जब भी भारत में फसल खराब होती है, तो हमें ज्यादा कीमतों का सामना करना पड़ता है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए भारत में जो कुछ भी होता है, उसका अक्सर दूसरे देशों पर भी बड़ा असर पड़ता है।' उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती उर्वरक कीमतों के अलावा यह भी चिंता का एक कारण है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की कीमत बढ़ने से किसान कम खाद का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पैदावार भी कम होगी और साल के आखिर में इसकी उपलब्धता भी कम होगी।

एफटीए के बेहतर उपयोग को लेकर योजना बना रहा केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: विकसित देशों के साथ कई मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर के बाद सरकार इनका अधिकतम लाभ उठाने के लिए 'एफटीए इस्तेमाल योजना' पर काम कर रही है। 2021 से अब तक भारत ने मारीशस, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, न्यूजीलैंड, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), यूरोपीय संघ (ईयू), ब्रिटेन और अमेरिका के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। ये एफटीए 38 देशों के साथ किए गए हैं।

एक अधिकारी ने बताया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग संगठनों, कारोबारियों और निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ कई बैठकें कर एफटीए के बेहतर उपयोग पर चर्चा की है। उन्होंने उद्योग जगत से इन समझौतों का लाभ उठाकर निर्यात और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने का आह्वान किया है।

दान पर टैक्स छूट के लिए 31 तक अपलोड करें विवरण

- किसी संस्थान को दो हजार रुपये तक ही नकद राशि दी जा सकती है दान स्वरूप
- इससे अधिक राशि बैंक ट्रांसफर या डिजिटल माध्यम से ही देनी होगी

जागरण संवाददाता, कानपुर : अगर आपने बीते वित्त वर्ष 2025-26 में किसी चैरिटेबल संस्थान को दान दिया है और आयकर की पुरानी व्यवस्था के तहत छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 मई 2026 तक दान दी गई रकम का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसका कारण यह है कि आयकर की नई व्यवस्था के तहत अब दान की रसीद मात्र से आयकर में छूट नहीं मिलेगी।

आयकर कानून की धारा-80जी (5) के तहत, दान प्राप्तकर्ता संस्थान को फार्म-10बीडी में दानदाता का नाम, पता, पैन व दान की राशि का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद पोर्टल से जो फार्म-10बीई जारी किया जाएगा। उसी के आधार पर दानदाता को कटौती की छूट दी जाएगी। कर मामलों के जानकार अधिवक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि नकद दान की सीमा व नियम भी निर्धारित हैं। इसके तहत किसी भी संस्थान को 2,000 रुपये तक ही नकद दान दिया जा सकता है। इससे ज्यादा की राशि बैंक ट्रांसफर या अन्य डिजिटल माध्यमों से देने पर ही टैक्स छूट मान्य होगी। सामान्यत: दान की 50 प्रतिशत राशि ही कटौती के रूप में मान्य होती है, जो सकल (सभी स्रोतों से प्राप्त) आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थानों को दिए दान पर ही 100 प्रतिशत छूट मिलती है। उन्होंने बताया कि चैरिटेबल संस्थानों को फार्म-10बीडी दाखिल करते समय डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रानिक मोड से सत्यापन करना होगा। यह नियम वित्त वर्ष 2025-26 (कर निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए पूरी तरह प्रभावी है।

टीसीएस रिटर्न 15 मई तक कर दें दाखिल

आयकर विभाग के नियमों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) का टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। इसमें देरी पर 200 रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि, यह विलंब शुल्क वसूले जाने वाले टीसीएस की कुल राशि से अधिक नहीं हो सकता। रिटर्न दाखिल होने के बाद संबंधित व्यक्ति या फर्म को आयकर विभाग के पोर्टल से टीसीएस प्रमाणपत्र भी आनलाइन जारी होगा। कर विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर कानून के दायरे में आने वाले करदाता जिनकी लेखा पुस्तकों (बही-खाते) का धारा 44 एबी के तहत आडिट कराया जाता है, उन पर ही धारा 206 सी के तहत निर्धारित वस्तुओं की बिक्री पर क्रेता से टीसीएस वसूलने की जिम्मेदारी होती है। इस वसूले गए कर का विवरण फार्म 27ईक्यू के माध्यम से विभाग को दिया जाना आवश्यक है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

ईरान ने अमेरिका को भेजा जवाब, पर खाड़ी में तनाव बरकरार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- यूएई-कुवैत का हमले विफल करने का दावा, ड्रोन हमले में जहाज पर लगी आग, होर्मुज से दो जहाज भी निकले
- ट्रंप ने यूरेनियम भंडार पर निगरानी की चेतावनी दी, आइआरजीसी बोला- हमला हुआ तो जवाब बेहद कड़ा होगा

पश्चिम एशिया में दो माह से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेज दिया है। एक दिन पूर्व ही उम्मीद जताई गई थी कि अमेरिका व ईरान के बीच इस हफ्ते पाक में शांति वार्ता हो सकती है। हालांकि खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है।

ईरानी समाचार एजेंसी आइआरएनए के मुताबिक, तेहरान के जवाबी प्रस्ताव में प्राथमिकता क्षेत्र में सैन्य कार्रवाइयां रोकने व तनाव कम करने को दी गई है। आइआरआइबी के अनुसार, ईरान के जवाब में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की शर्त रखी गई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष फिलहाल अस्थायी समझौते पर काम कर रहे हैं, ताकि होर्मुज स्ट्रेट में यातायात सामान्य रखा जा सके। इसके बाद परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर वार्ता आगे बढ़ेगी। हालांकि, ईरान के जवाबी प्रस्ताव का खुलासा नहीं किया गया है। इस बीच, कतर, सऊदी अरब, तुर्किए, चीन सहित कई देश राजनयिक प्रयासों के तहत ईरानी अफसरों और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के संपर्क में बताए जा रहे हैं।

एपी के अनुसार, यूएई ने रविवार को दावा किया कि उसने ईरान से जुड़े दो ड्रोन हमलों को विफल किया। कुवैत ने भी कहा, उसकी हवाई सीमा में कई ड्रोन घुसे, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। हालांकि, ईरान ने इन आरोपों से इन्कार किया है। कतर के तट से करीब 43 किमी दूर खड़े एक जहाज में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। कतर का दावा है कि ये जहाज अबू धाबी से आ रहा था। एएनआइ के अनुसार, तनाव के बीच राहत की खबर यह रही कि पनामा और कतर के झंडे वाले दो मालवाहक जहाज ईरान द्वारा तय समुद्री मार्ग से सुरक्षित होर्मुज पार कर गए। इनमें कतर एनर्जी का एलएनजी जहाज 'अल खारैतियात' पाकिस्तान के पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ, जबकि 'एमडीएल तूफान' ब्राजील की ओर बढ़ा। खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से कतर के एलएनजी लदे पहले जहाज ने होर्मुज पार किया है।

आइएएनएस के अनुसार, आइआरजीसी ने चेतावनी दी कि ईरानी तेल टैंकरों या व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ तो अमेरिकी सैन्य अड्डों व युद्धपोतों को निशाना बनाया जाएगा। आइआरजीसी की एयरोस्पेस डिवीजन ने भी एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उसके मिसाइल व ड्रोन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों व युद्धपोतों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा "हम केवल कार्रवाई के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।" न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के भूमिगत यूरेनियम भंडार पर हमारी नजर है। "यदि कोई उस जगह के करीब पहुंचा तो हम उसे उड़ा देंगे।"

हम दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। यदि संवाद या बातचीत की पहल होती है तो इसका अर्थ समर्पण या पीछे हटना नहीं है।

- मसूद पेजेशकियान, ईरान के राष्ट्रपति

खार्ग द्वीप से तेल लीकेज की खबर गलत : ईरान

रायटर के अनुसार, ईरान ने खार्ग द्वीप में तेल रिसाव की खबरों का खंडन किया है। ईरान की आयल टर्मिनल्स कंपनी ने तेल लीक की खबरों को बेबुनियाद बताया है। दरअसल, उपग्रह से जारी तस्वीरों में खाड़ी में देश के मुख्य तेल निर्यात हब के पश्चिम में एक चिकनी परत दिखी थी, जिस आधार पर रिसाव का दावा किया गया था। कंपनी अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय सामुद्रिक प्रदूषण निकाय, मरीन इमरजेंसी म्युचुअल एड सेंटर (एमईएमएसी) ने भी रिपोर्ट दी है कि किसी तरह के तेल रिसाव के संकेत नहीं मिले हैं। ईरानी अधिकारियों ने भी क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रयोगशाला में परीक्षण के आधार पर इन खबरों का खंडन किया है।

लेविट बनीं मां, ईरान ने दी बधाई, मिनाब हमले की भी दिलाई याद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को बेटी के जन्म पर ईरान ने बधाई दी है। साथ ही फरवरी में ईरान के मिनाब शहर में हुए स्कूल हमले का मुद्दा उठाकर अमेरिका की आलोचना भी की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 28 वर्षीय लेविट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपनी नवजात बेटी विवियाना की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि एक मई को उनके परिवार में बेटी के आने से घर खुशियों से भर गया है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और परिवार उसके साथ हर पल का आनंद ले रहा है। जवाब में अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस पर आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, बच्चों की मासूमियत हर जगह एक जैसी होती है। मिनाब के जिस स्कूल पर फरवरी में हमला हुआ था, वहां मारे गए 168 बच्चे भी उतने ही मासूम थे। लेविट जब अपनी बच्ची को दुलारें तो उन बच्चों की माताओं को भी याद करें।

इजरायल ने ईरान पर हमले के लिए इराक में बनाया सैन्य अड्डा!

तेल अवीव, एएनआइ : इजरायल ने ईरान पर हमले के लिए इराक के रेगिस्तानी इलाके में गुप्त सैन्य अड्डा स्थापित किया है, यहां से उसे ईरान पर हमले में काफी मदद मिलती है। यह रहस्योद्घाटन अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किया है। पता चला है कि इजरायल ने इस अड्डे से इराक के ईरान समर्थक उन सशस्त्र संगठनों पर भी हवाई हमले किए जिन्होंने तलाश करते हुए ठिकाने के नजदीक आने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार इराक के निर्जन रेगिस्तानी इलाके में बनाए गए इस अड्डे में इजरायल के स्पेशल फोर्स के जवान तैनात हैं और वहां पर हवाई हमले को अंजाम देने के लिए सारे इंतजाम हैं। यह अड्डा मार्च में ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले से ठीक पहले स्थापित किया गया। इजरायल ने ईरान से लंबी लड़ाई की तैयारी के तहत उसके नजदीक यह अड्डा तैयार किया है।

पाक में पुलिस चौकी पर हमला, 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए

- खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में घात लगाकर किया गया हमला
- विस्फोटकों से भरी गाड़ी पर सुरक्षाकर्मियों ने की गोलीबारी

पेशावर, प्रेट्र: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस चौकी पर हुए आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बन्नू में शनिवार देर रात हुई, जहां विस्फोटक से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी की ओर आ रही थी, तभी सुरक्षाकर्मियों ने उस पर गोलीबारी की, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट के प्रभाव से आसपास के कई घरों की छतें गिर गईं। पुलिस चौकी की इमारत भी ध्वस्त हो गई और कई सुरक्षाकर्मी मलबे के नीचे दब गए।

विस्फोट के बाद समूह ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप भारी गोलीबारी हुई। बन्नू पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए। इस घटना में मारे गए हमलावरों की संख्या और उनमें से किसी की गिरफ्तारी के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने हमले की निंदा करते हुए दुख व्यक्त किया। उनके कार्यालय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अफसरों को घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आफरीदी ने चौकी पर हुए हमले को "अत्यंत दुखद व कायरतापूर्ण कृत्य" बताया और कहा, ऐसे हमले पुलिस और जनता के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते।

पाकिस्तान के खबर पख्तूनखा प्रांत में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले के बाद रविवार को जुटी भीड़ के बीच मलबा हटाता एक्सकेवेटर। रायटर

पाक मंत्री ने खुद को मुनीर का 'मामूली कार्यकर्ता' बताया, बयान पर विवाद शुरू

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री अली परवेज मलिक के एक बयान ने देश में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद को पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की टीम का "मामूली कार्यकर्ता" बताया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का आश्वासन देते हुए दिए गए इस बयान पर इंटरनेट मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। आलोचकों का तर्क है कि एक मंत्री द्वारा खुद को सैन्य प्रमुख का कार्यकर्ता बताना पाकिस्तान की राजनीति में सेना के बढ़ते प्रभाव और 'हाइब्रिड सिस्टम' की कड़वी सच्चाई दर्शाता है।

इंटरनेट मीडिया यूजर्स और पत्रकारों ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। कहा, मंत्री जनता के प्रतिनिधि होने के बजाय 'वफादार नौकरों' की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विपक्ष और जनता ने पीएमएल-एन पर सेना को खुश करने के लिए राजनीति के स्तर को गिराने का आरोप लगाया है।

अमेरिकी कंपनी के मालिक ने 540 कर्मियों को रातोंरात बनाया करोड़पति

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क

- 1.7 अरब डालर में बेची कंपनी, 24 करोड़ कर्मियों में बांटने की घोषणा
- जिस दिन इसकी घोषणा की गई कर्मचारियों को नहीं हो रहा था विश्वास

अमेरिका निवासी एक शख्स ने अपनी कंपनी में काम करने वाले 540 कर्मियों को रातोंरात करोड़पति बना दिया। दरअसल, शख्स ने अपनी कंपनी को 1.7 अरब डालर में बेच दिया और 540 कर्मियों को उसमें से 24 करोड़ डालर बांट दिए। प्रत्येक कर्मी को औसतन 443,000 अमेरिकी डालर (करीब 41830496 रुपये) मिलेंगे।

वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, फाइबरबांड कार्प के पूर्व सीईओ ग्राहम वाकर ने अपनी कंपनी को गत वर्ष 1.7 बिलियन डालर में बेच दिया था। समझौते पर हस्ताक्षर से पहले उन्होंने शर्त रखी कि बिक्री से प्राप्त राशि का 15 प्रतिशत उनके कर्मियों को जाएगा। जब इसकी घोषणा की गई तो कई कर्मचारी भावुक और स्तब्ध रह गए।

पूरी राशि पाने के लिए कंपनी से जुड़े रहना जरूरी : जून से शुरू होने वाले भुगतान में एक रिटेंशन एग्रीमेंट है, जिसका अर्थ है कि कर्मियों को पूरी राशि प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ पांच वर्षों तक काम जारी रखना होगा। हालांकि, 65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों को इस शर्त से छूट दी गई है।

परिवार ने सबसे बुरे दौर में भी कर्मियों को वेतन देना जारी रखा था: फाइबरबांड की शुरुआत 1982 में वाकर के पिता क्लाउड ने टेलीफोन व बिजली के उपकरणों के लिए संरचनाएं बनाने के लिए की थी। 1998 में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। इसके तुरंत बाद डाट-काम क्रैश ने मांग को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे कर्मियों की संख्या 900 से 320 रह गई। कर्मचारियों ने वाशिंगटन जर्नल को बताया कि वाकर परिवार ने सबसे बुरे दौर में भी कर्मचारियों को वेतन देना जारी रखा।

भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ आठ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

पोर्ट आफ स्पेन, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो दिनी कैरेबियन यात्रा के दौरान भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा, जयशंकर ने 8-9 मई को कैरेबियन देश की यात्रा की, जहां उन्होंने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर व अन्य नेताओं संग द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही गत वर्ष पीएम मोदी की त्रिनिदाद व टोबैगो यात्रा के दौरान की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बिसेसर की उपस्थिति में, जयशंकर ने चयनित स्कूली बच्चों को 2,000 लैपटाप का पहला बैच सौंपा। कृषि-प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन भी किया, जिसके लिए भारत ने गत वर्ष 10 लाख अमेरिकी डालर की मशीनरी मुहैया कराई थी। बिसेसर व जयशंकर ने पेनाल में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र का उद्घाटन किया।

हंटावायरस से प्रभावित क्रूज से यात्रियों को निकालकर भेजा जा रहा उनके देश

टेनेरिफ, रायटर: हंटावायरस से प्रभावित क्रूज (जहाज) से रविवार को उतरे यात्रियों व चालक दल के सदस्यों के को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अफसरों की देखरेख में चल रही है और सोमवार तक जारी रहने की उम्मीद है। अफसरों ने बताया कि किसी भी यात्री में वायरस के लक्षण नहीं थे। उन्हें सैन्य बसों में टेनेरिफ हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से उनके देश द्वारा भेजे गए विमानों से द्वीप से भेजा जाएगा। यात्रियों को 42 दिन क्वारंटाइन रहने को कहा गया। क्रूज के चालक दल के 30 सदस्य व एक यात्री का शव जहाज पर ही रहेगा। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जहाज की उचित जांच पूरी होने की रिपोर्ट में कहा, "अर्जेंटीना व चिली से, जो इस वायरस के घर है, हर साल 500 से अधिक क्रूज जहाज आते हैं, पर यूरोप में इस बीमारी का प्रकोप कभी नहीं हुआ है। यह भी कहा, जहाज पर कोई चूहा नहीं मिला।

संपादकीय जागरण

सोमवार, 11 मई, 2026 : ज्येष्ठ कृष्ण - 9 वि. 2083

व्यक्ति के स्वभाव का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है

केरलम में देरी

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिलने के एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर कोई फैसला न हो पाना पार्टी नेतृत्व की दुविधा और कमजोरी को ही बयान करता है। यदि राज्य में मुख्यमंत्री चयन में और अधिक देरी होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच असमंजस बढ़ने के साथ उनके उत्साह में तो कमी आएगी ही, नेताओं और विशेष रूप से विधायकों के बीच गुटबाजी को भी हवा मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला के समर्थकों के बीच एक तरह का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऐसा शक्ति प्रदर्शन कई बार कलह में तब्दील हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव पूरी पार्टी पर पड़ता है। यह ध्यान रहे कि हाल के विधानसभा चुनावों में केवल केरलम में ही कांग्रेस अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाई है। बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उसे निराशा ही हाथ लगी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में इसलिए देरी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं।

कोई भी दल हो, मुख्यमंत्री चयन में आलाकमान को अपनी पसंद थोपने के स्थान पर विधायकों की राय को प्राथमिकता देने के साथ समर्थकों के मूड-मिजाज को भांपना चाहिए। जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, वे राजनीतिक नुकसान ही उठाते हैं। हो सकता है कि केरलम के कुछ विधायक केसी वेणुगोपाल को भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता देखना चाह रहे हों, लेकिन तथ्य यह है कि वे तो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़े थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का यह कोई उचित अथवा लोकतांत्रिक आधार नहीं हो सकता कि वे राहुल गांधी के विश्वासपात्र हैं। यदि मुख्यमंत्री चयन में विधायकों और समर्थकों की राय की अनदेखी करने की कोशिश की जाएगी तो फिर सहयोगी दल भी अपनी राय थोपने की चेष्टा करेंगे। केरलम में मुख्यमंत्री चयन में देरी इसलिए अधिक ध्यान खींच रही है, क्योंकि चुनाव वाले अन्य राज्यों और यहां तक कि त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री तय हो गया। केरलम में मुख्यमंत्री पद के चयन में जितनी अधिक देरी होगी, इस पद के दावेदारों के बीच खींचतान उतनी ही बढ़ेगी। यह खींचतान इस निर्देश से थमने वाली नहीं है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के समर्थक किसी तरह की टीका-टिप्पणी अथवा अभद्र व्यवहार न करें। केरलम में मुख्यमंत्री के चयन में जो देरी हो रही है, उससे यह भी नए सिरे से रेखांकित हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व समय पर फैसले नहीं ले पाता।

तत्परता जरूरी

दिल्ली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एजेंट और हथियार तस्करों की मिलीभगत के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। आइएसआइ एजेंट शहजाद भट्टी के बाद अब दिल्ली पुलिस को हथियार तस्कर शाहबाज अंसारी के तार भी आइएसआइ से जुड़ने की जानकारी मिली है। यही नहीं, ये भी सामने आया है कि दिल्ली के गैंग्सटर भी अंसारी के संपर्क में हैं और उससे हथियारों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक हथियार तस्कर के गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को उससे पूछताछ में ये जानकारी मिली है।

आइएसआइ एजेंट से हथियारों की खरीद करने वाले गैंग्सटर के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए

आइएसआइ एजेंट के हथियार तस्करों से संबंध पहले ही दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए चिंताजनक हैं और अब इन तस्करों का दिल्ली में सक्रिय गैंग्सटर से संपर्क दर्शाता है कि ये पूरा गठजोड़ कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अंसारी से जुड़े माड्यूल के अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से विदेशी हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। राजधानी और देश की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल सेल को इस गठजोड़ को जल्द से जल्द पूरी तरह ध्वस्त करना चाहिए, ताकि न ही दिल्ली में अवैध रूप से हथियार एकत्रित हो सकें और न ही हथियारों की खरीद-फरोख्त से होने वाली आय का आइएसआइ देशविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

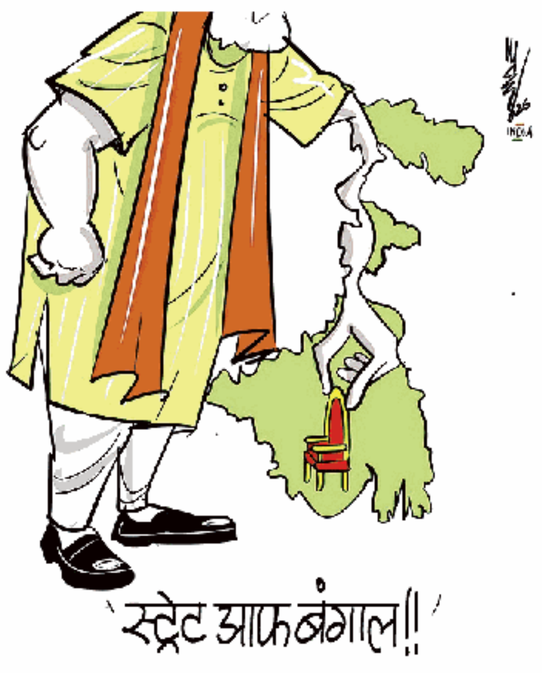

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व में पांच साल स्थिर सरकार चलने की उम्मीद है?

आज का सवाल

क्या द्रमुक और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आइएनडीआइए की स्थिति को कमजोर करेगी?

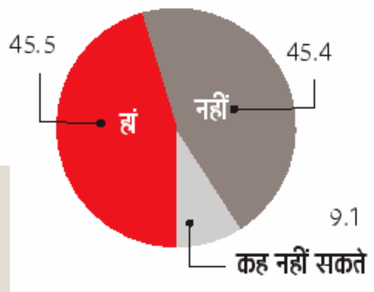

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

अटूट आस्था का शाश्वत प्रतीक सोमनाथ

योगी आदित्यनाथ

'नया भारत' आज सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनवी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव-अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है

अवधेश राजपूत

भारत केवल एक भूभाग नहीं, अपितु हजारों वर्षों की सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत राष्ट्र है। भारतीय दर्शन कहता है कि आत्मा अजर-अमर है, वह केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार भारत की सनातन संस्कृति और उसकी आस्था भी अनश्वर है। इतिहास साक्षी है कि इस चेतना को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, किंतु न इसे झुकाया जा सका, न समाप्त किया जा सका। सौराष्ट्र में समुद्र तट पर अवस्थित श्री सोमनाथ मंदिर उसी अमर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तेजस्वी प्रतीक है। विगत एक हजार वर्षों का कालखंड इसका प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता हर क्षण अडिग रही। आज जब भारतवर्ष 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं, अपितु भारत के आत्मा, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान को पुनः अनुभव करने का पावन अवसर भी है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ने शताब्दियों के असंख्य आक्रमण और विध्वंस देखे, किंतु हर बार वह और अधिक गौरव एवं तेज के साथ पुनः स्थापित हुआ। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक अनेक आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर वे स्वयं इतिहास में विलीन हो गए और सोमनाथ मंदिर अडिग खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जब देश विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितताओं से गुजर रहा था, तब हर भारतवासी यह अनुभव कर रहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, भारत को सांस्कृतिक स्वाधीनता का भी पुनर्स्थापन करना होगा। ऐसे समय में लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह केवल एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं, स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प था। सरदार पटेल जानते थे कि यदि राष्ट्र को आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव से जुड़ना ही होगा। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था कि स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि सरदार पटेल अपने उस स्वप्न को साकार होते नहीं देखे सके, पर प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डा. राजेंद्र प्रसाद का यह निर्णय इसकी उद्घोषणा था कि भारत के सांस्कृतिक आत्मा को किसी वैचारिक आग्रह से दबाया नहीं जा सकता।

आज, अमृतकाल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 'स्व' से साक्षात्कार कर रहा है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही कालखंड है। जो कार्य स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल और डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ किया था, वही चेतना आज मोदी जी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी पांच शताब्दियों के संघर्ष, धैर्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान की ऐतिहासिक परिणति है। कभी जिन आक्रांताओं ने श्रीरामजन्मभूमि को अपमानित कर भारत की आस्था पर प्रहार किया था, आज उनका नाम इतिहास के अंधकार में खो चुका है, किंतु प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है।

इसी क्रम में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास काशी की जीवंतता और भारत की सनातन चेतना के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज वैश्विक स्तर पर भी भारत की इस सांस्कृतिक चेतना को नई स्वीकृति प्राप्त हो रही है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, अध्यात्म और सनातन जीवनदृष्टि के प्रति विश्व का आकर्षण निरंतर बढ़ रहा है। यह केवल सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, यह भारत की उस शाश्वत दृष्टि की स्वीकृति है, जो मानवता को संतुलन, सहअस्तित्व और समरसता का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 'नया भारत' आज 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के रूप में सनातन आस्था के सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मना रहा है और गजनी जैसे आततायियों के विध्वंस पर उल्लास, सृजन और वैभव का नव-अंकुर प्रस्फुटित हो रहा है।

सोमनाथ का पुनर्निर्माण इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें स्मरण कराता है कि कोई भी राष्ट्र केवल आर्थिक शक्ति से महान नहीं बनता। उसकी वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक चेतना, उसके ऐतिहासिक आत्मविश्वास और उसकी सभ्यतागत निरंतरता में निहित होती है। जिन राष्ट्रों ने अपनी जड़ों को भुला दिया, वे इतिहास में धीरे-धीरे कमजोर पड़ गए, किंतु भारत ने हर युग में अपने आत्मा को सुरक्षित रखा। आज जब हम पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह अवसर नई पीढ़ी को भारत के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने का भी है। यह पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत की उत्तराधिकारी भी है। उसे यह समझना होगा कि भारत का उत्थान केवल आर्थिक प्रगति से संभव नहीं है। भारत तब पूर्ण रूप से विकसित और शक्तिशाली बनेगा, जब वह अपने आत्मा से जुड़कर आगे बढ़ेगा। श्री सोमनाथ मंदिर हमें यह भी स्मरण कराता है कि पुनर्निर्माण केवल भौतिक नहीं होता, वह मानसिक और राष्ट्रीय भी होता है। जब कोई समाज अपने टूटे हुए प्रतीकों को पुनः स्थापित करता है, तब वह केवल भवन नहीं बनाता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करता है। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ हमें यही प्रेरणा देती है कि राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा होता है। यदि संस्कृति सुरक्षित है, तो राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित है।

आइए, इस अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाएंगे। भावी पीढ़ियों को अपनी सभ्यता का गौरव समझाएंगे और अमृतकाल में भारत को उसके वास्तविक वैश्विक स्वरूप तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जय सोमनाथ!

(लेखक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

response@jagran.com

भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इस बार केवल सत्ता का गणित नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र के अर्थ को भी एक नई सामाजिक व्याख्या दी है। आसग्राम से कलिता माझी, हिंगलगंज से रेखा पात्रा और पनिहाटी से रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत केवल चुनावी सफलता नहीं है। यहां एक घरेलू सहायिका है, एक श्रमिक और वंचित वर्ग से आई महिला है तो एक ऐसी मां भी है जिसने अपनी निजी पीड़ा और सामाजिक अपमान को अपनी शक्ति और दृढ़निश्चय में बदल दिया। इन महिलाओं की उपस्थिति भारतीय राजनीति के उस बदले हुए चेहरे को सामने लाती है, जहां पहली बार हाशिए पर खड़ी दिखाई देने वाली स्त्रियां सत्ता और प्रतिनिधित्व के केंद्र में दिखाई देने लगी हैं। इन महिलाओं की जीत को यदि हम मात्र चुनावी परिणाम के रूप में देखेंगे तो यह हमारी सामाजिक दृष्टि की असफलता होगी। चुनावी आंकड़ों और राजनीतिक विमर्शों से परे इन महिलाओं की जीत नारी सशक्तीकरण का हस्ताक्षर है। यही वह नारी सशक्तीकरण है, जिसका आह्वान स्वतंत्रता के बाद से लगातार किया जाता रहा है और जिसकी चर्चा बौद्धिक तथा वैचारिक वर्ग वर्षों से करता आया है।

कलिता माझी, रेखा पात्रा और रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत के साथ स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि भारत में नारीवादी विचारधारा के समर्थक और उसके मुखर प्रवर्तक खुलकर इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। यह अपेक्षा इसलिए भी थी, क्योंकि वर्षों से स्त्री-प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्वकारी उपस्थिति को लेकर निरंतर आवाज उठाई जाती रही है। किंतु आश्चर्य यह है कि तमाम डिजिटल मीडिया मंचों से लेकर वैचारिक और बौद्धिक विमर्शों तक एक विचित्र-सी चुप्पी दिखाई देती है। वे स्वर, जो सामान्यतः स्त्री-अधिकारों और महिला नेतृत्व के प्रश्न पर अत्यंत मुखर दिखाई देते हैं, आज कहीं खो से गए हैं। नारीवादी चिंतक नैंसी फ्रेजर अपने चर्चित निबंध 'फ्राम रीडिस्ट्रिब्यूशन टू रिकग्निशन?' में इस बात पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं कि यदि नारीवाद केवल कुछ सफल और विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की उपलब्धियों

डा. ऋतु सारस्वत

बंगाल में कलिता माझी, रेखा पात्रा, रत्ना देवनाथ की जीत ही वास्तविक नारी सशक्तीकरण है और ऐसा ही होना चाहिए

महिलाओं का बढ़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व ● फाइल

तक सीमित रह जाए तो वह समाज की वास्तविक असमानताओं को नहीं बदल सकता। शायद यही कारण है कि जब साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन से निकली महिलाएं राजनीति और सार्वजनिक नेतृत्व तक पहुंचती हैं तो समाज उन्हें उतनी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, जितनी सहजता से प्रभावशाली और संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को स्वीकार करता है। बेल हुक्स ने अपनी पुस्तक 'फेमिनिस्ट थ्योरी : फ्राम मार्जिन टू सेंटर' में लिखा है कि मुख्यधारा का नारीवादी विमर्श लंबे समय तक मुख्यतः विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं के अनुभवों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। शायद यही कारण है कि श्रम, अभाव और संघर्ष से निकली महिलाओं को वह सहज स्वीकार्यता, प्रशंसा और मान्यता नहीं मिल पाती, जो प्रभावशाली और संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो जाती है।

भारत की कोई भी राजनीतिक विचारधारा अथवा दल जब दलित, वंचित और संघर्षशील महिलाओं को मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचाने का अवसर देता है, तब सबसे पहले उन महिलाओं के साहस और संघर्ष को सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें केवल किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखकर मौन हो जाना शायद उस व्यापक सामाजिक उद्देश्य को सीमित कर देना है, जिसकी बात दशकों से की जाती रही है। नारीवाद का उद्देश्य केवल स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिलाना नहीं, बल्कि लैंगिक शोषण और दमन की संरचनाओं को समाप्त करना है। स्त्री संघर्ष को केवल वैचारिक विमर्शों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता, उसे उन महिलाओं के जीवनानुभवों, वर्गीय संघर्षों और सामाजिक यथार्थ के साथ भी जोड़कर समझना होगा, जो हाशिए से निकलकर नेतृत्व तक पहुंचती हैं। तब उसका प्रभाव केवल निजी उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। यह स्थिति समाज की लोकतांत्रिक कल्पना, स्त्री आकांक्षाओं और प्रतिनिधित्व की पारंपरिक सीमाओं को भी बदलती है।

विडंबना यह है कि स्त्री-प्रतिनिधित्व और महिला नेतृत्व की चर्चा करने वाले समाजों में भी, जब अत्यंत साधारण, श्रमिक या सामाजिक रूप से उपेक्षित पृष्ठभूमि की महिलाएं राजनीति में पहुंचती हैं तो उनकी उपस्थिति को लेकर एक सूक्ष्म असहजता दिखाई देने लगती है। समस्या केवल स्त्री के राजनीति में आने की नहीं होती, बल्कि इस बात की भी होती है कि वह किस वर्ग और किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आई है। समय आ गया है कि स्वयं को नारीवाद का समर्थक कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह प्रश्न पूछे कि क्या वह कहीं चयनात्मक नारीवाद का शिकार तो नहीं। क्या वह वास्तव में हर उस महिला के साथ खड़ा है, जो वंचना, श्रम और सामाजिक उपेक्षा से निकलकर नेतृत्व तक पहुंचती है या फिर उसका समर्थन केवल उन महिलाओं तक सीमित रह जाता है, जिनसे वह वैचारिक या सामाजिक रूप से सहज महसूस करता है। यदि स्त्री संघर्ष और महिला नेतृत्व को भी पसंद-नापसंद तथा वैचारिक सुविधा के आधार पर स्वीकार किया जाएगा तो वह नारीवाद नहीं, बल्कि चयनात्मक नारीवाद बनकर रह जाएगा।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संभावनाएं

सृष्टि में सब कुछ अस्थायी है, किंतु जीवनदायी तत्वों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, भले ही वे कभी परिलक्षित नहीं होते। इसीलिए धरती पर जीवन-प्रक्रिया सदा गतिमान रहती है। संभावना ऐसा ही तत्व है, जो आशाएं क्षीण होने पर भी तन-मन में जीवनी शक्ति का संचार करता है और संसाधनों के नष्ट होने पर भी सफलता के नए द्वार खोलता है। संभावनाओं का संसार व्यापक होने से ये जीवन को विस्तार देती हैं। अतः इनके रहते जीवन कभी नहीं मरता। यद्यपि विधाता ने सबको समान अवसर उपलब्ध कराए हैं, किंतु फलप्राप्ति खुद के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। धैर्य, साहस एवं पराक्रम विपरीत परिस्थितियों में भी नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। जैसे प्रलयकाल के समय सब कुछ नष्ट हो जाने पर संभावनाएं पुनर्जीवन का इतिहास रचती हैं, उसी प्रकार उम्मीद न रहने पर भी संभावनाएं स्वयं उम्मीद बन जाती हैं। संभावनाएं साकार करने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण आज यही शिक्षा जीवन लेने का कारण बन रही है। असफल होने पर ही नहीं, कुछ कम अंक आने या रोजगार में देरी होने पर बच्चों में बढ़ रही अवसाद की प्रवृत्ति उनके जीवन को निगल रही है। बड़ों का दायित्व है कि संबल बनकर उन्हें तैयार करें कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होतीं। शत-प्रतिशत अंक न ज्ञान में प्रवीणता के प्रमाण हैं, न नौकरी पाने की गारंटी। कम अंक होने पर भी श्रेष्ठतम ज्ञान नवीन संभावनाओं को जन्म देता है, क्योंकि ज्ञान से कुछ भी अलभ्य नहीं।

निराश-हताश युवाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणास्रोत है। वे कहते हैं, 'आकाश की तरफ देखो, तुम अकेले नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है। इसके अनंत विस्तार में तुम्हें अनंत संभावनाएं नजर आएंगी, जो जीवन को उच्च शिखर पर ले जाएंगी।' अतः असफल होने पर भी इस विषम जीवन-यात्रा में संभावनाओं की डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

बंगाल के सामने असली चुनौती

'बंगाल को पटरी पर लाने की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि बंगाल केवल चुनावी नारों और वैचारिक संघर्षों से आगे बढ़कर ही अपनी वास्तविक क्षमता प्राप्त कर सकता है। यह विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व का केंद्र रहा बंगाल आज रोजगार पलायन, राजनीतिक हिंसा और आर्थिक ठहराव जैसी समस्याओं से जूझता दिखाई देता है। वास्तविक समस्या केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक विश्वास की है। कोलकाता, हावड़ा और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पहले जैसी आर्थिक सक्रियता दिखाई नहीं देती। बड़ी संख्या में युवा आज रोजगार के लिए बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद की ओर पलायन कर रहे हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक कमजोरी नहीं, बल्कि राज्य के भीतर घटते सामाजिक आत्मविश्वास को भी दर्शाती है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योग और ग्रामीण निवेश जैसे बुनियादी मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर सुंदरवन क्षेत्र तक स्थानीय अर्थव्यवस्था आज भी स्थायी विकास की प्रतीक्षा कर रही है। बंगाल को वास्तव में पटरी पर लाना है तो राजनीतिक संघर्ष से अधिक आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान देना होगा। केवल वैचारिक बहसें किसी राज्य को आगे नहीं बढ़ातीं। निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन ही किसी प्रदेश की स्थिर प्रगति का आधार बनते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बंगाल अपनी बौद्धिक विरासत को आधुनिक आर्थिक दृष्टि से जोड़कर विकास की नई दिशा तलाशे।

awanishg30@gmail.com

जनाकांक्षाओं का परिणाम

बंगाल की राजनीति में में परिवर्तन केवल एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि लंबे राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक धैर्य व जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में अंततः जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। वर्षों तक बंगाल की राजनीति में प्रभाव रखने वाली ममता बनर्जी व टीएमसी को जिस प्रकार जनता ने कठोर संदेश दिया, वह जनीति में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता ने ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन को उखाड़ फेंका। जीत इस बात का प्रमाण है कि सत्ता के नशे में चूर, अनैतिक और भ्रष्ट शासन का अंत निश्चित है। बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति महाभारत काल से मिलती-जुलती है, जहां ममता की भूमिका धृतराष्ट्र के समान रही, जो अपने सहयोगियों और परिवार के मोह में नैतिकता को ताख पर रखकर नियमों के विपरीत कार्य करती रहीं। आशा है कि बंगाल में भाजपा की यह विजय, राष्ट्रवाद और सुशासन की जीत है, जो बंगाल को जंगल राज से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा में लाएगी।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

धरती बचाने की चिंता करे दुनिया

धरती कराह रही है। कहीं पानी खत्म हो रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं जंगल जल रहे हैं और अब दुनिया के बड़े-बड़े शहर धीरे-धीरे जमीन में धंसने लगे हैं। यह केवल विज्ञानियों की चिंता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य का सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जकार्ता, ढाका, बैंकाक, मेक्सिको सिटी और शंघाई जैसे शहरों का धीरे-धीरे धंसना इस बात का संकेत है कि प्रकृति अब मानव के अत्यधिक दोहन का जवाब देने लगी है। धरती धंसने का सबसे बड़ा कारण भूजल का अंधाधुंध दोहन है। इंसान जमीन के नीचे जमा हजारों साल पुराने पानी को इतनी तेजी से निकाल रहा है कि मिट्टी और चट्टानों के बीच की खाली जगहें सिकुड़ रही हैं। परिणामस्वरूप जमीन नीचे बैठने लगती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी जल संकट की स्थिति में पहुंच चुकी है। पानी का दिवालियापन अब कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बनता जा रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई आदि भी तेजी से भूजल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को भयावह बना दिया है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। विज्ञानियों के अनुसार, वैश्विक तापमान बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर एक मीटर तक बढ़ सकता है। धरती को बचाने के लिए गंभीरता दिखाई नहीं देती। यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी, स्वच्छ हवा व सुरक्षित जमीन तक नसीब नहीं होगी।

विभूति बुपक्या, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

पोस्ट

अखिलेश दो बार हारे। तेजस्वी दो बार हारे। शरद पवार पार्टी नहीं बचा पाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। केजरीवाल अपनी सीट हार गए। ममता दो बार अपनी सीट हारीं। स्टालिन अपनी सीट हार गए। नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए। लेकिन सीखने को कोई तैयार नहीं।

आशुतोष@ashutosh83B

विजय के पास 108 सीटें हैं, जबकि भाजपा को हटा दें तो अन्नाद्रमुक के ए. पलानीस्वामी के पास 46 सीटें हैं। विजय अगर इसके साथ मिलकर सरकार बनाते तो सरकार चलाना अपेक्षाकृत आसान होता। विजय जनता के बीच लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है।

मुथुकृष्णन@dmuthuk

अभिनेता से नेता बने एमजीआर के माता-पिता मलयाली थे। सुपरस्टार रजनीकांत की मातृभाषा मराठी है। विजय ईसाई हैं, लेकिन हिंदू बहुल आबादी वाले तमिलनाडु की जनता ने उन्हें उनके पहले ही चुनाव में सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। यह दर्शाता है कि लोगों के दिलों को जीतने के मामले में तमिलनाडु में न तो धार्मिक पहचान आड़े आती है और न ही भाषाई दीवार। स्टैनले जानी@johnstanly

जनपथ

ममता की सत्ता गई जो बनती थीं 'मर्द',
बगल बांग्लादेश में कुछ को होता दर्द।
कुछ को होता दर्द कह रहे लड़ो लड़ाई,
देंगे पूरा साथ बांग्लादेशी भाई!
शुभचिंतक हैं कौन? गौर से देखे जनता!
किसके दम पर कूद रही थीं दीदी ममता!!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 296

क्या आपरेशन सिंदूर से मिले सबक ने रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है?
हां 75%
नहीं 25%

क्या भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है ?
हां 80%
नहीं 20%

आपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूरे हो गए हैं। यह आपरेशन 88 घंटे का था, लेकिन आधुनिक युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मन के हवाई क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करने की शानदार नजीर बना। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाने के साथ उसके 13 विमानों को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध में ड्रोन ने भी अहम भूमिका निभाई। भारत में बने हथियारों और रक्षा उपकरणों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व को दिखाया कि भारत स्वदेशी हथियारों के दम पर निर्णायक युद्ध लड़ने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में कमियों का भी पता चलता है और आपरेशन सिंदूर भी इसका अपवाद नहीं रहा। संघर्ष में चीन पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की रणनीतिक मदद मुहैया कर रहा था। भारत इससे सबक लेते हुए चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती के मद्देनजर सेनाओं के आधुनिकीकरण और आपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले एक वर्ष में सैन्य क्षमता के मामले में देश कितना सशक्त हुआ है इसकी पड़ताल अहम मुद्दा है..

कितना सशक्त हुआ देश

प्रतिक्रिया नहीं पराक्रम दिखाएगा भारत

3 लाख करोड़ से अधिक के 114 राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया अंतिम दौर में

1.85 लाख करोड़ रखे गए हैं नए हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 2026-27 के बजट में

24% तक बढ़ाया गया है नए हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए बजट

2.5% जीडीपी तक रक्षा खर्च पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है केंद्र सरकार अगले पांच वर्ष में

भारत का रक्षा उत्पादन

(लाख करोड़ रुपये में)

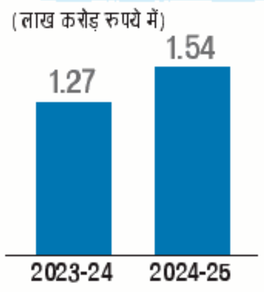

65% रक्षा उपकरण भारत में बनाए जा रहे हैं, पहले 70 प्रतिशत तक आयात पर थी निर्भरता

9,145 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर और तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर ने मिलाकर

16,000 एमएसएमई अपने उत्पादों के लिए जरिये मजबूत कर रही हैं स्वदेशी रक्षा क्षमताएं

788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए गए हैं 462 कंपनियों को

रक्षा निर्यात (करोड़ रुपये में)

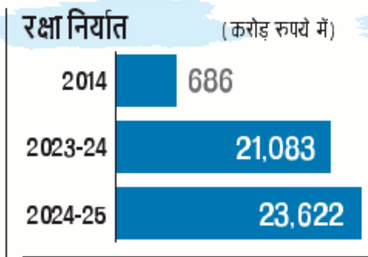

स्वदेशी का दम

आपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य रणनीति और पाकिस्तान-चीन के संयुक्त खतरे से निपटने की तैयारियों में एक बड़ा बदलाव आया है। 7-10 मई 2025 के बीच चले इस आपरेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब रणनीतिक धैर्य की नीति को त्याग कर निवारक प्रतिशोध की राह पर है। इसके लिए भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है।

स्वदेशी मारक क्षमता और ब्रह्मोस-एक्स

आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने ब्रह्मोस-एक्स मिसाइल के विकास को गति दी है, जिसकी गति मैक 4.5 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा, स्वदेशी तेजस मार्क-1ए और राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा चीन के बढ़ते हवाई खतरे को संतुलित करने के लिए एलएसी के करीब तैनात किया गया है।

उन्नत वायु रक्षा प्रणाली

आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई चीनी मिसाइलों (जैसे सीएम-401) को विफल करने के बाद, भारत अब अपने एस-400 ट्रायम्फ नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। मई 2026 तक रूस से शेष एस-400 यूनिट की डिलीवरी और इंडक्शन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही, स्वदेशी आकाश और एमआरएसएम प्रणालियों को उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया गया है ताकि चीन-पाक मिसाइल गठजोड़ को निष्प्रभावी किया जा सके।

डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग हब

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यूपी में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर विकसित किया जा रहा है। यूपी डिफेंस कारिडोर को 6 मुख्य शहरों (नोड्स) में विभाजित किया गया है, जहां अलग-अलग प्रकार के रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं:

लखनऊ : यहां ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सेना को सौंपा जा चुका है। लखनऊ यूनिट में सालाना 150 ब्रह्मोस बनाने की क्षमता है।

कानपुर : यह डिफेंस कारिडोर का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहां अदाणी डिफेंस ने एशिया का सबसे बड़ा गोला-बारूद और मिसाइल काम्प्लेक्स स्थापित किया है। बुलेटप्रूफ जैकेट, पैराशूट और छोटे हथियारों का भी निर्माण हो रहा है।

झांसी : यहां एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और विस्फोटक सामग्री बनाने की इकाइयां लगाई जा रही हैं।

अलीगढ़ : यह नोड छोटे हथियारों, रडार सिस्टम और ड्रोन मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध हो रहा है।

चित्रकूट और आगरा : यहां डिफेंस टेस्टिंग सेंटर और इलेक्ट्रानिक्स आधारित रक्षा उपकरणों के निर्माण पर फोकस है।

भविष्य की पैदल सेना

भारतीय सेना ने 2026 में भैरव फोर्स जैसे विशेष कमांडो दस्तों का गठन किया है। ये सैनिक भविष्य के युद्धों के लिए तैयार हैं, जो ड्रोन और उन्नत मिसाइल प्रणालियों से लैस हैं। इनका मुख्य कार्य सीमापार आतंकी ढांचों और चीनी सैन्य जमावड़े के खिलाफ सटीक ड्रोन स्ट्राइक करना है।

तकनीकी और एआइ का एकीकरण

भारत ने अपने सी4आइएसआर- कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनिसेंस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा है। यह तकनीक दुश्मन के रडार को जाम करने, लक्ष्य की पहचान करने और मिसाइल इंटरसेप्शन में मानवीय त्रुटि को कम करने में मदद कर रही है।

रिसर्च: महेंद्र सिंह

टू-फ्रंट वार के लिए थिएटर कमांड का गठन

भारत ने अपनी सैन्य संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की स्थापना को तेज कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य थल सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय स्थापित करना है ताकि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर एक साथ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ाएं उत्पादन क्षमता

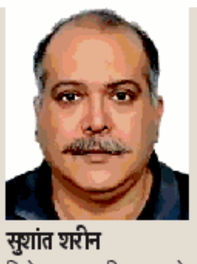

सुशांत शरीन
विशेषज्ञ, सामरिक मामले

आपरेशन सिंदूर में चले चार दिनों के संघर्ष के लिए हमारी सैन्य तैयारियां पर्याप्त साबित हुईं लेकिन महीनों तक चलने वाले युद्ध के लिए जरूरी है कि मिसाइलों, इंटरसेप्टर और ड्रोन का भंडार तैयार किया जाए। हमारी घरेलू उत्पादन क्षमता यहां निर्णायक भूमिका निभाएगी। रक्षा उद्योग को उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी।

आपरेशन सिंदूर के समय भारत की सैन्य तैयारियों का स्तर पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले भारत में भी विशेषज्ञ और दूसरे देश भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी स्वदेशी रक्षा प्रणालियां हैं, वे युद्ध के मैदान में कितनी कारगर साबित होंगी। आपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि रूस से आयातित एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हमारे स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान ने हमारी सीमा की ओर जो कुछ भी फेंका हमने उसे काफी किफायती तरीके से नष्ट कर दिया। यहां किफायती तरीका इसलिए अहम है क्योंकि हमने हाल में अमेरिका-ईरान युद्ध में देखा कि 10,000 डालर के ड्रोन को मार गिराने के लिए लाखों डालर की मिसाइलें इस्तेमाल की गईं।

मिसाइल हो, इंटरसेप्टर हों या एयर डिफेंस, चार दिन के संघर्ष के लिए तो यह पर्याप्त साबित हुआ लेकिन हमें देखना होगा कि अगर युद्ध एक दो माह तक खिंच जाता है तो उसके लिए मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियारों के भंडार की क्या स्थिति है। हाल में देखा गया कि बड़ी संख्या में अमेरिकी मिसाइलें ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में खत्म हो गए और अमेरिका में इस बात पर बहस चल रही है कि रणनीतिक भंडार को भरने में कितना समय लग सकता है। आधुनिक युद्ध के दौर में यह जरूरी है कि आपके पास घरेलू स्तर पर यह क्षमता हो कि लंबे समय तक खिंचने वाले युद्ध के लिए आवश्यक मात्रा में हथियार, मिसाइलें ड्रोन और दूसरे सैन्य साजो सामान का हम तेजी से उत्पादन कर सकें। इसके अलावा दूसरी अहम बात तकनीक का तेजी से बदलना है। आज कल तकनीक हर छह महीने में बदल रही है। हो सकता है कि हम कोई रक्षा प्रणाली विकास के बाद जब तक उत्पादन के चरण में ले जाएं, तब तक वह तकनीक पुरानी हो जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि यह तकनीक बेकार हो गई। हमें तकनीक को तेजी से अपग्रेड करने में सक्षम बनना पड़ेगा, तभी हम युद्ध के परिदृश्य में कारगर होने के लायक हथियार और रक्षा उपकरण बना पाएंगे। हमारे लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है क्योंकि हमारे सामने ऐसा दुश्मन है जिसका समर्थन एक तरफ चीन कर रहा है, जो तकनीकी तौर पर काफी आगे हो गया। तुर्किये का समर्थन भी पाकिस्तान को मिल रहा है। हम तकनीक और कुछ रक्षा उपकरणों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं और तुर्किये नाटो का सदस्य है और उसकी पहुंच भी पश्चिमी देशों की तकनीक तक है। ऐसे में हमें इस बात को लेकन सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान को तुर्किये से ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं, जिसके जरिये वह हमारे रक्षा उपकरणों का तोड़ निकाल सकता है। एक और बात है युद्ध में सरप्राइज की। आपरेशन सिंदूर में भी यह बात दिखी कि पाकिस्तान ने पहले हमें चौंकाया फिर उसके बाद हमने इस बात को समझ कर उस पर हमले किए। हमें भविष्य के लिए पहले से सरप्राइज के लिए तैयार रहना होगा। अगर पाकिस्तान 200 मिसाइलों से दिल्ली को निशाना बनाता है तो यह संभव है कि हम 95 प्रतिशत मिसाइलें रोक लें लेकिन 5 मिसाइलें भी गिरीं तो नुकसान होगा। हमें इस बात को लेकर तैयार रहना होगा क्योंकि 100 प्रतिशत मिसाइलें अमेरिका और इजरायल भी नहीं रोक पा रहे हैं। हमें अपनी जनता को भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा और उनको बताना कि इसमें जो भी नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी।

आपकी आवाज

एक साल पहले कश्मीर मे पर्यटन के लिए गए देश के मासूम नागरिकों को पाकिस्तानी आतताईयों द्वारा मौत की नींद सुलाने और इसके बाद आपरेशन सिन्दूर के तहत पाकिस्तान मे घुसकर आतंकियों का सफाया करना दिखाता है कि हमारी रक्षा प्रणाली काफी सुदृढ़ हैं। इस युद्ध में भारत की हवाई रक्षा प्रणाली ने भी खुद को साबित किया कि वह दुश्मन देश की मिसाइल और ड्रोन केंद्रित रणनीति का मुकाबला पूरी तरह डट कर कर सकती है। इसके बावजूद वायुसेना को भविष्य में अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ किसी भी संघर्ष की स्थिति मे अपने प्लेटफार्म, हथियारों, और रक्षा प्रणालियों को लगातार उन्नत बनाना होगा। **-मुन्ना खर्णकार**

आपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा खरीद की प्रक्रिया में तेजी आई है। सरकार ने रक्षा बजट में भी इजाफा किया है लेकिन भारत के सामने जिस तरह की रक्षा चुनौतियां हैं उसके लिहाज से रक्षा खर्च को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अपने देश में रक्षा खरीद प्रक्रिया को पूरा करने में वर्षों या कई बार दशकों तक समय लगता है। इससे सेना की रक्षा क्षमताओं पर असर पड़ता है। विदेशी आपूर्ति के अलावा घरेलू रक्षा आपूर्ति में भी भी काफी देरी होती है। हमें इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, जिससे सेना को उनकी जरूरत के रक्षा उपकरण समय से मिल सकें। **-मनोज वर्मा**

देश को रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है क्योंकि लंबे युद्ध दूसरे देशों की आपूर्ति के भरोसे नहीं जीते जा सकते हैं। इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं लेकिन हमें शोध एवं विकास में ज्यादा संसाधन लगाने होंगे। **-छाया मिश्रा**

शीर्ष पांच शक्तियों में शामिल हुआ भारत

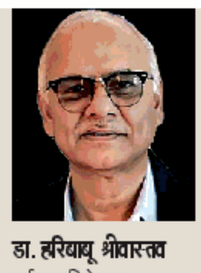

डा. हरिवाबू श्रीवास्तव
पूर्व महानिदेशक, डीआरडीओ

भारत अब जल, थल, नभ के साथ-साथ अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी नए शोध कर रहा है। सरकार इस दिशा में काफी सजग है, जिसका प्रमाण मिशन सुदर्शन की घोषणा है। यह मिशन हमारे सामरिक ठिकानों की चौबीसों घंटे स्वचालित निगरानी करेगा। भारतीय सेना में अब ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक के लिए विशेष यूनिट बनाई जा रही हैं।

मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया आपरेशन सिंदूर आधुनिक भारत के इतिहास की एक स्वर्णिम घटना है। इसका महत्व 1965, 1971 और कारगिल युद्धों की जीत से भी कहीं अधिक माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस युद्ध में भारत की विजय केवल सेना के शौर्य से नहीं, बल्कि भारत की अपनी तकनीक, स्वदेशी रिसर्च और सरकारी व निजी संस्थानों के आपसी तालमेल से हासिल हुई है। जब पाकिस्तान चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों से मिले आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तब भारत के स्वदेशी 'रक्षा कवच' ने युद्ध की कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखी। भारत की इस तकनीकी मजबूती का ही परिणाम है कि साल 2025-26 में हमारे रक्षा उत्पादन और विदेशों को हथियारों के निर्यात में रिकार्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। रक्षा विज्ञानियों के सामने हमेशा यह चुनौती होती है कि वे दुश्मन से दो कदम आगे रहें। एक बार युद्ध में इस्तेमाल होने के बाद हथियारों की तकनीक दुश्मन को पता चल जाती है, इसलिए भारत अब जल, थल, नभ के साथ-साथ अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी नए शोध कर रहा है। सरकार इस दिशा में काफी सजग है, जिसका प्रमाण 'मिशन सुदर्शन' की घोषणा है। यह मिशन हमारे सामरिक ठिकानों की चौबीसों घंटे स्वचालित निगरानी करेगा।

भारतीय सेना में अब ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक के लिए विशेष यूनिट बनाई जा रही हैं। रिसर्च की गति बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। हमारे विज्ञानियों ने सटीक हमले करने, साइबर सुरक्षा और स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने की तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। वर्तमान में भारत कई घातक हथियार तैयार कर रहा है। जैसे कुशा। यह एस-400 से भी उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। प्रलय और पिनाक लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाले मिसाइलें और राकेट सिस्टम है। विज्ञानी ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से चलने वाले इंजन का सफल परीक्षण कर चुके हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास और परीक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस एनजी जैसी नई मिसाइल और तारा जैसी उन्नत हथियार प्रणाली को सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है।

सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निवेश और खरीद की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। आइडीईएक्स और टीडीएफ जैसी योजनाओं की वजह से अब छोटे और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भी रक्षा उपकरण बना रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन योजनाओं में जितना निवेश किया गया, उससे कई गुना ज्यादा तो हमें विदेशों से आर्डर मिल चुके हैं। यह न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। आज भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक एकजुट इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। दुनिया की शीर्ष पांच रक्षा शक्तियों में भारत का नाम शामिल हो चुका है और वह जल्द ही शीर्ष तीन में जगह बना लेगा। आपरेशन सिंदूर के दौरान हमें यह भी पता चला है कि हमारी सेनाओं के पास किस तरह के रक्षा उपकरणों या हथियारों की कमी है। सरकार सेनाओं को अत्याधुनिक रक्षा उपकरण घरेलू या बाहरी स्रोतों से उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए रक्षा बजट में हथियारों और उपकरणों की खरीद के लिए रकम को 18 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का प्रतीक है आपरेशन सिंदूर : रेखा गुप्ता

कार्यक्रम में देशभक्ति गीत प्रस्तुत करते गायक आशीष कुलकर्णी ● जागरण

कनाट प्लेस सेंट्रल पार्क में आपरेशन सिंदूर शौर्य दिवस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा● चंद्र प्रकाश मिश्रा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर रविवार को दिल्ली सरकार ने कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'शौर्य दिवस' मनाया। इसमें भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को नमन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं, राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय सेना की तीनों सेनाओं के जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन यदि कोई देश की ओर गलत नजर उठाएगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन हर चुनौती का सशक्त उत्तर देना जानता है। उन्होंने कहा कि आज का आयोजन वीर सैनिकों के सम्मान और विकसित भारत के संकल्प को दोहराने का अवसर है। इस मौके पर गायक आशीष कुलकर्णी ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से पूरा सेंट्रल पार्क देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, पूर्व सैनिक, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैंक ऋण न चुकाने पर जारी नहीं कर सकते एलओसी : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

- कहा- गबन या हेराफेरी के अपराध में आरोपित न बनाए गए व्यक्ति के खिलाफ मान्य नहीं हो सकती एलओसी
- विभिन्न एजेंसियों के अनुरोध पर 23 याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जारी एलओसी को रद करते हुए अदालत ने की टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कर्ज न चुकाने के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एलओसी एक अंतिम कार्रवाई के रूप में की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही है और बैंक ऋण अदा करने में चूक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिए गए ऋण के हर मामले में एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां एलओसी जारी करने के मामले में व्यक्ति को गबन या हेराफेरी के किसी अपराध में आरोपित नहीं बनाया गया है, वहां एलओसी मान्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही पीठ ने अलग-अलग मामलों में वित्तीय संस्थानों, बैंकों व जांच एजेंसियों के अनुरोध पर 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए एलओसी को रद कर दिया।

पीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि एलओसी की जरूरत, उसकी कानूनी वैधता को सही ठहराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसे जारी करने वाली एजेंसी की होती है। एलओसी अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता।

विभिन्न मामलों में फंसे 23 लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआइ, एसएफआइओ व विभिन्न बैंकों के कहने पर एलओसी जारी किया गया था। इन सभी ने एलओसी को चुनौती दी है। अदालत ने 23 याचिकाओं को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था।

खबर विस्तार से पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

वंदे भारत ट्रेनों की तरह जनशताब्दी और शताब्दी की यात्रा होगी आरामदायक

राज्य ब्यूरो, जागरण● नई दिल्ली: शताब्दी और जनशताब्दी के पुराने कोच आने वाले दिनों में नए रूपरंग में दिखेंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वंदे भारत और अमृत भारत की तरह सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए 100 से अधिक शताब्दी और जनशताब्दी ट्रेनों के कोच का उन्नयन कर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रा के समय झटके लगने की समस्या दूर करने के लिए कपलिंग सिस्टम में भी बदलाव होगा।

इस समय देश में अलग-अलग रूट पर 48 शताब्दी और 54 जनशताब्दी ट्रेनें चल रही हैं। पहली शताब्दी एक्सप्रेस वर्ष 1988 में नई दिल्ली से झांसी के बीच चली थी। इसके बाद कई रूट पर शताब्दी ट्रेनें चलाई गईं। इस समय 24 जोड़ी शताब्दी और 27 जोड़ी जनशताब्दी ट्रेनें चल रही हैं। इन ट्रेनों के रेक काफी पुराने हो गए हैं। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। लगभग 10 वर्ष पहले भी स्वर्ण योजना के अंतर्गत शताब्दी और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के कोच की दशा सुधारने का अभियान चलाया गया था। इसके बावजूद इन ट्रेनों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। वहीं, अब वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनें चलने लगी हैं। मेल एक्सप्रेस के नए कोच में भी बेहतर सुविधाएं हैं। इसे ध्यान में रखकर रेलवे ने शताब्दी व जनशताब्दी ट्रेनों की दशा सुधारने का निर्णय लिया है।

शताब्दी ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी ● आकाइव

48 शताब्दी और 54 जनशताब्दी ट्रेनें इस समय अलग-अलग रूट पर चल रही हैं, ट्रेनों के कोच में होगा बदलाव

अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक शिकायत यात्रा के दौरान झटके महसूस होने को लेकर है। इसे दूर करने के लिए नई तकनीक के शाक एब्जार्बर और बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर लगाए जाएंगे। कोच के अंदर का इंटीरियर भी बदला जाएगा। यात्री के आराम को ध्यान में रखकर एर्गोनोमिक सीटें लगाई जाएंगी। इस तरह की सीट की बनावट इस तरह से होती है कि लंबे समय तक बैठने के बाद भी थकान महसूस न हो। वंदे भारत की तरह प्रत्येक सीट पर यूएसबी चार्जिंग प्वाइंट, मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल स्नैक टेबल भी अधिक सुविधाजनक होगा। लाइटिंग बेहतर की जाएगी। कोच के फर्श भी इस तरह से होंगे कि उसे साफ करना आसान हो। बायवैक्यूम शौचालय लगाए जाएंगे। अभी अधिकांश शताब्दी में जैविक शौचालय हैं। वाशबेसिन भी इस तरह से लगेगा जिससे कि फर्श पर पानी नहीं फैले। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले सभी जोन को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अग्नि की ताकत

एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की प्रतिरोधक क्षमता के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। जिस 'मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल', यानी एमआईआरवी तकनीक से यह लैस है, उसमें मुख्य मिसाइल कई वॉरहेड्स दागती है। नतीजतन, दुश्मन की वायु सुरक्षा प्रणाली को चकमा देना आसान हो जाता है। भारत के अलावा अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास ही यह तकनीक है। हालांकि, परीक्षण की गई मिसाइल की मारक-क्षमता नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि साल 2024 में 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत इसी तकनीक से लैस अग्नि 5 का सफल परीक्षण हो चुका है और उसकी रेंज करीब 5,000 किलोमीटर थी, इसलिए इस बार इससे अधिक ही होगी। इसे अग्नि 6 की पूर्वपीठिका भी कहा जा रहा है, जिसकी पुष्टि कम-से-कम दो तथ्य कर रहे हैं। पहला, परीक्षण की गई मिसाइल परमाणु-सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक थी, जिसकी मारक क्षमता अमूमन 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है। दूसरा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष समीर वी कामत ने अभी-अभी कहा है कि संगठन अग्नि 6 मिसाइल के निर्माण के लिए तैयार है, बस सरकार से हरी झंडी मिलने की देर है।

ताजा परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक का अप्रतिम उदाहरण है। नई दिल्ली के पास निस्संदेह ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, आकाश जैसी स्वदेशी मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन इनमें ध्वजवाहक अग्नि ही है। गुजरे साढ़े तीन दशकों में इसने 700 किलोमीटर से लेकर 5,000 किलोमीटर तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। आज भारत के सुरक्षा बेड़े में इसकी पांचवीं पीढ़ी की मिसाइलें हैं, जो परमाणु हथियार तक ले जा सकती हैं। इस बीच ऐसी महारत भी हासिल की गई है कि ये मिसाइलें सड़क या रेल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च की जा सकती हैं। अभी जो परीक्षण हुआ है, उसका लक्ष्य विशेषकर पश्चिमी मोर्चे, उत्तरी सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करना है, जो सामरिक ताकत का नया केंद्र बनता जा रहा है। संभवतः इन्हीं वजहों से पाकिस्तान की तरफ से चिंता जताई गई है कि भारत दुनिया के किसी भी देश को निशाना बनाने की राह पर निकल चुका है। हालांकि, विश्व बिरादरी जानती है कि भारत के रक्षा कार्यक्रम आत्म-सुरक्षा के इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि 'शत्रु को आक्रमण से रोकने के लिए न्यूनतम संख्या में हथियार रखे जाएं'।

साधारण बम को 'गाइडेड' बनाने में मिली सफलता के बाद एमआईआरवी से लैस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमता का उद्घोष है।

अग्नि की इस सफलता का प्रभाव भारत के रक्षा उद्योग पर भी पड़ेगा। देश का रक्षा-निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो चुका है। भारत अब दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है, जिनमें मिसाइल, आर्टिलरी गन, रडार, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उन्नत साजो-सामान भी शामिल हैं। दूसरे देश भारतीय सुरक्षा प्रणाली पर लगातार भरोसा जताने लगे हैं और घरेलू उत्पादन में भी अनवरत वृद्धि हो रही है। साल 2029 तक रक्षा-निर्यात 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पाना कठिन नहीं लगता। खासकर, दो दिन पहले डीआरडीओ द्वारा किया गया 'टीएआरए' का सफल परीक्षण, जिसमें साधारण बम को भी लक्षित हमले के लिहाज से 'गाइडेड बम' बनाया जा सकता है, और अब एमआईआरवी की सफलता यह भरोसा जगाती ही है कि भारत समय से पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 11 मई, 1951

पुनः नेपाल

नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा और गृह मंत्री श्री कोइराला अपने साथी मंत्रियों के साथ दिल्ली आये हैं। नेपाल शासन की गाड़ी दलदल में फंस गयी है और उसे बाहर निकालने के काम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू की सहायता प्राप्त करने के लिए नेपाली मंत्रियों ने भारत की यात्रा की है। श्री नेहरू ने ही नेपाल की गुत्थी को सुलझाने में पहले भी मदद दी थी। यह उनकी विवेक-युक्त सलाह का परिणाम था कि नेपाली कांग्रेस ने विद्रोह समाप्त करके राणाओं के साथ शासन की जिम्मेदारी का बोझ उठाना स्वीकार किया था। श्री नेहरू ने नेपाल की समस्या का यह हल निकाला था कि नेपाल का भावी संविधान बालिग मताधिकार पर चुनी हुई संविधान सभा तैयार करे, जिसका निर्माण सन् 1952 के अन्त तक हो जाना चाहिए। अन्तरिम काल में नेपाल का शासन चलाने के लिए एक ऐसे मंत्रिमण्डल का निर्माण सुझाया गया, जिसमें राणाओं और नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधियों का अनुपात आधा-आधा हो। इस मंत्रिमण्डल को संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त पर काम करना था और नेपाल के इस प्रयोग की सफलता के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। इस हल को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। उसके अनुसार दो विरोधी तत्वों को एक गाड़ी में जोत दिया गया था, किन्तु आशा यह की गयी थी कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ दोनों के आपसी विरोध और कटुता कम होते जायेंगे और वे नेपाल में वास्तविक लोकतंत्र का विकास करने के लिए मिल-जुलकर काम कर सकेंगे।

यह आशा पूरी नहीं हुई। राणा पक्ष के मंत्रियों और नेपाली कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों की शुरू से ही पटरी नहीं बैठ पायी। उनमें प्रारंभ से ही रस्साकशी शुरू हो गयी। सबसे पहले इस बात पर झगड़ा हुआ कि मंत्रिमण्डल की बैठक में कौन मंत्री किस स्थान पर बैठे। इस विषय में भी विवाद हुआ कि मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाये, राजा के हस्ताक्षरों की पुष्टि कौन करे और सरकारी आदेशों पर राजा की मुहर (लाल निशान) या प्रधानमन्त्री की मुहर (खड्ग निशाना) का उपयोग किया जाये। ये साधारण बातें थीं। किन्तु काठमाण्डू में गोरखा दल ने जो विद्रोह किया, उसने दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया।

होर्मुज मार्ग पर ईरानी नाके के मायने

होर्मुज जलमार्ग पर 'जहाज सूचना घोषणा' की नई ईरानी व्यवस्था जहाज कंपनियों के खर्च बढ़ा देगी। अगर ऐसा हुआ, तो माल भाड़ भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी।

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

ईरान पर अमेरिकी हमले और जवाबी कार्रवाई के कुछ ही समय बाद तेहरान ने कह दिया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अब लग रहा है कि ऐसा ही है। एक तरफ अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर सरगर्मी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने बाकायदा युद्ध खत्म होने का एलान कर दिया है, ताकि डोनल्ड ट्रंप को इस मसले पर कांग्रेस (संसद) की मंजूरी के लिए न जाना पड़े। दूसरी तरफ, ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर 'चेक नाका' भी लगा दिया है।

यहां चेक नाका का इस्तेमाल सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल किया इसलिए, ताकि बात साफ समझी जा सके। मामला कुछ-कुछ वैसा ही हो गया है, जैसा आपने अक्सर हाइवे किनारे या जंगल के रास्तों पर देखा होगा। ट्रकों को रोककर सरकारी कारकुन गाड़ी और ड्राइवर के कागजों के अलावा उनमें लदे माल की भी जांच-पड़ताल करते हुए मिलते हैं। कभी-कभी इस चक्कर में रास्ते जाम हो जाते हैं।

अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक होर्मुज भी कुछ इसी अंदाज में चलेगा। कम से कम ईरान ऐसा ही चाहता है। होर्मुज का महत्व तो अब सबको पता है। दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए तो इस मार्ग को जीवनरेखा भी कहा जा सकता है, क्योंकि देश की जरूरत का आधे से ज्यादा कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आता रहा है। अब ईरान का कहना है, इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को पहले से इजाजत लेनी होगी और उसके लिए उनको एक प्रश्नावली के जवाब देने पड़ेंगे। इस प्रश्नावली में पूरे चालीस सवाल हैं, जिनमें जहाज का नाम, मालिकाना अधिकार, पहचान संख्या, मूल देश, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, जो माल लदा है, वह क्या है, उसका मालिक कौन है, जैसे तमाम सवाल शामिल हैं। यही नहीं, जहाज पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का ब्योरा भी देना होगा।

ईरान की इस नई 'वेसल इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन' या जहाज सूचना घोषणा की व्यवस्था करने का काम 'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी' के जरिये होगा। मतलब साफ है। ईरान अब फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमार्ग के रास्ते ओमान की खाड़ी व अरब सागर तक के रास्ते एवं उससे गुजरने वाले जहाजों के आवागमन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वह एक तरह से बाकी दुनिया को याद दिला रहा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था सिर्फ कारखानों, बाजारों, उपभोक्ताओं, बैंकों, टेक्नोलॉजी और एआई जैसी चीजों से ही नहीं चल सकती, उसे कुछ संकरे समुद्री रास्तों से गुजरने की इजाजत भी चाहिए होती है।

जाहिर है, पहला झटका तो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों और उनके मालिकों को ही झेलना है। इसीलिए दुनिया की बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनियों ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। ये कंपनियां पहले ही कह चुकी हैं कि इस युद्ध की वजह से उनके ईंधन खर्च और कामकाज की लागत में भारी बढ़ोतरी हो गई है। बहरहाल, ईरान के इस कदम को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो यह कि वह इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर निगरानी रखना चाहता है और संभवतः उनसे टोल भी वसूलना चाहता है। इसके बाद जहाज पर लदे सामान का ब्योरा मांगने का अर्थ यह हो सकता है कि अब वह यहां दोस्त-दुश्मन का हिसाब भी करना चाहता है, यानी कोई ऐसा देश, जिसे ईरान मित्र नहीं मानता, इस मार्ग से अपना सामान आसानी से या मुफ्त में न ले जा सके।

दोनों ही स्थितियों में भारत इस मसले से दूर नहीं रह सकता। इसका असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। हो सकता है, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें या दाम में उछाल कुछ देर से नजर आए, मगर रसोई गैस की आपूर्ति व गैस संचालित उद्योगों और खाद कारखानों के लिए मुश्किलें उतनी दूर नहीं हैं। रसोई गैस की परेशानी तो सबके सामने है। प्लास्टिक की पैकिंग में आने वाली तमाम चीजें बाजार में या तो कम आ रही हैं या उनके दाम बढ़ रहे हैं। संकट जारी रहा, तो आगे और लक्षण सामने आएंगे। सवाल है, इससे महंगाई कितनी बढ़ सकती है? इस सवाल का सीधा उत्तर देना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का बढ़ना इस पर निर्भर है कि यह संकट कितने दिन और चलेगा? सरकार टैक्स घटाएगी या नहीं? तेल कंपनियां कितना बोझ खुद उठाएंगी और कितना वे दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी? रुपये का दाम डॉलर के सामने कितना और गिरेगा?

अनेक एजेंसियां अनुमान लगा रही हैं। एक गणित यह है कि एक बैरल कच्चे तेल के दाम में हर दस डॉलर की बढ़त से भारत में महंगाई का आंकड़ा 0.55 से 0.6% तक बढ़ सकता है। लड़ाई छिड़ने के पहले ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल की कीमत तय करने वाला अहम वैश्विक बेंचमार्क) 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था। वहां से यह 100 डॉलर के पार बना रहता है, तो 30 डॉलर की बढ़ोतरी है, यानी भारत की महंगाई दर में डेढ़ से पौने दो फीसदी तक वृद्धि देखी जा सकती है।

तेल व गैस का महंगाई से सीधा रिश्ता है और महंगाई के साथ-साथ यह डॉलर के मुकाबले रुपये को कमजोर करने में भी भूमिका निभाता है। रुपये की कीमत गिरने का मतलब है, आयात और महंगा होना। इसमें तेल और गैस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल और खाने के तेल जैसी चीजें भी शामिल हैं। होर्मुज में नई ईरानी व्यवस्था जहाज कंपनियों के खर्च बढ़ाएगी और इसमें वक्त भी बर्बाद हो सकता है। ऐसा होने पर माल भाड़ा और बीमा भी बढ़ेगा। यह लागत भी आखिरकार कारोबारियों और खरीदारों तक पहुंचेगी, यानी आपूर्ति श्रृंखला की महंगाई अब सिर्फ ट्रक व रेल भाड़े से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय भाड़े से शुरू हो जाएगी।

बड़ी कंपनियां ऐसी स्थिति में या तो दाम बढ़ाती हैं या पैकिंग छोटी कर देती हैं, पर छोटे कारोबारी मुश्किल में आ जाते हैं। सिलेंडर महंगा होते ही ढाबे वाला दाम नहीं बढ़ा सकता। वह या तो कुछ चीजें बनाना बंद कर देता है या फिर अपने साथ लगे कुछ लोगों की छुट्टी कर देता है। जाहिर है, गरीबी के जाल में फंसा इंसान सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ता है।

उम्मीद की किरण इस बात में है कि ईरान भारत को अपना दुश्मन नहीं मानता। हो सकता है, वह भारतीय जहाजों और भारत जाने वाली सामग्री के रास्ते में ज्यादा अड़चनें न खड़ी करे। ऐसा हुआ, तो संकट जल्दी खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका असर भी कम होगा, लेकिन अगर यह संकट कई महीनों तक चलता रहा, तो शायद महंगाई 2026 में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्या अनियोजित विकास की भेंट चढ़ते रहेंगे जंगल

यहां स्कैन करें

सुरेश भाई | पर्यावरण कार्यकर्ता

उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के बाली घाट से कोटमन्या तक मौजूदा मोटर मार्ग की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है। सघन वनों के बीच से गुजर रही इस सड़क के दोनों ओर हिमालय का अद्भुत नजारा है। यहीं पर महात्मा गांधी की शिष्या सरला बहन का आश्रम है, जो 'हिम दर्शन कुटीर' के नाम से जाना जाता है। इस वन में बड़ी संख्या में बांज, बुरांश, काफल, उतीस जैसी दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष मौजूद हैं। फिलहाल इस सड़क-मार्ग की चौड़ाई करीब छह मीटर है, जिसे 12 से 18 मीटर किए जाने की तैयारी है। जाहिर है, इससे दुर्लभ वन प्रजाति के अनेक पेड़ काटने पड़ेंगे, वे कट जाएंगे।

यह हाल सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है। 'द स्टेट ऑफ इंडियाज एन्वायरनमेंट 2026' रिपोर्ट बताती है कि साल 2023-24 में देश भर में 29,000 हेक्टेयर वन-भूमि का इस्तेमाल गैर-वन गतिविधियों में किया गया, जो 2022-23 की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक था। साल 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच पूरे भारत में 1,73,397 हेक्टेयर जंगल सड़कों, बिजली लाइनों, खनन, सिंचाई, रेलवे व पनबिजली परियोजनाओं की भेंट चढ़ गए। इसी तरह, एनर्जी कंसल्टेंसी देने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी यूटिलिटी बिडर मानती है कि 1990 से 2020 तक भारत में जंगल कटने की घटनाओं में जबर्दस्त वृद्धि हुई है और 2015 से 2020 के बीच इसमें तेज उछाल दर्ज की गई। उसके आंकड़ों की मानें, तो बीते तीन दशक में देश में 6.68 लाख हेक्टेयर वन भूमि खाली कराए गए हैं। हालांकि, देश की आधिकारिक रिपोर्टें कुल हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी के संकेत देती हैं, पर स्वतंत्र अध्ययन इसे सही नहीं मानते और प्राकृतिक वन क्षेत्र में भारी कमी की बात कह रहे हैं।

मैदानी क्षेत्र के लोगों का आना-जाना बढ़ गया है, जिनकी सुविधा के लिए पहाड़ों में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ अधिक होने लगी है।

वनों की कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान जगजाहिर हैं। हिम दर्शन कुटीर के आसपास के इलाकों की ही बात करें, तो यहां दुर्लभ वन्य जीव प्रजाति कस्तूरी मृग का अनुसंधान केंद्र है, जिसका अस्तित्व यहां की जैव-विविधता पर टिका हुआ है। यहां से बरड़ और पुंगर नदियां निकलती हैं। वन संपदा से घिरी इस पर्वतमाला के दोनों ओर सैकड़ों गांव बसे हुए हैं, जहां के लोगों के जल का स्रोत ये नदियां हैं। उनकी खेती-बाड़ी भी इन्हीं से चलती है। यहां शीतकाल में भारी बर्फ भी पड़ती है, जिसे देखने के लिए मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। यह उत्तराखंड का एक मनमोहक पर्यटन केंद्र है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानी इस प्राकृतिक छटा का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। बावजूद इसके यहां पर करीब 13 हजार पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं, जिनको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर काटने की तैयारी चल रही है। गौरतलब है, सन् 1980 में भी यहां जब पेड़ों के कटाने की आशंका बढ़ी, तब सरला बहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इसका सख्त विरोध किया था, जिसके बाद यहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई की योजना रोक दी गई थी। क्या इस बार सरला बहन का बचाया यह वन अनियोजित विकास की भेंट चढ़ जाएगा?

विडंबना यह है कि अदालतों में भी विकास के नाम पर सरकार का पक्ष अधिक सुना जा रहा है, जबकि गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी क्षेत्र के लोगों का हिमालय की तरफ पहले से अधिक आना-जाना बढ़ गया है। उनकी सुविधा के लिए पर्वतों की शांत वादियों में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ अधिक होने लगी है। क्षणिक सुविधाओं के लिए इंसान बड़ी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ाता दिख रहा है। यही कारण है कि हिमालयी राज्यों में जहां जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बची-खुची दुर्लभ वन प्रजातियों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं आस-पास के गांवों के जल-स्रोतों और यहां से निकलने वाली नदियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस गंभीर विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन लापरवाही का अंतहीन सिलसिला जारी है।

कहने की जरूरत नहीं, विकास ऐसा होना चाहिए, जो आफत खड़ी न करे। हिमालय के वनों को उजाड़ने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि जलवायु संकट से बचने के लिए प्राकृतिक वनों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपराध एक बीमारी

अमेरिका में एक पंद्रह साल का लड़का दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसे अदालत में पेश किया गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, 'तुमने क्या सचमुच चुराया था ब्रेड-पनीर का पैकेट?'

लड़के ने नजरें नीचे करके जवाब दिया- 'हां, मुझे जरूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। घर में सिर्फ मां हैं, जो बीमार और बेरोजगार हैं, ब्रेड और पनीर भी उन्हीं के लिए चुराई थी।' जज ने पूछा- 'तुम कुछ काम नहीं करते?' लड़के ने कहा- 'करता था एक कार वाश में। मां की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की, तो मुझे निकाल दिया गया। आज सुबह से घर से निकला था, पचास लोगों के पास गया, थोड़े से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया; बिल्कुल आखिर में यह कदम उठाया।'

जिरह खत्म हुई, जज ने फैसला सुनाना शुरू किया, जो अद्भुत था- 'ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस अदालत में मौजूद हर शख्स-मुझ सहित- सब मुजरिम हैं, इसलिए यहां मौजूद हरेक शख्स पर दस-दस डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। दस डॉलर दिए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा।'

यह कहकर जज ने दस डॉलर अपनी जेब से बाहर निकालकर रख दिए और फिर आगे लिखना शुरू किया- 'इसके अलावा मैं उस दुकान पर एक हजार डॉलर का जुर्माना लगाता हूं कि उसने एक भूखे-प्यासे बच्चे से अमानवीय सुलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर चौबीस घंटे में जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो यह अदालत दुकान को सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूरी राशि आरोपी किशोर को देते हुए अदालत उससे माफी तलब करती है।'

फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे, लड़के की भी हिचकियां बंध गई थीं। जज साहब अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गए थे। जो भी ज्ञानी होंगे, उनका यही रुख होगा। चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाए, तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हमारा समाज और अदालतें इस तरह के निर्णय के लिए तैयार हैं?

यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाए, तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हमारा समाज और अदालतें ऐसे निर्णय के लिए तैयार हैं?

ओशो हमेशा हर तरह के दंड के खिलाफ रहे हैं। उनके मुताबिक, सजा से अपराध को रोका नहीं जा सकता। सजा से कोई इंसान बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा भ्रष्ट हुआ है। आदमी को दंड से नहीं, प्रेम से ठीक किया जा सकता है। जुर्म की ओर देखने का बिल्कुल नया विज्ञान, नया रवैया होना जरूरी है। अपराध एक बीमारी है, क्या किसी को कैंसर हुआ, तो आप उसे जेल में डाल देंगे और उससे कैंसर ठीक होगा?

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

प्रेस की स्वतंत्रता पर ही हर तरह की आजादी निर्भर करती है। इसके बिना मानवाधिकारों की रक्षा, विकास और शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करें और ऐसी दुनिया बनाएं, जहां सच बोलने वाले सुरक्षित रहें।

अनुलोम-विलोम
परीक्षा में सख्ती

बच्चों के जी का जंजाल बनती परीक्षाएं

भारत में हर साल 37 लाख से ज्यादा नौजवान जेईई और नीट की परीक्षाएं देते हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये परीक्षाएं अब योग्यता की कसौटी नहीं, जी का जंजाल बन गई हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चों पर अब सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं होता, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दबाव भी उन्हें परेशान करता है। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले ही बच्चे टूट रहे हैं। यहां कदाचार रोकने या सख्ती के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह बच्चों के लिए गंभीर मानसिक उत्पीड़न है। लंबी आस्तीन मना, जूते मना, घड़ी मना, रबर बैंड मना। लड़कियों के झुमके, बालों की क्लिप, नाक की लौंग, और तो और, कई बार उनके अंतर्वस्त्र तक चेक किए जा रहे हैं। तीन घंटे के पेपर से पहले दो घंटे गेट पर बच्चों को अपराधियों की तरह लाइन में खड़ा करके जांचा जा रहा है।

एनटीए कहता है कि कदाचार रोकने के लिए यह सब किया जाता है, किंतु सोचिए कि एक 17 साल के बच्चे या बच्ची के अंतर्वस्त्र उतरवाना चीटिंग रोकना है या उसकी गरिमा की हत्या? साल 2024 में नीट का पेपर लीक बिहार-गुजरात से हुआ। बड़े माफिया पकड़े गए, पर सजा किसे मिली? गेट पर खड़ी उस बच्ची को, जिसके अंतर्वस्त्र में हुक था या उसे, जिसकी पैंट में मेटल बटन था, उसे सजा मिल रही है। नीट 2024 में ही पेपर लीक के आरोप उछले, 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले। ग्रेस मार्क्स का घोटाला हुआ। एनटीए ने 1,563 बच्चों को 20 से 70 नंबर का 'टाइम लॉस' का ग्रेस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर से परीक्षा हुई। सोचिए, उस बच्चे का क्या, जो बॉर्डरलाइन स्कोर पर था? पहले ग्रेस से चयन हुआ, फिर री-टेस्ट में बाहर। इस तरह सिस्टम ने एक महीने में उसे दो-दो बार मारा। पेपर लीक एनटीए की अपनी कमजोरियों और गलतियों के कारण हुआ था, लेकिन उसकी सजा परीक्षार्थियों को आज भी मिल रही है।

साफ है, इस पूरी व्यवस्था में बदलाव की गंभीर आवश्यकता है। साल में तीन बार नीट और चार बार जेईई की परीक्षा हो सकती है, जिनका बेस्ट स्कोर गिना जाना चाहिए। इसी तरह, जांच के नाम पर बच्चों का उत्पीड़न और समय की बर्बादी को भी रोकना जरूरी है। बच्चों से जब परीक्षा फीस जमकर वसूली जा रही है, तो परीक्षा-केंद्रों पर कदाचार रोकने की आधुनिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा सकती हैं? कहने का अर्थ यही है कि आज जिस तरह से ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, वह 'एंट्री एग्जाम' नहीं, एंट्री गेट पर ही 'एग्जीक्यूशन' है।

अंजनी सक्सेना, टिप्पणीकार

कदाचार रोकने के हर उपाय अनिवार्य

कदाचार-मुक्त परीक्षा के लिए अगर सख्ती बरतनी पड़ रही है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि नीट परीक्षा में जिस तरह से परीक्षार्थियों की सघन तलाशी होती है, वह गलत है। ऐसे लोगों से सीधा सवाल यही है कि क्या पूर्व में परीक्षा के दौरान 'मुन्ना भाई' नहीं पकड़े गए हैं? याद कीजिए, पहले की परीक्षाओं में ब्लूटूथ और मोबाइल के सहारे किस तरह से परीक्षा में चोरी की जाती थी। कदाचार करवाने वालों का एक तंत्र बना हुआ था, जो लाखों रुपये लेकर परीक्षार्थियों को परीक्षा पास करवाने की गारंटी लिया करता। जब ऐसे फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने लगे, तब जाकर नीट परीक्षा में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।

सवाल यह भी है कि जब आप कोई चोरी नहीं कर रहे या आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, तो फिर जांच-पड़ताल से घबराना कैसा? एक-दो घंटे यदि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ भी रहा है, तो यह आपके ही हित में है। मान लीजिए, ऐसी सख्ती न हो और कदाचार के मामले सामने आ जाएं, तो यकीनन उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक की गलती की सजा आखिर सभी परीक्षार्थियों को क्यों मिलनी चाहिए? इसलिए, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही उस 'एक' को पकड़ने की व्यवस्था की जाती है, ताकि सही परीक्षार्थियों को नुकसान न उठाना पड़े। इस तरह परीक्षा की शुचिता पर किसी तरह के दाग भी नहीं लग पा रहे।

नीट ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कई तरह की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही कड़ी जांच-पड़ताल व तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। डमी उम्मीदवार मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी और तीन साल तक के लिए उसे प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 (पूर्व में 144) लागू की जाती है, ताकि किसी भी बाहरी दखल को रोका जा सके। जब प्रशासनिक तौर पर इतनी तैयारी की जाती है, तो किसी परीक्षार्थी से यह अपेक्षा रखना कि वह इसमें अपना सहयोग देगा, क्या गलत है? कदापि नहीं।

मेरा तो यह भी मानना है कि कदाचार-मुक्त परीक्षा के लिए जितने भी उपाय अपनाए जा सकते हैं, वे सभी अपनाए जाने चाहिए। परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसमें किसी भी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हां, जो फर्जी परीक्षार्थी हैं या जिनके मन में चोर है, वे जरूर इस पर हल्ला मचाएंगे। किंतु ऐसे तत्वों को नजरंदाज करना ही बेहतर है।

कुणाल वत्स, टिप्पणीकार

भारतीय नौकरशाही का चमकदार इतिहास

भारत में कुछ ऐसे नौकरशाह हुए हैं, जिनकी यादों को संजोना जरूरी है। एक ऐसे ही नौकरशाह थे योजना आयोग के पहले सचिव त्रिभुवन प्रसाद सिंह। उनकी 114वीं जयंती पर एक मशहूर नर्सरी ने गुलाब की एक नई किस्म 'त्रिभुवन' तैयार कर उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी है। देश में बहुत पहले ही आर्थिक सुधारों की पैरवी करने वाले ऐसे आदर्श अधिकारी के योगदान को समझने के लिए उनके पुत्र 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रेसीडेंट एन के सिंह से हिन्दुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जैड़ा ने बातचीत की है। पेश हैं मुख्य अंश...

■ आपके पिता त्रिभुवन प्रसाद सिंह के नाम पर सम्मान स्वरूप गुलाब की किस्म त्रिभुवन विकसित की गई है, आप इसे कैसे देखते हैं?

उन्हें सम्मानित करना केवल एक प्रशासक और नीति निर्माता को सम्मानित करने से कहीं अधिक है। यह उस व्यक्ति को याद करने का भी प्रतीक है, जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने तक पहुंचे। इसलिए त्रिभुवन केवल गुलाब की एक नई किस्म नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट लोक सेवक और एक गुलाब प्रेमी की जीवंत स्मृति है। उन्होंने पटना में हमारे परिवार के शेखपुरा स्थित आवास पर दो हजार से अधिक गुलाब के पौधों का अद्भुत बाग बनाया था, जिसमें प्रत्येक पर उसकी वंशावली और विशेषताओं को सावधानीपूर्वक लेबल किया था। यह किसी शौकिया व्यक्ति का उत्साह नहीं था, यह उनके धैर्य, अध्ययन और निरंतर देखभाल को दर्शाता था। पिता स्वयं आगंतुकों को बगीचे में ले जाते थे और उन्हें विभिन्न किस्मों के आनुवांशिक महत्व समझाते थे।

■ आप 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद केंद्र में व्यय व राजस्व सचिव थे। आपके पिता त्रिभुवन प्रसाद सिंह भी इन पदों पर रहे थे। इन दोनों समय को आप कैसे देखते हैं?

देश की परिस्थितियां बदल चुकी थीं। इसका वर्णन मैं एक दूसरी किताब *इंडियाज मिस्ड अपारच्युनिटी* में करने जा रहा हूं कि हमने आर्थिक सुधारों के लिए 1991 तक का इंतजार क्यों किया? जब 1978 में चीन में भी आर्थिक सुधार शुरू हो चुके थे, तब हम इसमें पीछे क्यों रहे? हालांकि, उस दौर में सत्ता में वामपंथी विचारधारा का बोलबाला था और उस विचारधारा के इतर भी सरकार को सुझाव देना अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उस समय भी नौकरशाह आर्थिक सुधारों के पक्षधर थे और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे, लेकिन सरकार को यह स्वीकार्य नहीं था। इस सबके बावजूद मेरे पिता तत्कालीन (1968-69) वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को करों को तर्कसंगत बनाने के लिए सहमत कर चुके थे। दरअसल, उस दौर में आय पर 90 फीसदी तक कर लगता था। उनके प्रयास से कर सुधार की सोच बलवती हुई थी। व्यय सचिव के कार्यकाल के रूप में भी उनकी एक उपलब्धि रही। उन्होंने यह सोच विकसित की कि वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति होनी चाहिए। तब विभागों में वित्तीय सलाहकार का पद नहीं होता था। बाद में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति हुई।

इसी प्रकार कृषि सचिव के रूप में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब में पिताजी का जिक्र किया है कि किस प्रकार वह निडर होकर फैसले लेते थे। कृषि मंत्रालय के अधिकारी चाहते थे कि कुरियन एनडीडीबी और डेयरी कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद से हटें, लेकिन बतौर कृषि सचिव मेरे पिता ने कहा कि जब मंत्रालय ने उन्हें नियुक्त किया है, तब उन्हें हटाने की क्यों सोच रहे हैं और उन्होंने इस विवाद को वहीं खत्म कर दिया था।

■ आर्थिक मुद्दों पर मोरारजी देसाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में भी मतभेद थे?

दरअसल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर टकराव था। तब मेरे पिता राजस्व सचिव थे। वह भी इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने निडर होकर अपनी राय सरकार को दी थी। मोरारजी देसाई भी उनसे सहमत थे। उन्होंने भी इसका विरोध किया, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्री पद छीन लिया। बाद में मोरारजी देसाई ने उप-प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अलावा मोरारजी देसाई को हटाने के और भी कारण थे, वह राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे थे। जब वह हटा दिए गए, तब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

■ आपके पिताजी जब सचिव थे, तब आप भी इस सेवा में आ चुके होंगे, तो किस प्रकार वह आपसे अनुभव साझा करते थे? क्या बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विचार रखने की कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ी थी?

बिल्कुल चुकाई। इंदिरा गांधी ने एक बार उनसे कहा कि आप मोरारजी के करीब थे, अब तो उनके बिना आपका मन नहीं लगता होगा? इस पर पिता ने कहा कि वह नौकरशाह हैं, उनका काम अपनी ड्यूटी करना है। खैर, बाद में उन्हें राजस्व सचिव से हटाकर कृषि सचिव बना दिया गया। दरअसल, नौकरशाहों को विपरीत विचार रखने पर दंडित करने का सिलसिला कांग्रेस शासन में ही शुरू हो चुका था।

गुलाब के फूल की नई किस्म – त्रिभुवन

> हमने टीपी सिंह के नाम पर गुलाब फूल की एक किस्म का नाम रखने का फैसला किया, ताकि आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में देश की नीतियों के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा सके। ब्लैक प्रिंस और कॉरिडा को मिलाकर यह नई किस्म बनाई गई है, क्योंकि उन्हें गहरे लाल रंग के गुलाबों से बहुत लगाव था। अब त्रिभुवन हमारे बगीचे की अनमोल धरोहर है।
>
> –सर्वेश श्रीराम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केएसजी सन, बेंगलुरु

■ आपके पिता का जन्म बिहार के बांका जिले के लहौरिया गांव में एक शिक्षक के घर 9 मई 1913 को हुआ था। अंग्रेजी शासन के बावजूद वह इंडियन सिविल सर्विस में सफल हुए। उनके इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं?

हां, उनका संघर्ष सिर्फ मेरे लिए प्रेरणादायक नहीं, बल्कि समूचे बिहार के नौजवानों के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी उस क्षेत्र में घरों में चर्चा होती है कि कैसे उस जमाने में हेड मास्टर के बेटे ने आईसीएस में सफलता हासिल की थी। दरअसल, पिताजी अर्थशास्त्र के गहरे जानकार थे। शुरुआती अध्ययन भागलपुर और पटना में करने के बाद नाना जी की आर्थिक मदद से वह विदेश पढ़ने गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और फिर वापस लौटकर आईसीएस अधिकारी बने। उन्हें बिहार कैडर मिला और बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए केंद्र की नौकरशाही में गए। पटना एवं तिरहुत संभागों के कमिश्नर रहे। कोशी प्रोजेक्ट भी देखा। फिर केंद्र में योजना आयोग में आए।

■ आपने योजना आयोग का जिक्र किया। बतौर सचिव योजना आयोग को आकार देने में उनकी भूमिका तब क्या रही थी?

दरअसल, नेहरू कैबिनेट ने शुरुआती फैसलों में ही योजना आयोग बनाने का निर्णय लिया था। नेहरू केंद्रीय आर्थिक मॉडल के पक्षधर थे जैसा उस समय सोवियत संघ में हुआ करता था। निजी क्षेत्र की जिसमें कोई भूमिका नहीं थी। वह निजी संपत्ति को भी खत्म करना चाहते थे, जिस समय मेरे पिता योजना आयोग में अतिरिक्त सचिव बनकर आए, तब तक आयोग आकार ले चुका था, लेकिन पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वह आयोग में थे। बाद में जब वह सचिव प्रोन्नत हुए, तब कैबिनेट सचिव ने कहा कि आपको योजना आयोग का ही सचिव बना देते हैं। उससे पहले तक कैबिनेट सचिव ही योजना आयोग के पदेन सचिव होते थे। इस प्रकार वह योजना आयोग के पहले सचिव बने। योजना आयोग तब वित्त मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर था। योजना आयोग के एक मशहूर सदस्य थे त्रिलोक सिंह, जिनके नाम से योजना आयोग ज्यादा मशहूर था। लोग कहते थे कि दिल्ली में तीन सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा और त्रिलोक सभा यानी योजना आयोग।

■ उस दौर के राजनीतिक हालात में नौकरशाहों की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं?

पिताजी कहा करते थे कि नौकरशाह को राजनीतिक नेतृत्व को ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए, जो उचित हो। ऐसी सलाह देनी चाहिए, जैसी नेतृत्व अपेक्षा करता हो। फिर जो भी निर्णय हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उनके मामले में ऐसा ही हुआ था। उन्हें राजस्व सचिव पद से हटाया गया था। हालांकि, बाद में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और तब तक पिताजी का निधन हो चुका था। तब मेरी मां उन्हें बधाई देने गईं। मोरारजी देसाई ने उनसे कहा था कि वह टीपी को 'मिस' कर रहे हैं। आज जो जगह उन्होंने शंकर (अपने सचिव) को दी है, वह टीपी की थी। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से टीपी को दिक्कत हुई। खैर, इन सब परिस्थितियों के बावजूद नौकरशाह तब भी निडर होकर अपनी राय रखते थे। हालांकि, फैसला राजनीतिक नेतृत्व का ही अंतिम होता था।

गुलाब के अपने बाग में त्रिभुवन प्रसाद सिंह।

■ आपको बिहार में उनके कार्यकाल की क्या कोई घटना अभी भी याद है?

मुझे ही नहीं, बिहार के लोगों को भी याद है। पिताजी सबसे पहले दानापुर के एसडीओ बने थे। बाद में मैं और मेरी बहन कृष्णा भी वहां एसडीओ रहीं। उस दौरान एक अंग्रेज सिपाही ने एक नाई को मार दिया था। इस पर पिता ने अंग्रेज सिपाही पर कानूनी कार्रवाई की। तब ऐसा नहीं होता था। पिताजी का मानना था, कानून सबके लिए बराबर है। दानापुर में आज भी इस घटना की चर्चा होती है। इस कारण पिताजी का तबादला हो गया था। उनकी इसी न्यायप्रियता के चलते वहां एक पार्क का नाम त्रिभुवन पार्क रखा गया है। एक त्रिभुवन लाइब्रेरी भी बनाई गई है।

■ उनकी क्या नसीहत आप हमेशा याद करते हैं?

वह कहते थे कि जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। निराशा व असफलता के मौके भी आएंगे, पर शौक, आपका जुनून नहीं छूटना चाहिए। पिता को बागवानी का शौक था। पटना में तत्कालीन राज्यपाल जाकिर हुसैन उनके घर गुलाब देखने आते थे। अब केएसजी सन ने उनके सम्मान में गुलाब की एक किस्म त्रिभुवन जारी की है। यह गहरे रंग का वैसा ही गुलाब है, जैसा पिता को पसंद था, जिसे वह लगाते थे।

जीने की राह

हर जगह काम आने वाले कुछ कौशल

घर हो या बाहर, हमारी सफलता केवल तकनीकी ज्ञान पर निर्भर नहीं करती। हमारा सुकून इस पर भी टिका है कि हम लोगों और हालात के साथ कैसे तालमेल बिठा पाते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही कौशल दिए गए हैं, जो एक बेहतर पेशेवर और सुलझा हुआ इंसान बनाने में हमारी मदद करते हैं –

लचीलापन

लचीलापन वह शक्ति है, जो हमें टूटने के बजाय झुककर वापस संभलने की क्षमता देती है।
क्या करें: अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उनसे भागें नहीं ■ जो हो गया उस पर पछताने के बजाय 'अगला कदम' क्या होगा, उस पर ध्यान दें ■ एक मजबूत सामाजिक और भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम बनाएं।

सहयोग

बड़े व महान काम दूसरों के सहयोग से किए जा सकते हैं। अपने अहंकार को पीछे छोड़कर सबको साथ लेकर काम करें। यह कौशल घर हो या बाहर, हर जगह आगे बढ़ाता है।
क्या करें: ■ दूसरों की खूबियां पहचानें और उनकी सराहना करें। ■ 'मेरी जीत' की बजाय 'हमारी जीत' की सोच से काम करें। ■ अपनी कमियों को स्वीकार करें और जहां जरूरत हो, वहां मदद मांगने में संकोच न करें।

समस्या सुलझाना

अक्सर हम समस्या के 'क्यों' और 'किसने किया' में उलझ जाते हैं, जबकि रचनात्मकता हमें 'कैसे ठीक होगा' की ओर ले जाती है। एक शांत दिमाग ही जटिल गुत्थियों को सुलझा सकता है।
क्या करें: ■ बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांट लें। ■ 'प्लान–बी' तैयार रखें ■ समस्या को चुनौती मानें, बाधा नहीं।

नेतृत्व

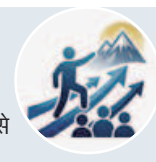

यह कोई पद नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक सच्चा लीडर वह है, जो दूसरों को लीडर बनने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व अपने आचरण से दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने की कला है। एक अच्छा लीडर जोखिम और जिम्मेदारी दोनों उठाने के तैयार रहता है।
क्या करें: ■ बोलने से ज्यादा दूसरों को समझें ■ सफलता का श्रेय दूसरों को भी दें ■ बिना स्वार्थ दूसरों की मदद के लिए रहें।

सकारात्मकता

सकारात्मकता यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा। यह विश्वास रखें कि जो भी होगा, आप उसे संभालने के काबिल हैं।
क्या करें: ■ शिकायत की जगह 'शुक्रिया' कहने की आदत बढ़ाएं। ■ पीठ पीछे लोगों की बुराई न करें। ■ प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताएं।

धैर्य और दृढ़ता

बांस का पेड़ सालों अपनी जड़ें जमीन में गहरी करता है और फिर अचानक ऊपर बढ़ता है। सफलता भी ऐसी ही है। चुनौती के समय सब्र रखें और पूरे विश्वास से आगे बढ़ें।
क्या करें: ■ अपनी जिम्मेदारी लें। ■ दूसरों से तुलना न करें ■ सिद्धांतों से समझौता न करें ■ कठिन समय में अपनों का साथ न छोड़ें।

एकदा

गुरु दक्षिणा

एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह चीज मांगी, जो बिलकुल व्यर्थ हो या जिसका जीवन में कोई उपयोग न हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया, तो मिट्टी बोल पड़ी, 'तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये वनस्पतियां, ये रूप, रस व गंध सब कहां से आते हैं?' शिष्य आगे बढ़ गया।

थोड़ी दूर पर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई, 'तुम मुझे बेकार क्यों मान रहे हो? तुम अपने भवन किससे बनाते हो? मंदिरों में किससे गढ़ कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं?' यह सुनकर शिष्य ने अपना हाथ खींच लिया। वह सोचने लगा कि आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है? सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है, जो मैं गुरुजी को दक्षिणा में दे सकूं? रास्ते में उसे एक संत मिले तो युवक ने उन्हें अपनी बात बताई।

संत मुस्कराए और युवक से कहा 'व्यर्थ चीजें वह नहीं होती हैं, जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि व्यर्थ की चीजें वह हैं, जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। व्यर्थ और तुच्छ वह है, जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। भीतर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है, जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं। यह सुनकर शिष्य सीधा गुरु जी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा, क्योंकि अब वह गुरु को दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष: मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृष: आत्मविश्वास भरपूर तो रहेगा, लेकिन धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ मिल सकता है।

मिथुन: पठन-पाठन में रुचि रहेगी। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

कर्क: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव तथा साज-सज्जा के काम पर खर्च बढ़ेंगे।

सिंह: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या: मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा।

तुला: मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से व्यस्तता बढ़ सकती है।

वृश्चिक: आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

धनु: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

मकर: वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कुंभ: मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। यात्रा पर जाने का योग है।

मीन: मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता भी बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

11 मई, सोमवार, **शक संवत्** : 21 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग:** 28 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम:** 23 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्:** प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि अपराह्न 03.25 बजे तक पश्चात दशमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 01.29 बजे तक पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन–रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। प्रात: 07.30 बजे से प्रात: 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 03.09 मिनट से। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मैं एक पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूं, कृपया बताएं कि वास्तु के अनुसार क्या करूं?
–अनिल कुमार, झारखंड

■ पंप लगाने के लिए प्लॉट उत्तर या पूर्व मुखी हो तो अच्छा है। बोरिंग प्लॉट के उत्तर या पूर्व दिशा में करवाएं। पेट्रोल डीजल का टैंक वायव्य कोण में अच्छा रहता है।

■ मालिक का ऑफिस दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा मैनेजर का ऑफिस दक्षिण दिशा में बनाया जा सकता है। टॉयलेट को उत्तर पश्चिम में बनाना चाहिए। साइन बोर्ड, पंप का नाम दक्षिण दिशा में लिखना अच्छा रहता है। कैश की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए, जो कि उत्तर की ओर खुलनी चाहिए।

वर्ग पहेली : 8325

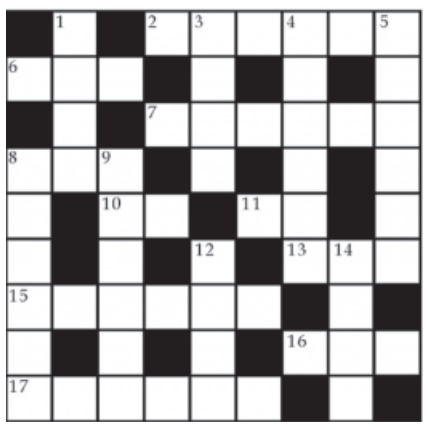

ऊपर से नीचे
1. अनुभवी; अभिज्ञ; ज्ञानी; परिचित (4)
3. जल का प्राणी; जलजंतु; पानी में रहने वाले जीव (4)
4. अशक्त करवाना; कमजोर कराना (2,4)
5. असुविधा होना; झंझट होना; दिक्कत होना; मुश्किल होना (4,2)
8. पालक से छल करने वाला; स्वामी से द्रोह करने वाला; कृतघ्न, निष्ठाहीन; विश्वासघाती (6)
9. कमल जैसे नेत्रों वाला; राजीव लोचन 6)
12. अनेक बार; फिर फिर (2,2)
14. फैलना; पैर फैलाकर सोना; विस्तृत होना (4)

बाएं से दाएं
2. दूसरे स्थान पर आए प्रतियोगी को मिलने वाला पदक; चांदी का तमगा (3,3)
6. कसकर बांधना; खिंचाव पैदा करना; फैलाना; किसी को लक्ष्य करके अस्त्र उठाना (3)
7. बचाना; लाभ कमाना (3,3)
8. जहन्नुम; दोजख; पापियों के लिए निर्धारित स्थल; बहुत गंदा स्थान (3)
10. राय; विचार; आशय; भाव; सम्मति (2)
11. लोकोपयोगी कार्य; वेतन ले कर किया जाने वाला काम; चाकरी; खिदमत; नौकरी (2)
13. मापना; पैमाइश करना; नाप लेना; थाह लेना (3)
15. छीनना; वंचित करना (3,3)
16. बात मनवाने के लिए किसी के पास या द्वार पर अड़ कर बैठना; पकड़ना; रखना; स्थापित करना (3)
17. चिंतन करना; विचार करना (3,3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8324

1 मा	■	2 का	या	3 प	ल	ट	4 हो	ना
था	■	र्य	■	ता	■	■	न	■
5 ख	ट	का	ना	■	6 फ	ला	हा	र
पा	■	ल	■	■	ट	■	र	■
ना	■	■	7 उ	ड़	ना	■	■	8 व
■	9 रा	■	ठा	■	■	10 ठ	■	र्ण
11 च	ह	क	ना	■	12 ब	ह	ला	ना
■	गी	■	■	13 पे	■	र	■	ती
14 सू	र	ज	अ	स्त	हो	ना	■	त

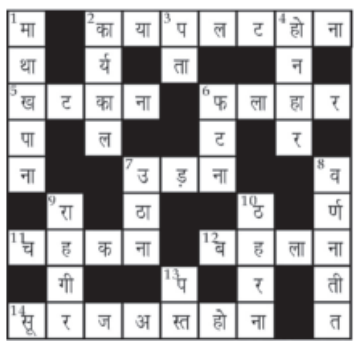

सुडोकू : 8307

* मध्यम

7	8		1					
9					6		5	
		1	9	4				
1							6	
		2		7		1		
	5							8
				1	3	6		
	4		6					5
					8		7	4

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8306

1	2	6	9	8	7	3	4	5
9	5	3	6	2	4	1	7	8
4	7	8	1	5	3	9	2	6
6	9	7	8	3	5	4	1	2
5	1	4	2	6	9	7	8	3
8	3	2	7	4	1	6	5	9
2	4	1	5	9	6	8	3	7
3	8	9	4	7	2	5	6	1
7	6	5	3	1	8	2	9	4

अमर उजाला

प्रवाह

78

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ सोमवार, 11 मई 2026

जब वातावरण में कार्बन बढ़ने लगे, तब समझ लीजिए पृथ्वी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। - डोना माल्ट्ज

तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनना प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। देखना होगा कि वह केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और कैसे सुशासन की स्थायी मिसाल कायम करते हैं।

बदलाव का चेहरा

तमिलनाडु की राजनीति में रविवार का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब 1967 के बाद राज्य में पहली बार किसी गैर-द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय के राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही दशकों से द्रविड़ दलों (द्रमुक और अन्नाद्रमुक) के बारी-बारी सत्ता पर काबिज रहने की परंपरा टूटी है, जो राज्य की राजनीति में नई पीढ़ी और एक नए राजनीतिक विमर्श के प्रवेश का संकेत भी है। उल्लेखनीय है कि 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन इसे सरकार बनाने के लिए दस विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। कांग्रेस के पांच और भाकपा-माकपा के दो-दो विधायकों के समर्थन के बावजूद विजय की पार्टी बहुमत से दूर थी। फिर, वीसीके और आइयूएमएल के समर्थन से आखिरकार अनिश्चितता समाप्त हो गई और राज्य को अपना नौवां मुख्यमंत्री मिल गया। हालांकि दक्षिण भारतीय राजनीति में सिनेमा और राजनीति का मेल नया नहीं है। अन्नादुरई, एम करुणानिधि और एमजीआर से लेकर जयललिता तक तमिल समाज ने फिल्मी सितारों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर भी स्वीकार किया है। विजय भी इसी परंपरा की नई कड़ी हैं, जिन्होंने अपनी सार्वजनिक छवि को राजनीतिक दिशा दी और युवाओं के बीच एक प्रभावशाली समर्थन तैयार किया। सिनेमा में भले नायक अकेले ही समस्याओं का समाधान कर देता है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में निर्णय सामूहिक जिम्मेदारी से लिए जाते हैं। लिहाजा, उनके सामने गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को साथ रखने की चुनौती होगी। तमिलनाडु देश के उन राज्यों में गिना जाता है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में, नए मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि उनका कम प्रशासनिक अनुभव राज्य के विकास की राह में बाधा न बने। जल संकट, कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याएं और मछुआरों की परेशानियां जैसे मुद्दे तो राज्य के सामने हैं ही, केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाना भी उनकी राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा होगी। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विजय की राजनीति अब तक प्रमुखतः भावनात्मक अपील और जनसंपर्क पर आधारित रही है, पर मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनसे ठोस नीतिगत दृष्टि की अपेक्षा की जाएगी। लोकतंत्र में हर नया नेतृत्व एक अवसर लेकर आता है। विजय का मुख्यमंत्री बनना भी इसका ही प्रतीक है, जिसमें तमिलनाडु नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। अब यह तो राज्य के नए निजाम और उनकी टीम पर ही निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को सुशासन की स्थायी मिसाल में कैसे बदलते हैं।

हर उत्पाद का कार्बन फुटप्रिंट होता है

आज सरकारें उद्योगों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां प्रदर्शित करने के लिए दबाव बना रही हैं। यदि यह संभव है, तो उत्पादों पर कार्बन फुटप्रिंट भी दर्शाया जाना चाहिए, क्योंकि हर उत्पाद कार्बन उत्सर्जन करता है, जो पृथ्वी के लिए नुकसानदेह है।

अनिल पी. जोशी
पर्यावरणविद

बढ़ते तापमान और अनिश्चित जलवायु व्यवहार ने पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर दिया है। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, वह हमारी ही देन है। हमारी वर्तमान जीवनशैली और उपभोक्तावाद इसके प्रमुख कारण हैं। पृथ्वी की एक सीमित वहन क्षमता है, और इसका शोषण उस सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण इसी अति-शोषण के स्पष्ट उदाहरण हैं।

मानव पहले की तुलना में कहीं अधिक उपभोक्ता बन गया है। पहले हमारी निर्भरता स्थानीय संसाधनों तक सीमित थी, जो स्थिरता का समर्थन करती थी। औद्योगीकरण के साथ, उपभोक्ता बाजारों ने ऐसे उत्पाद बनाने शुरू किए, जो आकर्षक तो थे, लेकिन बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के कारण जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे।

हममें से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम जो कुछ भी लेते, खाते या उपभोग करते हैं, उसका अपना एक कार्बन फुटप्रिंट होता है। जितना अधिक हम ऐसे उत्पादों का उपभोग करेंगे, उतना ही हम सीधे तौर पर कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा बनते जाएंगे। यदि यह समझ हमें हो जाए, तो शायद हम शुरुआत में ही व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अब तक हम ऐसे बड़े कदम नहीं उठा पाए हैं।

हर उत्पाद पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करता है और उन्हें कार्बन उत्सर्जन के रूप में वापस लौटाता है। उदाहरण के लिए, चाहे हम चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या कपड़ों का उपयोग करें, हर उत्पाद का अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है। प्रत्येक कोल्ड ड्रिंक लगभग 0.15 से 0.3 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करती है। व्यापक रूप से पसंद किए जाने वाले जंक फूड का कार्बन फुटप्रिंट 0.3 से 3 किलोग्राम तक होता है, जो उसके घटकों और प्रसंस्करण पर निर्भर करता है। कॉस्मेटिक उत्पाद भी अपनी संरचना, पैकेजिंग और अन्य प्रक्रियाओं के कारण लगभग 0.2 से 6 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करते हैं।

उच्च कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों में खाद्य पदार्थों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पाद भी शामिल हैं। आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले उत्पादों में, कॉफी बीन्स लगभग 17 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करते हैं, जबकि चॉकलेट लगभग 19 किलोग्राम प्रति किलोग्राम। प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे आलू के चिप्स या वेफर्स लगभग 2.5–4 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, नमकीन या भुजिया लगभग 2–3.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, बिस्कुट लगभग 2–3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, और इंस्टेंट नूडल्स लगभग 3–5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करते हैं। खाद्य पदार्थों में, बीफ का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, जो लगभग 15.5 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम (लगभग 155 किलोग्राम प्रति किलोग्राम) है। इसके बाद मटन लगभग 5.8 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम और प्रॉन लगभग 4.1 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम उत्सर्जित करते हैं। पनीर लगभग 2.8 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि पोर्क और चिकन क्रमशः लगभग 2.4 किलोग्राम और 1.8 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम उत्सर्जित करते हैं।

इसके विपरीत, मैन्युअल या घरेलू उत्पादों का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। घर पर बने भुने हुए स्नैक्स का कार्बन फुटप्रिंट एक किलोग्राम प्रति किलोग्राम से कम होता है, जिससे वे अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बनते हैं। मुख्य खाद्य उत्पादन में, चक्की आटा लगभग 0.4–1.0 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि पारंपरिक घराट या हाथ से चलने वाली चक्कियां केवल 0.05–0.2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करती हैं। इसी प्रकार, खेती की पद्धतियों में भी अंतर दिखाई देता है। जैविक खेती लगभग 0.2–0.6 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित करती है, जबकि रासायनिक आधारित खेती का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, जो 0.8 से 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम तक होता है। औद्योगिक वस्त्र उत्पादन का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, क्योंकि यह बिजली से चलने वाली मशीनों, जीवाश्म ईंधन, रासायनिक प्रसंस्करण और लंबी परिवहन श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है। औसतन, फैक्टरी में बने वस्त्र लगभग 15–25 किलोग्राम प्रति किलोग्राम कपड़े के हिसाब से कार्बन उत्सर्जित करते हैं। इसके विपरीत, हाथकरघा (हैंडलूम) से बने वस्त्रों का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, जो लगभग 1–3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम होता है। हस्तनिर्मित कागज औसतन लगभग 100–300 किलोग्राम प्रति टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि पेपर मिल लगभग 600–1,900 किलोग्राम प्रति टन कार्बन उत्सर्जन करती हैं।

उपभोक्ता इन तथ्यों से काफी हद तक अनजान हैं। दुर्भाग्यवश, मितव्ययिता उद्योगों के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि उनकी वृद्धि अत्यधिक उपभोग को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है। पिछले 100 वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति ने मानव जीवन को अधिक आरामदायक बनाया है, और उद्योगों ने इसका लाभ उठाकर अपने उत्पादों का आक्रामक प्रचार किया है, जो अक्सर आकर्षक मगर भ्रामक जानकारी पर आधारित होता है। आज सरकारें उद्योगों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां प्रदर्शित करने के लिए दबाव बना रही हैं। यदि यह संभव है, तो उत्पादों पर कार्बन फुटप्रिंट क्यों नहीं दर्शाया जाना चाहिए? यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोक्ता इस बात से अनजान हैं कि उनका उपभोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यह वह समय है, जब जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण के प्रति व्यापक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन की जानकारी, ठीक वैसे ही दी जानी चाहिए, जैसे कैलोरी और सामग्री की दी जाती है। यह उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद कर सकती है कि कोई उत्पाद न केवल उनके स्वास्थ्य पर, बल्कि पृथ्वी पर भी क्या प्रभाव डालता है।

हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि उपभोक्ता को योगदानकर्ता भी होना चाहिए। इस पहल के माध्यम से लोग यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें कम कार्बन वाले उत्पादों का उपयोग करना है, और इस प्रकार हम सभी प्रकृति की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नेपोलियन बोनापार्ट

यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कौन-सा है, तो मैं कहूंगा- वह युद्ध जो मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। अपने अहंकार से युद्ध। यदि मैं अपने भीतर की अधीरता को जीत पाता, तो मेरा जीवन अलग ही होता।

जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कौन-सा है

मैंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते। राजाओं को झुकते देखा, साम्राज्यों को मिटते देखा और अपनी सेना को यूरोप की धरती पर विजयी कदमों से चलते देखा। एक समय ऐसा था, जब लोग मुझे अपराजेय कहते थे। मुझे खुद भी लगने लगा था कि मेरी इच्छा ही इतिहास की दिशा बदल सकती है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। मैं शुरू से बेहद महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षा की ये आग मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी। मेरे भीतर ऊपर उठने की एक बेचैनी थी। मैं निर्धन द्वीप कोर्सिका से आया था। मेरे पास कोई विरासत नहीं थी। अगर पास कुछ था, तो केवल मेरा यह विश्वास कि मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी नियति बदल सकता है। और फिर मैंने इसी को अपना धर्म बना लिया। युद्धभूमियों पर मैंने जाना कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस समय मुझे सचमुच लगता था कि इच्छाशक्ति से सब कुछ जीता जा सकता है। और शायद उसी विश्वास ने मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन ऊंचाइयां मनुष्य को एक भ्रम भी देती हैं। लगातार विजय मिलने लगे, तो मनुष्य यह भूलने लगता है कि वह भी सीमित है। मैंने भी यही भूल की। मुझे लगने लगा था कि मैं समय और प्रकृति से भी बड़ा हो गया हूं। यही महत्वाकांक्षा का सबसे खतरनाक क्षण होता है, जब वह प्रेरणा से अहंकार में बदल जाती है। मैंने साम्राज्य जीते, लेकिन उस समय मैं स्वयं को नहीं जीत पाया था। संसार पर अधिकार करना आसान है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर अधिकार करना बेहद मुश्किल है। एक राजा हजारों सैनिकों को आदेश दे सकता है, परंतु अपने भीतर उठती लालसाओं को काबू करना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। प्रकृति ने मुझे बता दिया कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह अजेय नहीं है। मैंने अपने सैनिकों को भूख से मरते देखा। उस समय मैंने जाना कि महत्वाकांक्षा यदि विवेक से न जुड़ी हो, तो वह हजारों लोगों के दुख का कारण बन सकती है। उस हार ने मुझे भीतर से बदल दिया था। पराजय केवल सिंहासन ही नहीं छीनती, वह मनुष्य से उसका भ्रम भी छीन लेती है।

यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कौन-सा है, तो मैं कहूंगा- वह युद्ध जो मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। अपने भय से युद्ध, अपने अहंकार से युद्ध। मैंने अनेक देशों को जीता, लेकिन यदि मैं अपने भीतर की अधीरता और अतृप्त महत्वाकांक्षा को जीत पाता, तो मेरा जीवन अलग ही होता। फिर भी मैं महत्वाकांक्षा को दोष नहीं दूंगा। महत्वाकांक्षा मनुष्य की ऊर्जा है। उसी से सभ्यताएं बनती हैं, नए विचार जन्म लेते हैं, साधारण मनुष्य असाधारण बनते हैं। अंततः मैंने समझा कि सबसे बड़ी अमरता मनुष्य के कर्मों और विचारों में होती है, साम्राज्यों में नहीं। साम्राज्य टूट जाते हैं। सेनाएं बिखर जाती हैं। विजय के जयघोष मौन हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं को जीत लेता है, उसकी विजय समय भी नहीं मिटा सकता।

सपने देखो, आगे बढ़ो

सूत्र

महत्वाकांक्षा मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन सच्ची विजय तब मिलती है,जब वह अपने भय, अहंकार और असंतुष्ट इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख ले। स्वयं को जीतना सबसे कठिन और महान युद्ध है। शक्ति, साम्राज्य और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, जबकि चरित्र, विवेक और आत्मसंयम ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। इसलिए सपने देखो, आगे बढ़ो।

दूसरा पहलू

वेबपेज लोगों में केवल मुख्य जानकारी तेजी से खोजने की आदत डालते हैं, जिससे गहराई से पढ़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

जब हम डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ते हैं

एरिक डी. राइक्ले

समस्या उन डिजिटल उपकरणों से पढ़ने में आती है, जिनमें विज्ञापन, पॉप-अप, वीडियो बच्चों का ध्यान भटकाते हैं।

दृश्य जानकारी को आंखों से मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 60 मिलीसेकंड और शब्द पहचानने में अतिरिक्त 100 से 300 मिलीसेकंड लगते हैं। यही कारण है कि पढ़ने की गति की एक सीमा होती है।

स्वीडन सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि वह कक्षाओं में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को कम करके फिर से किताबों की ओर रुख कर रही है। सरकार ने छात्रों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को इसका मुख्य कारण बताया है। डिजिटल स्क्रीन व किताबों पर पढ़ने से जुड़ा विज्ञान इसके प्रभावों के बारे में क्या बताता है? भले ही पढ़ना आसान काम लगे, लेकिन वास्तव में यह एक जटिल क्षमता है, जिसे सीखना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी आंखें तेजी से एक शब्द से दूसरे शब्द तक जाती हैं। इन्हें 'सैकेड्स' कहा जाता है। आंखें केवल छोटे-छोटे ठहरावों के दौरान ही शब्दों को स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। शोध बताते हैं कि एक बार में हमारी दृश्य जानकारी ग्रहण करने की क्षमता सीमित होती है। अंग्रेजी जैसी भाषाओं में आंखें बाईं ओर केवल 2-3 अक्षरों और दाईं ओर 8-12 अक्षरों तक ही स्पष्ट पहचान कर पाती हैं। किसी शब्द को पहचानने में भी समय लगता है। दृश्य जानकारी को आंखों से मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 60 मिलीसेकंड और शब्द पहचानने में अतिरिक्त 100 से 300 मिलीसेकंड लगते हैं। यही कारण है कि पढ़ने की गति की एक सीमा होती है और बहुत तेज पढ़ने पर समझने की क्षमता घटने लगती है। पढ़ने की अच्छी क्षमता वर्षों के अभ्यास से विकसित होती है। इसमें दृष्टि, ध्यान, शब्द पहचान, भाषा समझ और आंखों की गतिविधियों से जुड़े मस्तिष्क के हिस्से एक साथ काम करते हैं। ई-रीडर जैसे उपकरणों में किताब और डिजिटल पढ़ाई में अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि वे पढ़ने की प्रक्रिया को सहयोग देते हैं। लेकिन समस्या उन उपकरणों में आती है, जिनमें विज्ञापन, पॉप-अप, वीडियो ध्यान भटकाते हैं। छोटे बच्चों में ध्यान नियंत्रित करने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसलिए बार-बार आने वाले व्यवधान उनकी समझ को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि वेबपेज लोगों में केवल जानकारी तेजी से खोजने की आदत डाल सकते हैं, जिससे गहराई से पढ़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल पढ़ाई तेजी से बढ़ी, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। चूंकि पढ़ने की क्षमता किसी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए डिजिटल पढ़ाई के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। *(द कन्वर्सेशन)*

आंकड़े

मातृ मृत्यु दर

भारत में प्रति एक लाख जन्मों पर 88 मांओं की मौतें दर्ज की गई हैं। देश में आज भी कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं की जान सबसे अधिक खतरे में है।

ओडिशा	153
छत्तीसगढ़	146
मध्य प्रदेश	142
उत्तर प्रदेश	141
असम	110

आंकड़े मातृ मृत्यु दर के, संख्या में।

स्रोत : सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम

श्रीकृष्ण कालयवन नामक राक्षस को एक गुफा में ले गए, जहां मुचुकुंद सो रहे थे। मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही राक्षस भस्म हो गया।

भक्ति और तप का मार्ग

अंतर्यात्रा
संकलित

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक समय असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र ने इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। राजा ने देवताओं की ओर से युद्ध किया और अपने अद्भुत बल से असुरों को पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा।

राजा मुचुकुंद ने पृथ्वी पर अपने परिवार के पास लौटने की इच्छा जताई, परंतु इंद्र ने बताया कि स्वर्ग में बीते एक वर्ष के दौरान पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं और उनके प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने वरदान मांगा कि वे गहरी निद्रा में सो सकें और जो भी उन्हें जगाए, वह उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए। इंद्र ने उन्हें यह वरदान दे दिया। राजा एक गुफा में जाकर सो गए। त्रेतायुग से सोते-सोते वे द्वापर युग में पहुंच गए। उसी समय कालयवन नामक राक्षस श्रीकृष्ण का पीछा कर रहा था। भगवान उसे मुचुकुंद की गुफा में ले गए। कालयवन ने अंधेरे में मुचुकुंद को पैर से ठोकर मार दी। जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी, कालयवन भस्म हो गया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने राजा को दर्शन देकर भक्ति व तप का मार्ग बताया। अंततः तपस्या द्वारा मुचुकुंद को मोक्ष प्राप्त हुआ।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 मई, 1952

रूस हवाई शक्ति बढ़ा रहा है, इससे अमेरिका को खतरा है

अमरीका को रूस से खतरा
वह अपनी हवाई शक्ति बढ़ा रहा है

अमेरिकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैंडनबर्ग ने कहा कि रूस तेजी से अपनी हवाई शक्ति बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका की रक्षा योजना को भारी खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा।

नए संतुलन की तलाश में

राजकिशोर

मुद्दा

हालिया चुनाव परिणाम इस धारणा को स्पष्ट चुनौती देते हैं कि बंगाली अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी विचार हैं।

हालिया चुनाव परिणामों ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वहां के सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर एक नए विमर्श को जन्म दिया है। अक्सर तर्क दिया जाता रहा है कि बंगाल की वैचारिक भूमि पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसे आज हिंदुत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, की जड़ें नहीं हैं और यह उत्तर या पश्चिम भारत से आयातित एक राजनीतिक विचार है। यदि तटस्थ विश्लेषण किया जाए, तो एक भिन्न तस्वीर उभरती है। सामान्यतः माना जाता है कि हिंदुत्व शब्द और उसके व्यापक अर्थों की अवधारणा सावरकर ने स्थापित की, पर उनसे लगभग तीन दशक पहले 1892 में बंगाली विद्वान चंद्रनाथ बसु ने अपनी पुस्तक *हिंदुत्वः हिंदुर प्राकृत इतिहास* में इसे परिभाषित किया था। बसु के लिए यह कोई संकीर्ण धार्मिक आग्रह नहीं, बल्कि व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक आत्मबोध था। उन्होंने विविधता के भीतर सांस्कृतिक निरंतरता को समाज की बड़ी शक्ति माना।

यह वह समय था, जब बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक चेतना आकार ले रही थी और समाज सुधारक अपनी परंपराओं तथा जड़ों की ओर लौटकर नई पहचान गढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बंकिम के *आनंदमठ* ने आधुनिक राष्ट्र की कल्पना केवल एक भूभाग के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के प्रतीक रूप में की। *आनंदमठ* का 'वंदे मातरम्' अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से जुड़े युवाओं के लिए प्रतिरोध का प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी वैचारिक मंथन को स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने व्यापक आयाम दिए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को आत्मविश्वास और आधुनिकता के साथ प्रस्तुत किया। जबकि महर्षि अरविंद ने अपने 'उत्तरपाड़ा अभिभाषण' में सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। स्वतंत्रता के बाद यह विमर्श राजनीतिक स्वरूप में तब सामने आया, जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। डॉ. मुखर्जी ने बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना को राष्ट्रीय अखंडता और राजनीतिक संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास किया।

बंगाल पुनर्जागरण की परंपरा में ब्रह्म समाज, रवींद्रनाथ की सार्वभौमिक मानवीय दृष्टि, सामाजिक सुधार आंदोलनों और बाद के वामपंथी विचारों का भी गहरा प्रभाव रहा है। अनेक इतिहासकारों व विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की अस्मिता बहुस्तरीय रही है, जिसमें धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना के साथ उदारवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की परंपराएं भी शामिल रही हैं। अतः वर्तमान राजनीतिक बदलाव को केवल सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में देखना सरलीकरण होगा।

स्वतंत्रता के बाद के दशकों में लंबे वामपंथी शासन और बाद में क्षेत्रीय राजनीति के दौर में 'बंगाली अस्मिता' को एक विशेष राजनीतिक व सांस्कृतिक ढांचे में परिभाषित किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा, काली पूजा और अन्य पारंपरिक उत्सवों को सिर्फ सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी अवधि में यह धारणा मजबूत हुई कि बंगाली अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी विचार हैं। हालिया चुनाव परिणाम इस धारणा को चुनौती देते हैं। चुनाव के दौरान ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक अभिव्यक्ति के बीच संबंध अधिक स्पष्ट दिखाई दिया। नंदीग्राम जैसे क्षेत्रों में, जहां कभी भूमि और कृषि अधिकारों के संघर्ष प्रमुख थे, वहां अब सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी चर्चा के केंद्र में दिखा।

इससे यह प्रतीत होता है कि बंगाल का एक बड़ा वर्ग अब बंगाली अस्मिता और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के बीच विरोध नहीं देखता। *कृत्तिवास रामायण*, चंडी पाठ और शक्ति उपासना जैसी परंपराएं लंबे समय से बंगाल के सामाजिक जीवन का हिस्सा रही हैं। वर्तमान राजनीति में इन प्रतीकों की बढ़ती उपस्थिति को समाज का एक वर्ग अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में देख रहा है। वहीं आलोचकों का मानना है कि यह ध्रुवीकरण को भी जन्म दे सकता है। यही कारण है कि बंगाल का वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन को केवल चुनावी घटना नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे इतिहास, सांस्कृतिक स्मृतियों, सामाजिक बदलावों और समकालीन राजनीति की जटिल अंतःक्रिया काम करती दिखती है। नए राजनीतिक संकेत बताते हैं कि राज्य का समाज अपनी विभिन्न ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धाराओं के बीच नए संतुलन की तलाश में है। यह प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी, इसका अंतिम उत्तर भविष्य की राजनीति और समाज ही तय करेंगे।

ताकि सनद रहे

डायरेक्ट या रेगुलर फंड: किसे चुनना सही?

म्यूचुअल फंड की दुनिया में जब कोई निवेशक कदम रखता है, तो अक्सर उसके सामने एक ही योजना के दो अलग-अलग विकल्प आते हैं- एक है डायरेक्ट और दूसरा रेगुलर। पहली नजर में ये दोनों बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे दिखते हैं।

इनका निवेश पोर्टफोलियो एक होता है, फंड मैनेजर भी वही होता है और बाजार की चाल के साथ इनके बढ़ने या घटने की रणनीति भी एक जैसी होती है। लेकिन, इन दोनों के बीच एक ऐसा बारीक अंतर छिपा है, जो लंबे समय में आपके मुनाफे की पूरी तस्वीर बदल सकता है।

खर्च और कमीशन का गणित

इन दोनों विकल्पों के बीच बुनियादी अंतर केवल निवेश करने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी लागत का है।

- **डायरेक्ट फंड:** जब आप किसी डायरेक्ट फंड में निवेश करते हैं, तो आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़ते हैं। इसमें बीच में किसी बिचौलिये, एजेंट या वितरक की कोई भूमिका नहीं होती।
- **रेगुलर फंड:** रेगुलर फंड में एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक होता है।

सुनने में यह अंतर बहुत मामूली लग सकता है- शायद आधा या एक फीसदी- लेकिन जब आप 15 से 20 साल के निवेश की बात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यह छोटा-सा अंतर लाखों रुपये के मुनाफे का अंतर पैदा कर देता है। यही कारण है कि डायरेक्ट फंड में रिटर्न हमेशा रेगुलर फंड से थोड़ा बेहतर दिखाई देता है।

सिर्फ बचत नहीं, व्यवहार भी है जरूरी

अगर डायरेक्ट फंड सस्ता है, तो रेगुलर फंड का अस्तित्व क्यों है? इसका जवाब निवेशक के व्यवहार में छिपा है।

एक अच्छा सलाहकार आपकी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से सही योजना चुनने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण जब बाजार में उतार-चढ़ाव आता है और घबराहट बढ़ती है, तब सलाहकार आपको जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से रोकता है। म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग रिटर्न से ज्यादा अपने व्यवहार के कारण नुकसान उठाते हैं। बार-बार फंड बदलना या बाजार गिरते ही पैसा निकाल लेना ऐसी गलतियां हैं, जो किसी भी अतिरिक्त शुल्क से कहीं ज्यादा भारी पड़ती हैं।

आप कहां खड़े हैं?

चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आप निवेश को लेकर कितने सक्रिय हैं।

- **डायरेक्ट फंड उनके लिए है:** जिन्हें बाजार की बुनियादी समझ है, खुद रिसर्च कर सकते हैं, योजनाओं की निगरानी करने का समय है और बाजार की उथल-पुथल में शांत रहकर फैसले ले सकते हैं।
- **रेगुलर फंड उनके लिए है:** जो निवेश की दुनिया में नए हैं, बाजार को ट्रैक करने का समय नहीं है या चाहते हैं कि कोई विशेषज्ञ आपके निवेश की निगरानी करे और मुश्किल समय में सही दिशा दिखाए।

तारीख पता है?

आईपीओ लिस्टिंग

- **15 मई:** Bagmane Prime Office Reit Co. (3405 करोड़ रुपये)

घोषणाएं

- **11 मई:** मलेशियाई पाम ऑयल के आंकड़े, जनवरी-मार्च के लिए बेरोजगारी आंकड़े
- **12 मई:** अप्रैल के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति आंकड़े, USDA 2025-26 के लिए विश्व कृषि आपूर्ति और मांग अनुमानों के संशोधित आंकड़े पेश करेगा
- **13 मई:** OPEC की मासिक रिपोर्ट, IEA की मासिक रिपोर्ट
- **14 मई:** अप्रैल के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़े
- **15 मई:** SBI की EGM,
- **20 मई:** बुनियादी क्षेत्र उत्पादन आंकड़े

■ **डिस्क्लेमर :** अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।

भारत में संपत्ति का सुरक्षा घेरा बहुत कमजोर है। आग, बाढ़ और भूकंप जैसी कोई बड़ी आपदा किसी भी मिडिल क्लास परिवार को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने के लिए काफी है। 2026 का सबसे बड़ा सबक यही है-संपत्ति बनाना जितना जरूरी है, उसे बीमा से सुरक्षित करना उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य है।

जीवन की तरह संपत्ति का बीमा भी है जरूरी

आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके वित्तीय झटकों से खुद को बचाना आपके अपने हाथ में है।

विराज ने 10 साल तक दिन-रात मेहनत करके नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान खड़ी की थी। दुकान को नया लुक देने के लिए विराज ने शानदार इंटीरियर और महंगे एसी पर 5 लाख रुपये खर्च किए।

जब उनसे किसी ने इंश्योरेंस की बात की, तो उनका जवाब था- छोड़िए भाई साहब, यहां कुछ नहीं होता, ये पैसे की बर्बादी है।

विराज की तरह अधिकांश लोग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को आज भी पैसे की बर्बादी मानते हैं। यही वजह है कि भारत में बीमा का सुरक्षा अंतराल (Protection Gap) औसतन 92-95% है। इसका मतलब है कि 100 रुपये के नुकसान में से 95 रुपये का बोझ आपकी या सरकार की जेब पर पड़ता है।

भारत का बीमा बाजार तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। भारत में कुल बीमा पेनेट्रेशन जीडीपी का 3.7% है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के मामले में यह 1% से भी कम है।

जबकि इसकी तुलना में जोखिम लगातार बढ़ रहा है। 2024 में 365 में से 322 दिन भारत ने अत्यधिक खराब मौसम का सामना किया। 2025 में यह बढ़कर 331 दिन हो गया। 2022 से 2025 के बीच आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में 47% का इजाफा हुआ। 2023 में 7,000 से ज्यादा आग लगने की दुर्घटनाएं हुईं।

■ आइए अब जानते हैं होम इंश्योरेंस का कवरेज तय कैसे होता है

होम इंश्योरेंस कवरेज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप केवल इमारत का बीमा करा रहे हैं, केवल सामान का या दोनों का। इमारत का मूल्य रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, न कि संपत्ति का बाजार मूल्य। इमारत का मूल्य जानने के लिए, संपत्ति के निर्मित क्षेत्र और प्रति वर्ग फुट निर्माण दर का गुणा किया जाता है।

इसे उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए आपके घर का निर्मित क्षेत्र 1200 वर्ग फुट है और निर्माण लागत 1,500 प्रति वर्ग फुट है, तो इमारत के ढांचे के लिए बीमा राशि 18 लाख होगी।

होम इंश्योरेंस लागत का अनुमान

कवरेज का प्रकार	बीमा राशि	अनुमानित वार्षिक प्रीमियम
केवल ढांचा	18 लाख	1,200-2,000 रुपये
केवल सामान	05 लाख	500-1,200 रुपये
व्यापक कवर	23 लाख	1,500-3,000 रुपये
ऐड-ऑन्स के साथ	25 लाख +	2,500-4,500 रुपये

Source: बैंक बाजार डॉट कॉम। दरें बीमाकर्ता, स्थान, संपत्ति की आयु और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

भारत में आपदा और सुरक्षा का हाल

आपदा	अनुमानित नुकसान	बीमा कवरेज	कवरेज नहीं
बाढ़	2000 से 2024 के बीच 100 अरब डॉलर	5%	95%
चक्रवात/तूफान	2000 से 2024 के बीच 15-20 अरब डॉलर	5–8%	92–95%
भूकंप	कुल 10-15 अरब डॉलर, 2001 गुजरात में 4.5 अरब डॉलर	1%	99%
सूखा	2016 में जीडीपी पर 100 अरब डॉलर का प्रभाव	2–5%	95%
लू	सीधे तौर पर 1-3 अरब डॉलर	1%	99%
भूस्खलन	कुल 1-2 अरब डॉलर, 2013 में अकेले उत्तराखंड में 2 अरब डॉलर	1%	99%
जंगल की आग	1.74 लाख करोड़ रुपये/वर्ष अनुमानित हानि	1%	99%
औद्योगिक, शहरी आग	हर साल 1,000 करोड़ रुपये की बीमित हानि	30-40%	60-70%
सभी आपदाएं	2000 से 2024 के बीच 162 अरब डॉलर	5–8%	92–95%

Source: Munich Re, Swiss Re, UNDP, EM-DAT, IMD, Germanwatch CRI 2026

अनिवार्य आवश्यकता बन गया है बीमा

अमिताभ दीवान
हेड, लार्ज कॉर्पोरेट रिस्क, पॉलिसीबाजार फॉर बिजनेस

हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम मौसम, पावर ग्रिड या हमारे आसपास के लोगों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, वह है हमारी तैयारी। जीवन भर की मेहनत से बनाए घर या दुकान को असुरक्षित छोड़ना वैसा ही है जैसे तूफान में दरवाजा खुला छोड़ देना। अपनी संपत्ति को एक व्यापक बीमा पॉलिसी के साथ सुरक्षित करना आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए सबसे अधिक पेशेवर और जिम्मेदारी भरा काम है।

IRDAI ने बदली जनरल इंश्योरेंस की दुनिया

अब किसी भी क्लेम को केवल 'दस्तावेजों की कमी' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

- बीमा कंपनी को जो भी दस्तावेज चाहिए, उन्हें पॉलिसी देते वक्त ही मांगना होगा। क्लेम के समय आपसे सिर्फ वही कागज मांगे जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर उस घटना से जुड़े हों।
- रिटेल ग्राहक अब जब चाहें अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। कंपनी को बचे हुए समय का प्रीमियम आनुपातिक आधार पर वापस करना होगा।
- बीमा कंपनी आपकी पॉलिसी तब तक कैंसिल नहीं कर सकती जब तक कि 'धोखाधड़ी' साबित न हो जाए।
- आग बीमा के साथ बाढ़, भूकंप और आतंकवाद के लिए अलग से ऐड-ऑन चुनने या हटाने की पूरी आजादी।
- पॉलिसी के साथ एक सरल पन्ने की कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, जिसमें आसान भाषा में लिखा होगा- क्या कवर है, क्या नहीं और क्लेम कैसे मिलेगा।

बीमा लेते वक्त इन गलतियों से बचें

- पुनर्निर्माण लागत के बजाय बाजार मूल्य का उपयोग करना
- सामान के मूल्य का कम अनुमान लगाना
- उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का हिसाब न रखना
- सस्ते प्रीमियम के चक्कर में जरूरी ऐड-ऑन्स को छोड़ देना

समझ-बूझ

खोया हुआ पीएफ वापस दिलाएगा ई-प्राप्ति पोर्टल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निष्क्रिय खातों की खोज के लिए आधार आधारित पोर्टल ई-प्राप्ति शुरू किया है। इससे उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका पैसा निष्क्रिय खातों में फंसा हुआ है।

आधार बनेगा पहचान की चाबी

- अक्सर पुरानी नौकरियों के दौरान बने भविष्य निधि खातों का विवरण याद नहीं रहता या वे यूएएन से जुड़े नहीं होते। ई-प्राप्ति पोर्टल आधार के जरिये सत्यापन की एक सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करेगा।
- इससे सदस्य अपने उन पुराने खातों तक पहुंच सकेंगे, जो वर्तमान पहचान संख्या से नहीं जुड़े हैं। इसके बाद अपनी जानकारी को अपडेट कर उन्हें मुख्य खाते से जोड़ना और सक्रिय करना आसान हो जाएगा।

किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ?

- यूएएन के दौर से पहले काम शुरू करने वाले और जिनके पास रोजगार के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है।
- पहला चरण उनके लिए जिन्हें अपनी पुरानी सदस्य पहचान संख्या याद है।

खबरों के आर-पार

कर्ज में हुई चूक तो प्रॉपर्टी होगी जब्त

बैंक और NBFC कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की जमीन-मकान को जब्त कर सकेंगे। RBI के नए मसौदा नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्ज NPA बन जाता है और वसूली के अन्य सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बैंक अपनी वसूली नीति के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त कर सकते हैं।

- RBI ने ऐसी संपत्तियों के निपटान के लिए अधिकतम सात साल की समय सीमा का प्रस्ताव दिया है।
- संपत्तियों का निपटान निष्पक्ष आधार पर करना होगा ताकि वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक राशि वसूल की जा सके।

पूछताछ

मेरी पहले से EMI चल रही है, क्या नया कर्ज मिल सकता है?

हां, यदि आप पहले से EMI चुका रहे हैं, तब भी आप नया कर्ज ले सकते हैं, लेकिन यह आपकी बचत और FOIR अनुपात पर निर्भर करता है।

बैंक केवल आपकी कुल तनख्वाह नहीं देखते, बल्कि आपकी कुल मासिक आय में से वर्तमान की सभी EMI को घटा देते हैं। जो राशि बचती है, उसी के आधार पर तय होता है कि आप नया कर्ज लेने के योग्य हैं या नहीं। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (FOIR) सबसे महत्वपूर्ण संख्या है, जिसे बैंक ट्रैक करते हैं। यह मापता है कि आपकी आय का कितना हिस्सा पहले से ही ईएमआई के लिए प्रतिबद्ध है। एक आदर्श FOIR 50% से कम होना चाहिए।

आमतौर पर बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके सभी मासिक खर्च (नए प्रस्तावित कर्ज सहित) आपकी कुल आय के 50-60% से अधिक न हों। वे यह विश्वास चाहते हैं कि आप बिना किसी डिफॉल्ट के नए कर्ज की किस्तें चुका सकेंगे।

फंड की फिटनेस

NFO की मुख्य बातें

- **निवेश अवधि:** 4 मई से 15 मई तक
- **यूनिट आवंटन:** 20 मई
- **न्यूनतम निवेश:** 100 रुपये से शुरुआत
- **एग्जिट लोड:** 15 दिनों से पहले 0.25%

बाजार की बुनियाद पर दांव

अब एक्सचेंज और ब्रोकिंग हाउस की कमाई बनेगी आपका मुनाफा

आमतौर पर निवेशक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदकर मुनाफे की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस दुकान का हिस्सा बनने के बारे में सोचा है जहां ये शेयर बिकते हैं? एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐसा ही अनूठा मौका देने के लिए लेकर आया है- एक्सिस निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स फंड। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो खुद शेयर बाजार के सिस्टम को चलाती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकिंग हाउस और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां।

Axis Nifty Capital Markets Index Fund

■ कमाई का मॉडल

इसका गणित बहुत सीधा है। जब बाजार में ट्रेडिंग बढ़ती है, नए निवेशक आते हैं या IPO की धूम मचती है, तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी इन कंपनियों की आय में वृद्धि होती है। चूंकि यह एक इंडेक्स फंड है, इसलिए यह निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स का अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर खुद स्टॉक नहीं चुनता, बल्कि इंडेक्स की कंपनियों में उसी अनुपात में पैसा लगाता है, जिससे निवेश की लागत भी कम रहती है।

■ सावधानी भी जरूरी

ध्यान रहे कि यह एक सेक्टर-आधारित फंड है। यदि बाजार में सुस्ती आती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, तो इस सेक्टर की कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आ सकता है, जिसका सीधा असर आपके रिटर्न पर पड़ेगा। इसलिए, इसमें वही निवेशक हाथ डालें जो बाजार के उतार-चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हों।

■ एक्सपर्ट की सलाह

मनी ट्री के सह-संस्थापक सिद्धार्थ शर्मा के अनुसार, यह फंड उन आक्रामक निवेशकों के लिए बेहतर है, जो पहले से ही मिडकैप या मल्टीकैप फंडों में निवेश कर रहे हैं। इसमें 3 से 5 साल का लंबी अवधि का नजरिया रखना जरूरी है।

म्यूचुअल फंड और एफडी की भीड़ में पेंशन को न भूलें

पेंशन सिर्फ बचत नहीं, एक अनुशासन है। यह 40-50 साल की लंबी साझेदारी है। इसलिए अपनी वित्तीय योजना में म्यूचुअल फंड के साथ पेंशन को भी जरूर शामिल करें।

एस. रमन
चेयरमैन
पीएफआरडीए

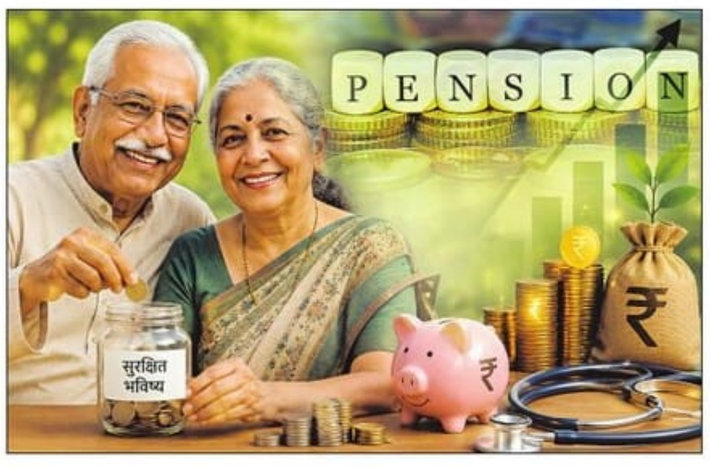

अब से ठीक 10 साल बाद यानी 2036 में भारत की तस्वीर बदल चुकी होगी। तब तक देश में बुजुर्गों की आबादी 20 करोड़ को पार कर जाएगी। साल 2011 की तुलना में यह दोगुनी होगी। परिवार छोटे हो रहे हैं और औसत उम्र बढ़ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ आज की कमाई का नहीं, बल्कि उस वक्त की आर्थिक गरिमा का है, जब हाथ-पैर काम करना बंद कर देंगे।

पेंशन म्यूचुअल फंड नहीं है। अक्सर हम इन दोनों को एक ही तराजू में तौलते हैं लेकिन पेंशन का मकसद एटीएम से पैसा निकालना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य के लिए लोहे की दीवार खड़ी करना है। एनपीएस को आम आदमी के लिए सरल व सुलभ बनाने के लिए पीएफआरडीए पेंशन क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रहा है.

■ एनपीएस संचय बनेगा सरल निवेश विकल्प

एनपीएस संचय उन निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो फंड मैनेजर या एसेट एलोकेशन (इक्विटी, सरकारी बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड) चुनने की जटिलता में नहीं पड़ना चाहते। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें निवेश का एक निश्चित ढांचा होगा जैसा कि 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए चल रहा है।

यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्हें एसेट एलोकेशन की समझ नहीं है लेकिन वे एक सुरक्षित उत्पाद चाहते हैं, जो अच्छा मार्केट रिटर्न दे सके। पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार इस ढांचे ने लगभग 9.5% का औसत वार्षिक रिटर्न दिया है, जो कई अन्य सरकारी बचत योजनाओं और बैंक एफडी से काफी अधिक है।

■ यूपीआई से खुलेगा खाता

पेंशन को उतना ही सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, जितना सरल एक बैंक खाता खोलना या यूपीआई पेमेंट करना है। इसके लिए अगले 30 दिनों के भीतर दो बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होने की उम्मीद है। भीम इंटरफेस पर यूपीआई के माध्यम से आप मात्र दो क्लिक में अपना एनपीएस खाता खोल सकेंगे। यदि आपका किसी बैंक (जैसे एसबीआई) में पहले से बचत खाता है, तो यूपीआई एप आपके बैंक के माध्यम से ही आपकी केवाईसी जानकारी प्राप्त कर लेगा। आपको अलग से कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। खाता खुलने के बाद आप यूपीआई के जरिये कभी भी और कितनी भी बार आसानी से पैसा जमा कर पाएंगे।

■ स्टार एनपीएस से बढ़ेगी पहुंच

यह प्लेटफॉर्म बीएसई स्टार के साथ मिलकर बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी गैर-बैंक डिस्ट्रीब्यूटर्स और यहां तक कि ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को भी पेंशन एजेंट बनाया जा सकेगा। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ सुदूर गांवों तक एनपीएस की पहुंच आसान हो जाएगी।

■ यह क्यों महत्वपूर्ण है?

वर्तमान में म्यूचुअल फंड में कमीशन (ट्रेल कमीशन) लगभग 1.5% के करीब है, जबकि एनपीएस में यह बहुत कम है। डिजिटल वितरण से न केवल लागत कम होगी, बल्कि उन 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना भी मुमकिन होगा, जो वर्तमान में किसी भी पेंशन दायरे से बाहर हैं।

जानना जरूरी है

पेंशन + स्वास्थ्य: बुढ़ापे का डबल कवर

पेंशन सेक्टर का सबसे क्रांतिकारी बदलाव 'पेंशन-स्वास्थ्य खाता होने वाला है। एक 'फूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' पर काम चल रहा है। इसमें आपके पेंशन फंड का एक हिस्सा स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होगा। यह एक टॉप-अप इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। अस्पताल के खर्च का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य खाते से जाएगा और बाकी का 5 लाख तक का कवर इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसका प्रीमियम बहुत कम होगा क्योंकि यह एक ग्रुप पॉलिसी की तरह काम करेगा।

एनपीएस अब पहले से कहीं ज्यादा लचीला है

- पहले 60% पैसा निकाल सकते थे और 40% की एन्युटी (पेंशन) लेना अनिवार्य था। अब इसे बदलकर 80-20 कर दिया गया है। यानी अब आप मैच्योरिटी पर अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते हैं।
- यदि आपका कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये तक है, तो आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं। 15 साल के लॉक-इन का डर अब खत्म हो गया है।
- आप 75 साल की उम्र तक अपनी एन्युटी को टाल सकते हैं, तब तक आपका पैसा बाजार के रिटर्न के साथ बढ़ता रहेगा।

इन्फोग्राफिक्स

केंद्रीय बैंकों ने बेचा सोना क्या फीकी पड़ेगी गोल्ड की चमक?

दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने पिछले 10 महीनों में पहली बार मार्च 2026 में सोने की बिकवाली की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में केंद्रीय बैंकों ने शुद्ध रूप से 30 टन सोना बेचा है।

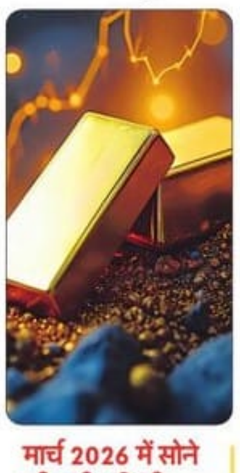

सबसे बड़े बिकवाल

60 टन
सोना बेचा तुर्किये ने
(सबसे बड़ी बिकवाली)

देश	बिकवाली
रूस	6 टन
अजरबैजान	22 टन *

*(Q1 2026 के दौरान)

प्रमुख खरीदार:

11 टन
सोना खरीदा पोलैंड ने
(सबसे ज्यादा खरीदारी)

देश	खरीदारी
उज्बेकिस्तान	9 टन
कजाकिस्तान	6 टन
चीन	5 टन

मार्च 2026 में सोने की खरीद-बिक्री

विवरण	आंकड़े
कुल खरीद	37 टन
कुल बिक्री	66 टन
शुद्ध बिक्री	30 टन
12 महीने का औसत	21 टन

गोल्ड बाजार पर क्या असर?

- अगर केंद्रीय बैंक की बिकवाली का ट्रेंड जारी रहा, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है।

Source: WGC, बोनस रिसर्च

कंटेंट : अमर उजाला बोनस टीम

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

टीचिंग एसोसिएट के पदों पर रिक्तियां

3540 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 03 जून, 2026
वेतनमान : रुपये 28,850 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : rssb.rajasthan.gov.in

कर्मचारी चयन आयोग ■ 731 पद

स्टेनोग्राफर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
पात्रताएं : बारहवीं व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : ssc.gov.in

बीपीसीएल में करें आवेदन ■ 250 पद

जूनियर एग्जीक्यूटिव व अन्य पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 17 मई, 2026
आयु-सीमा : पदानुसार अधिकतम उम्र 32 व 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : bharatpetroleum.in

ऑयल इंडिया में मौके ■ 49 पद

जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 08 जून, 2026
पात्रताएं : दसवीं, बारहवीं व अन्य योग्यताएं
यहां आवेदन करें : oil-india.com

संघ लोक सेवा आयोग ■ 45 पद

असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 29 मई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsc.gov.in

आईआईएफसीएल में रिक्तियां ■ 15 पद

उप-महाप्रबंधक व सहायक महाप्रबंधक के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 08 जून, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम उम्र पदानुसार 45 वर्ष व 50 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : iifcl.in/Site/Index/189

यहां भी हैं रोजगार के अवसर...

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश : निदेशक का पद खाली।

- आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19 मई, 2026
- iwai.nic.in

भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ : शोध सहयोगी/शोध सहायक का पद खाली।

- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
- iiml.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

नवाचार के अग्रदूत

एलन मस्क से प्रेरित और दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह विकसित और सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाले गैलेक्सआई के संस्थापकों में से एक सुयश सिंह ने अंतरिक्ष जगत में नवाचार का अग्रदूत बनकर वाकई एक क्रांति की है।

पहचान

शख्स
सुयश सिंह

चर्चा
उनकी कंपनी गैलेक्सआई के 'मिशन दृष्टि' की वजह से।

क्यों
उनके नेतृत्व में दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

साल 2019, जुलाई का महीना और कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स के ऑफिस का नजारा। पूरी दुनिया की नजरें 'हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता' पर टिकी थीं। दुनियाभर से आए हजारों प्रतिभाशाली इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास से आई एक टीम भी मौजूद थी। यह टीम अपने सपनों को एक छोटे-से 'पॉड' (एक प्रकार का कैप्सूल) में समेटकर यहां तक पहुंची थी। खास बात यह है कि 2,500 से अधिक आवेदकों में से प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली यह इकलौती एशियाई टीम थी, जिसका नेतृत्व एक युवा इंजीनियर कर रहा था। हालांकि, फाइनल में जर्मनी की टीम विजयी हुई, लेकिन भारतीय टीम के नवाचार की स्वायत्तता और उसके बेजोड़ इंजीनियरिंग कौशल ने स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क तक को बेहद प्रभावित किया। मस्क ने न केवल टीम से मुलाकात की, बल्कि उनके काम को सराहा और टीम के सदस्यों के जज्बे की खुलकर तारीफ भी की। उस टीम का नेतृत्व करने वाला वही युवा इंजीनियर वर्षों बाद आज दुनियाभर में सुर्खियों में छाया हुआ है। नाम है सुयश सिंह। फिलवक्त सुयश की चर्चा उनकी कंपनी गैलेक्सआई के 'मिशन दृष्टि' की वजह से हो रही है, जिसके तहत दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह अत्याधुनिक उपग्रह बादलों, धुएं और घने अंधेरे के पार भी स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है।

बादलों के पार देखने वाली तकनीक

सुयश सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अलग-अलग स्कूलों में हुई। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की और बाद में आईआईटी, मद्रास से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। कॅरिअर की शुरुआत उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में डाटा एनालिटिक्स से की, जिसके बाद वे मशीन विजन और डीप-टेक रिसर्च से जुड़े। 2021 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 'गैलेक्सआई' की स्थापना की।

भारत की पहली टीम

आईआईटी में पढ़ाई के दौरान ही सुयश सिंह ने वर्ष 2017 में 'आविष्कार हाइपरलूप' टीम बनाई। इसे भारत की पहली छात्र-नेतृत्व वाली हाइपरलूप टीम माना जाता है। नवाचार क्षमता और नेतृत्व कौशल के कारण उन्हें आन्त्रप्रेन्योर इंडिया की प्रतिष्ठित '35 अंडर 35' सूची में भी शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा, वह एआईईएसईसी से भी जुड़े रहे हैं। यह युवाओं से जुड़ा एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है, जो दुनिया के 100 से अधिक देशों में सक्रिय है।

सात समंदर पार की सीख

सुयश पहली बार हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता में असफल हो गए थे। इसके बाद, उन्होंने अपने खर्चे पर अमेरिका जाकर प्रतियोगिता को करीब से समझा और फिर टीम की रणनीति बदली। इसी बदलाव के बाद उनकी टीम 2019 में फाइनल तक पहुंची। सुयश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उस मेल को पसंद करते हैं, जो जटिल से जटिल डाटा (जैसे सैटेलाइट इमेज) को आम लोगों के लिए आसान बना सके।

जब प्रधानमंत्री ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सुयश सिंह और उनकी टीम की 'न्यू इंडिया के युवा नवोन्मेषक' कहकर सराहना की थी। यह किसी युवा डीप-टेक संस्थापक के लिए बड़ी उपलब्धि है। सुयश एक अच्छे वक्ता भी हैं और टेडएक्स जैसे मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।

जिंदगी का यादगार लम्हा

एलन मस्क से हुई अपनी मुलाकात को सुयश अपनी जिंदगी का ड्रीम मोमेंट मानते हैं। सुयश एलन मस्क को ही अपना प्रेरणास्रोत भी मानते हैं। मस्क के 'फर्स्ट प्रिंसिपल्स' दृष्टिकोण और असंभव लगने वाले लक्ष्यों को हासिल करने की उनकी क्षमता से वह काफी प्रभावित हैं।

जंगलों की आग का वह 'एहसास'

सुयश को स्टार्टअप गैलेक्सआई की प्रेरणा किसी बोर्डरूम से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा से मिली थी। साल 2018 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग का अध्ययन करते समय सुयश ने एक गंभीर तकनीकी कमजोरी को महसूस किया कि पारंपरिक ऑप्टिकल सैटेलाइट घने धुएं के पार नहीं देख सकते थे, और दूसरी ओर रडार डाटा इतना जटिल था कि आम लोगों के लिए उसका उपयोग करना बहुत मुश्किल था। इसी हताशा और चुनौती ने उन्हें 'ऑप्टोसार' बनाने के लिए प्रेरित किया। यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड सेंसर है, जो एक ही सैटेलाइट में ऑप्टिकल और रडार इमेजिंग, दोनों की खूबियों को जोड़ता है।

आज का दिन

11 मई, 1998

भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी सैन्य और वैज्ञानिक ताकत का परिचय दिया तथा परमाणु संपन्न राष्ट्र बना।

- 1910 : ग्लेशियर नेशनल पार्क की स्थापना उत्तर-पश्चिमी मोंटाना में की गई थी।
- 1951 : राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था।
- 1965 : बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में लगभग 17 हजार लोगों की मौत हुई थी।
- 2000 : भारत के एक अरबवीं बच्ची 'आस्था' का जन्म हुआ।

व्रत त्योहार

आज : ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी।
कल : ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

- सूर्योदय : 05.36
- सूर्यास्त : 18.58

(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 22 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 29 प्रविष्टे, 24 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी 14.52 तक उपरांत एकादशी, पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र 25.16 तक उपरांत उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र, वैधृति योग 23.18 तक उपरांत विष्कुम्भ योग, विष्टि (भद्रा) करण 14.52 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा मीन राशि में 19.19 बजे।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है। स्वजन सहयोग मिलेगा।

वृष : मन में आशा का संचार होगा। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

मिथुन : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। भौतिक सुख साधनों पर व्यय होगा। संतान पक्ष से कुछ चिंता रहेगी।

कर्क : पराक्रम में वृद्धि होगी। राजकाज में सफलता मिलेगी। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा।

सिंह : आत्मबल बनाए रखें। पूर्वनियोजित कार्य सफल होगा। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे।

कन्या : आरोग्य सुख उत्तम रहेगा। राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं।

तुला : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। धैर्य रखने पर योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में सहकर्मियों से निराशा होगी।

वृश्चिक : लोकप्रियता में कमी आ सकती है। भू-संपत्ति के कार्य अटक सकते हैं। नौकरी में व्यस्तता बढ़ेगी।

धनु : मनोत्साह बना रहेगा। विरोधी शांत रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकार बढ़ सकते हैं। यात्रा से अटका कार्य बनेगा।

मकर : मानसिक उलझन बनी रहेगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

कुंभ : दिनमान सामान्य रहेगा। अटके कार्य में आंशिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

मीन : वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। यात्रा में कष्ट होगा। व्यवसाय में मंदी रहेगी।

सुडोकू

4	9			6		8	5	
	5		1				9	
6								4
2	8				9			3
	7						2	
1			3				4	5
8								9
	2				4		8	
	4	6		5			7	2

उत्तर

4	9	7	2	6	3	8	5	1
3	5	2	1	4	8	6	9	7
6	1	8	7	9	5	2	3	4
2	8	4	5	7	9	1	6	3
5	7	3	4	1	6	9	2	8
1	6	9	3	8	2	7	4	5
8	3	5	6	2	7	4	1	9
7	2	1	9	3	4	5	8	6
9	4	6	8	5	1	3	7	2

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

दिल्ली-एनसीआर

एल्विश यादव को कॉल और मैसेज कर मांगी 10 करोड़ की रंगदारी

गुरुग्राम। बिग बॉस ओटीटी-2 विजेता एल्विश यादव से कॉल व मैसेज करके 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। आरोपियों ने विदेशी नंबर से रंगदारी का मैसेज केवल एल्विश यादव को ही नहीं बल्कि उनके पिता को भी भेजा है। दो दिन में रुपये न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। मामले की जानकारी मिलने व शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-56 थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस को दी शिकायत में एल्विश यादव ने बताया कि 5 मई को उनके पास विदेशी नंबर से कॉल आई थी। वे यह कॉल उठा नहीं पाए। इसके कुछ देर बाद विदेशी नंबर से ही व्हाट्सएप पर मैसेज आए। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नजदीकी रणदीप मलिक बताया और उसने 10 करोड़ रुपये देने की मांग की। यह रकम दो दिन में देने के लिए कहा गया। ऐसा न करने पर गोली मारने की धमकी दी गई।

एल्विश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि यह मैसेज न केवल उनके पास आया है बल्कि उनके पिता के मोबाइल पर भी भेजा गया है। ब्यूरो

डीएमई पर मनमानी... फिर पहुंची बाइक, हादसे में दो युवकों की मौत

भोजपुर में ट्रक के ब्रेक लगाने से हुई दुर्घटना, पुलिस-एनएचएआई की निगरानी पर सवाल

संवाद न्यूज एजेंसी

मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर प्रतिबंध के बावजूद बाइक दौड़ाने से दो और युवकों की जान चली गई। हादसा रविवार दोपहर भोजपुर के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, युवकों के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया। बाइक तेज रफ्तार में होने के कारण ट्रक से टकरा गई। इस हादसे ने एक बार फिर पुलिस और एनएचएआई की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि भोजपुर के पट्टी गांव निवासी दीपू (18) और हापुड़ के सदीकपुरा निवासी सागर (18) दिल्ली से आ रहे थे। बाइक सागर चला रहा था और दीपू पीछे बैठा था। भोजपुर के पास हुए हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

पेट्रोलिंग वाहन ने उनको मोदीनगर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, सागर ने हेलमेट लगा रखा था। दीपू बिना हेलमेट के था। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत भाग निकला। एसीपी के अनुसार, उसकी पहचान की जा रही है। इसके लिए डीएमई पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद दोनों युवक दिल्ली से गाजियाबाद तक कैसे पहुंच गए। करीब 30 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करने के दौरान उन्हें कहीं भी नहीं रोका गया।

पुलिस अब एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों को हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों घरों में कोहराम मचा हुआ है।

परिवारों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दीपू और सागर अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मोदीनगर पट्टी गांव में मृतकों के घर मौजूद लोग। संवाद

सागर

दीपू

20 हजार रुपये चालान, फिर भी रोजाना टूट रहे नियम

डीएमई पर बाइक दौड़ाने पर 20 हजार रुपये तक का चालान किया जाता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बाइक सवार एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं। पहले गाजियाबाद में करीब 10 स्थानों पर चेकिंग होती थी, लेकिन अब कई जगह जांच अभियान कमजोर पड़ गया है। ऐसे में बाइक सवार बिना रोकटोक जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। एनएचएआई पर भी जागरूकता और निगरानी व्यवस्था मजबूत न करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी होने के बावजूद बाइक सवारों को रोकने के प्रभावी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराया कैंटर, दो महिलाओं और मासूम की मौत

हापुड़ : चालक को झपकी आने से हादसा, बरेली से लुधियाना जा रहे थे लोग

संवाद न्यूज एजेंसी

गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखैड़ा रहमतपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार की देर रात तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। घटना में दो महिलाओं और एक नौ माह के बच्चे की मौत हो गई। चालक को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। दोनों महिलाओं के पति घायल हो गए हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का यातायात बहुत देर तक बाधित रहा।

पुलिस के अनुसार जिला हरदोई के गांव मांझ निवासी अभिषेक व उनका साला लालाराम निवासी गांव सुकटिया सिंगावली जिला बरेली अपने परिवारों के साथ पंजाब के लुधियाना जा रहे थे। दोनों वहां पर खेतों में मजदूरी करते हैं। शनिवार की शाम करीब छह बजे अभिषेक, उसकी पत्नी चांदनी, नौ माह के पुत्र अभिजीत, साला लालाराम व साले की पत्नी सावित्री के साथ किराए के कैंटर में ट्रैक्टर, बाइक व घरेलू सामान लादकर लुधियाना रवाना हुए थे। अभिषेक व लालाराम कैंटर में पीछे बैठे थे। चांदनी, सावित्री व अभिजीत आगे अंदर केबिन में थे।

देर रात करीब 12 बजे गांव जखैड़ा रहमतपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आ गई। इससे तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में सावित्री, चांदनी व अभिजीत की मौके पर ही मौत हो गई। कैंटर में पीछे बैठे अभिषेक और लालाराम घायल हो गए। हादसा होने के बाद कैंटर चालक भाग गया। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर एक तरफ यातायात बाधित हो गया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कैंटर को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अभिषेक और लालाराम को वापस भेज दिया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि हादसे के संबंध में पुलिस को अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस कैंटर चालक की तलाश कर रही है।

मां चांदनी के साथ बेटा अभिजीत

सावित्री
फाइल फोटो

हादसे में कैंटर में सवार दोनों के पति भी घायल, चालक भागा

नींद आने पर चालक को पिलाई थी चाय

घायल लालाराम ने बताया कि दुर्घटना से पहले भी कैंटर चालक को गजरौला के आसपास नींद आने लगी थी। इससे चालक कैंटर को सही ढंग से नहीं चला पा रहा था। दुर्घटना न हो इसलिए उन्होंने एक ढाबे पर कैंटर रुकवाकर चालक को चाय पिलाई थी। ड्राइवर ने वहां कुछ देर आराम भी किया था।

टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कसा शिकंजा ईडी ने अटैच 349.55 करोड़ की संपत्ति

ईडी ने जारी किया कंपनी के निदेशकों को नोटिस

फरीदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लि. के खिलाफ धनशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 349.55 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की हैं। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई के बाद कंपनी प्रबंधन पर कानूनी दबाव बढ़ गया है। मामले में कंपनी के निदेशकों समेत संबंधित संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

ईडी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के कुंडली व सोनीपत क्षेत्र में 26 आवासीय व वाणिज्यिक परियोजनाएं लॉन्च की थीं। इन परियोजनाओं के नाम पर 14,105 ग्राहकों से करीब 4,619.43 करोड़ रुपये जुटाए गए।

जांच एजेंसी का आरोप है कि ग्राहकों से ली गई राशि का इस्तेमाल परियोजनाओं को पूरा करने के बजाय दूसरी कंपनियों में निवेश, जमीन खरीद और पुराने कर्ज चुकाने में किया गया। जांच में कई परियोजनाओं के अधूरे होने और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लंबित मिलने की बात सामने आई है। पार्क स्ट्रीट समेत कई प्रोजेक्ट वर्षों बाद भी पूरे नहीं हो सके। ब्यूरो

अंडरपास में कैंटर ने बाइक सवार को रौंदा, मौत

नोएडा। सेक्टर-71 अंडरपास में रविवार की शाम एक तेज रफ्तार कैंटर वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दूर जाकर कैंटर चालक कैंटर छोड़कर भाग निकला।

सूचना पर पहुंची फेज-3 थाना पुलिस ने अंडरपास में ट्रैफिक रुकवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही कैंटर को भी कब्जे में लिया। मौके पर करीब 45 मिनट तक अंडरपास में सेक्टर-52 से 71 की ओर का आवागमन बंद रहा। थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के नंदग्राम का विनोद कुमार (29) किसी काम से नोएडा बाइक से आए थे। ब्यूरो

परियोजना — यूपीएसआरटीसी ने जारी किया टेंडर, 170 करोड़ रुपये है अनुमानित लागत, पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण

नोएडा में बनेगा एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस टर्मिनल

काव्यांश मिश्रा

नोएडा। सेक्टर-35 के मोरना बस डिपो की सूरत बदलने वाली है। करीब 170 करोड़ की लागत से यहां नया बस टर्मिनल बनेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस टर्मिनल का निर्माण देखरेख व संचालन का टेंडर जारी कर दिया है। परियोजना के प्रारूप के मुताबिक यहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही यहां शॉपिंग मॉल और होटल भी बनेगा।

करीब 31 हजार वर्ग मीटर में बने मोरना बस डिपो से लखनऊ, उत्तराखंड समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों के लिए बसें संचालित की जाती है। लेकिन यहां पर अभी सुविधाएं बेहतर स्थिति में नहीं हैं। शहर के बीच स्थित बस डिपो को नए सिरे से बस टर्मिनल के रूप में बनाने का निर्णय परिवहन निगम ने लिया है। इसका मकसद अन्य राज्यों व जिलों के लिए बस सेवा का विस्तार है। इसके साथ ही यहां पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना है। निगम की तरफ से जारी किए गए टेंडर में पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल निर्माण से जुड़ी परियोजना के लिए कई शर्तें भी शामिल की गई हैं। पीपीपी मॉडल पर तैयार होने वाले बस टर्मिनल की देखरेख चयनित एजेंसी करेगी। एजेंसी को 33 साल के लिए बस टर्मिनल और 90 साल के लिए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स की देखरेख व निगरानी मिलेगी। बस टर्मिनल में यात्रियों के लिए होटल भी बनाए जाएंगे। लंबे सफर से आए यात्री होटलों में विश्राम कर सकेंगे।

पीपीपी मॉडल पर बस टर्मिनल बनना है। इसके लिए मुख्यालय से ही कार्य किया जाना है। बस टर्मिनल बनने से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। - **मनोज कुमार सिंह, आरएम गौतमबुद्ध नगर**

डिपो से रोजाना 188 बसें होती हैं रवाना

नोएडा बस डिपो 188 बसें संचालित होती हैं। जो लखनऊ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मेरठ, बरेली, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, हरिद्वार, देहरादून तक जाती हैं। डिपो से एक भी एसी बस नहीं रवाना होती।

नोएडा और गाजियाबाद समेत 49 जिलों में मिली थी मंजूरी

पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने के लिए प्रदेश के 49 जिलों के बस डिपो को चिन्हित किया गया था। इसमें आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, इटावा, नोएडा, मेरठ, हरदोई, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, अयोध्या आदि शामिल किए गए थे। इन डिपो पर यात्रियों का आवागमन ज्यादा होने के कारण ये निर्णय लिया गया था। अब मंजूरी मिलने से आगामी कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

कल्पमेधा

लोग धूल की तरह होते हैं। या तो वे आपको पोषण देकर एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वे आपका विकास रोककर और थका कर मृत कर सकते हैं।

– प्लेटो

चीन का चेहरा

आखिरकार चीन ने दुनिया के सामने यह सच कबूल लिया है कि पिछले वर्ष भारत के 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान उसने पाकिस्तान की सहायता की थी। यह पहली बार है, जब चीन ने इस संघर्ष में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका स्वीकार की है। हालांकि भारत ने संघर्ष विराम के बाद विश्वास के साथ यह दावा किया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के खुलासे हुए थे, लेकिन चीन ने अब तक इन्हें खारिज कर दिया था। दरअसल, चीन वैश्विक जगत को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान उसकी भूमिका एक तटस्थ देश की रही है। मगर, चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। अब चीन की इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसी लिहाज से अपनी रक्षा नीतियां, कूटनीति और रणनीति तैयार करनी होंगी। पिछले कुछ समय से ऊपरी तौर पर चीन का रुख भले ही भारत को लेकर आक्रामक न रहा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक ऐसे देश की है, जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके जवाब में भारत ने 'आपरेशन सिंदूर' चलाकर सीमा पार आतंकियों के कई ठिकानों पर हमला किया था। इस कार्रवाई में सौ से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी। भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पिछले साल जुलाई में यह दावा किया था कि चीन ने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी मदद प्रदान की थी। भारत की सैन्य तैनाती की निगरानी के लिए उसने अपने उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया था। तब चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। मगर बीते गुरुवार को चीन के विमानन उद्योग निगम के चेंगदू वायुयान डिजाइन एवं अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने मीडिया से एक साक्षात्कार में माना कि आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी मदद प्रदान की गई थी।

दरअसल, पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन निर्मित जे-10सीई लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जिनका उत्पादन चीन के विमानन उद्योग निगम की एक सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है। खबरों के मुताबिक, चीन ने भारत-पाक संघर्ष को अपने लड़ाकू विमानों की क्षमता को परखने की एक प्रयोगशाला की तरह लिया और पाकिस्तान को तकनीकी मदद मुहैया कराई। साफ है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग अब केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है। पाकिस्तान के जरिए चीन अपने आधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणालियों का वास्तविक युद्ध स्थितियों में परीक्षण कर रहा है। चीन की यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय में सामने आई है, जब वह पाकिस्तान को अपना जे-35 बमवर्षक विमान बेचने की योजना बना रहा है। ऐसे में चीन के इस कबूलनामे को अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह सक्षम दिखाने और उन्हें सैन्य हथियारों के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल, चीन की चालबाजी से यह साफ है कि भारत को भविष्य में संघर्ष की स्थिति में और अधिक सतर्क रहना होगा। साथ ही भारत को चीन के नापाक इरादों को कूटनीति के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाना चाहिए।

संवाद के बजाय

बिहार के पटना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान राज्य की पुलिस का जैसा रवैया सामने आया है, उसे आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत किसी मसले पर सरकार से विचार की मांग के स्वर का दमन करने की तरह देखा जा सकता है। सवाल है कि अगर नागरिकों के सामने अपनी किसी मांग के लिए आंदोलन या प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तो संवाद के जरिए उनकी समस्या का समाधान करने या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी या उन्हें चुप कराने के लिए सीधे लाठी-डंडे का सहारा लिया जाएगा? हैरानी की बात है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में लगातार देरी और टालमटोल से परेशान विद्यार्थियों ने जब पटना में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अगर उन्हें रोकना भी था, तो पानी की बौछार या कोई अन्य उपाय करने के बजाय बेहरमी से उन पर लाठियां चलाना ही अकेला उपाय क्यों माना गया?

राज्य की पुलिस के इस रवैये को क्या किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों के प्रति एक लोकतांत्रिक शासन की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? अगर नागरिकों के किसी हिस्से को सरकार से अपने अधिकार या अन्य मांग करने से इस तरह रोका जाएगा, तो उसमें नागरिक अधिकारों की क्या जगह रह जाएगी? आखिर क्या वजह है कि विद्यार्थियों के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाने की नौबत आई है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर सरकार का यह रुख सामने आया है। इससे पहले भी कई बार विद्यार्थियों और अन्य नागरिक समूहों ने अलग-अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार या बातचीत करने के बजाय उन्हें चुप करने और भगाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया गया। अफसोसनाक यह है कि बिहार में जो पार्टियां फिलहाल सत्ता में हैं, उन्होंने एक समय जनता की उपेक्षा किए जाने को ही मुद्दा बनाया था। हकीकत यह है कि आंदोलनों या प्रदर्शन के प्रति पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का जो रवैया है, उससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए जगह सिमट रही है।

युद्ध की महत्त्वाकांक्षा के परोक्ष मोर्चे

अफसोसनाक है कि महाशक्तियों ने अपनी युद्ध महत्त्वाकांक्षा के लिए मछलियों को भी नहीं बख्शा। आमतौर पर युद्ध के समय अन्य चिंता के कारण इसका विरोध दब जाता है।

पुष्परंजन

होर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा बिछाए बारूदी सुरंगों की खोज और उन्हें निष्क्रिय करने में अमेरिका क्या 'कामिकाजे डाल्फिन' का इस्तेमाल कर रहा है? हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से जब यह पूछा गया, तो वे चुप लगा गए और सिर्फ इतना बोल सके कि 'न तो हम इसकी पुष्टि करेंगे और न ही इससे इनकार करेंगे कि हमारे पास कामिकाजे डाल्फिन हैं।' होर्मुज में ईरान भी 'कामिकाजे डाल्फिन' का इस्तेमाल कर सकता है। इस मामले में ईरान का सैन्य सहयोगी रूस उसके साथ खड़ा है। दरअसल, 'कामिकाजे' द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी पायलट थे, जो अपने विमानों को मित्र देशों के युद्धपोतों से टकराकर आत्मघाती हमले करते थे। शीत युद्ध के दौरान, सोवियत नौसेना ने समुद्री जीवों से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए थे, जिनमें काला सागर में डाल्फिन को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। यह इकाई सेवस्तोपोल के पास 'कजाच्या बुख्ता' में स्थित थी और आज भी वहीं मौजूद है। मौजूदा दौर में चूंकि ईरान की मदद रूस अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, इसलिए उस पर अमेरिकी एजंसियों को शक होना लाजिमी है।

डाल्फिन ही एकमात्र समुद्री जीव नहीं हैं, जिन्हें रूस ने प्रशिक्षण दिया हो। वर्ष 2019 में नार्वे के तट पर देखी गई एक बेलुगा ह्वेल के बारे में माना गया था कि उसे रूसी नौसेना ने प्रशिक्षण दिया था। मछुआरों का कहना था कि बेलुगा ह्वेल ने अजीब तरह की 'हार्नेस' पहन रखी थी, जिसमें शायद कैमरे लगे थे और वह उनकी नावों से बंधी पट्टियों और रस्सियों को खींच रही थी।

अमेरिकी नौसेना के पास भी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मदद के लिए डाल्फिन को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम दशकों पुराना है। मनुष्यों का आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर यानी आइक्यू 7.4 के साथ सबसे अधिक है, लेकिन बाटल-नेक डाल्फिन की आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर 5.3 है, जो अन्य सभी जीवों की तुलना में काफी अधिक है। 'कैलिफोर्निया सी लायन' भी कम नहीं है, जिसने बुद्धिमत्ता परीक्षण में इंसानों को पीछे छोड़ा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांताक्रूज प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस सील प्रजाति वाली मछली के परीक्षण के लिए कई परीक्षण-प्रारूप तैयार किए थे। आखिर डाल्फिन के साथ-साथ 'कैलिफोर्निया सी लायन' को भी नौसैनिक अभियानों और जल खुफियागिरी जैसे कार्यों के लिए चुना गया।

अमेरिका का 'मरीन मैमल प्रोग्राम' प्रशांत महासागर में अवस्थित 'नेवल इन्फार्मेशन वारफेयर सेंटर' का अहम हिस्सा है। वे शायद झूठ बोलते हैं कि इस महकमे की डाल्फिन 'कामिकाजे डाल्फिन' नहीं हैं, क्योंकि वे बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देती हैं। इसके बजाय उनका मुख्य काम बारूदी सुरंगों का पता लगाना है।

फौजी मकसद के लिए डाल्फिन का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है। रूस ने भी अपने बंदरगाहों की रखवाली के लिए इनका इस्तेमाल किया है। ईरान ने साल 2000 में रूस से डाल्फिन खरीदी थी। वे प्रशिक्षित डाल्फिन शायद बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान के पास कोई सक्रिय डाल्फिन कार्यक्रम है। हालांकि 'वाल स्ट्रीट जर्नल' ने पिछले महीने एक खबर दी थी कि ईरान होर्मुज जलमार्ग को खोलने की अमेरिकी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए बारूदी सुरंगें ले जाने वाली डाल्फिन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा था।

> अमेरिकी नौसेना के पास भी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मदद के लिए डाल्फिन को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम दशकों पुराना है। डाल्फिन और समुद्री शेरों, दोनों की कम रोशनी में देखने की क्षमता और पानी के भीतर दिशात्मक श्रवण शक्ति उत्कृष्ट होती है, जिससे वे अंधेरे या धुंधले पानी में भी पानी के नीचे के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं। डाल्फिन को पानी के नीचे बिछी उन खानों का पता लगाने और उनके स्थान को चिह्नित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो सैन्य या नागरिक जहाजों पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

अमेरिकी नौसेना का डाल्फिन कार्यक्रम 1959 से चल रहा है, जिसका मकसद 'बाटल-नोज डाल्फिन' और 'कैलिफोर्निया सी लायन्स' को पानी के नीचे की चीजों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने का प्रशिक्षण देना है। 'मरीन मैमल प्रोग्राम' के वेबपेज के मुताबिक, 'प्रशिक्षित डाल्फिन के पास सबसे उन्नत 'सोनार' होता है। पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन इन जीवों का मुकाबला नहीं कर सकते'। यह भी एक तथ्य है कि डाल्फिन और समुद्री शेरों, दोनों की कम रोशनी में देखने की क्षमता और पानी के भीतर दिशात्मक श्रवण शक्ति उत्कृष्ट होती है, जिससे वे अंधेरे या धुंधले पानी में भी पानी के नीचे के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं। डाल्फिन को पानी के नीचे बिछी उन खानों का पता लगाने और उनके स्थान को चिह्नित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो सैन्य या नागरिक जहाजों पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

समुद्र में बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले अभियान के दौरान एक डाल्फिन आमतौर पर एक छोटी नाव में दो-तीन प्रशिक्षकों के साथ यात्रा करती है। कुछ मिलने पर ये जीव नाव के आगे वाले चप्पू को थपथपाते हैं और कुछ न मिलने पर पीछे वाले चप्पू को थपथपाते हैं। डाल्फिन खोजी गई खानों के पास 'मार्कर बुआ' छोड़ती हैं, ताकि मानव गोताखोर उन्हें ढूंढ़कर निष्क्रिय कर सकें, लेकिन डाल्फिन का उपयोग आमतौर पर होर्मुज जलमार्ग में मौजूद सक्रिय युद्ध जैसी स्थिति में नहीं किया जाता है। इसके बजाय डाल्फिन का उपयोग लड़ाई समाप्त होने के बाद बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में विशेष रूप से 2003 की उस घटना का उल्लेख किया जाता है, जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा दक्षिणी इराक पर कब्जा करने के बाद इराकी बंदरगाह 'उम कसर' की ओर जाने वाली किसी भी बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए डाल्फिन को तैनात किया गया था।

सैन्य उद्देश्यों के लिए डाल्फिन को प्रशिक्षित करने का रूसी इतिहास जबरदस्त रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह इकाई यूक्रेन की सेना के अधीन चली गई। 'सेवस्तोपोल कार्यक्रम' को 2012 में यूक्रेनी नौसेना द्वारा फिर से शुरू किया गया था। यूक्रेन ने सेवस्तोपोल के पास एक एक्वेरियम में डाल्फिन को प्रशिक्षित किया था। यह कार्यक्रम सोवियत-युग की एक योजना से प्रेरित था, जो 1990 के दशक में उपेक्षा का शिकार हो गया था। सेवस्तोपोल नौसैनिक अड्डा रूसी सेना के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्रीमिया के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिस पर मास्को ने 2014 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने इन जीवों को वापस करने की मांग की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दो साल बाद रूसी नौसेना ने पांच और डाल्फिन खरीदने की योजना की घोषणा की। यह स्पष्ट नहीं है कि आज सेवस्तोपोल में मौजूद मानी जाने वाली डाल्फिन वही हैं या नहीं। वर्ष 2018 की उपग्रह तस्वीरों से पता चला कि रूस ने सीरियाई युद्ध के दौरान सीरिया के टार्टस में अपने नौसैनिक अड्डे पर भी डाल्फिन का इस्तेमाल किया था।

इस मसले पर सबसे अफसोसनाक है कि महाशक्तियों ने अपनी युद्ध महत्त्वाकांक्षा के लिए मछलियों को भी नहीं बख्शा। इसे रोकने के लिए दुनिया के देश आगे क्यों नहीं आते? हालांकि पशु कल्याण संगठनों ने हमेशा सैन्य उद्देश्यों के लिए जानवरों के उपयोग पर चिंता जताई है, लेकिन यह विरोध आमतौर पर युद्ध के समय अन्य चिंता के कारण दब जाता है। अक्सर इन जीवों के सैन्य उपयोग से संबंधित जानकारी गोपनीय होती है, जिसके कारण सार्वजनिक विरोध का दायरा सीमित हो जाता है।

सीखने की यात्रा

फारूक आफरीदी

दुनिया मेरे आगे

दुनिया को हम अक्सर एक स्थान, एक व्यवस्था या फिर एक भौगोलिक विस्तार के रूप में देखते हैं, जहां मनुष्य जन्म लेता, जीता और आखिरकार विदा हो जाता है। हमारी दृष्टि अगर थोड़ी गहरी हो, तो यही दुनिया एक ऐसी विशाल पाठशाला दिखाई देती है, जहां हर क्षण एक पाठ, हर घटना एक अध्याय और हर अनुभव एक परीक्षा है। यहां कोई स्थायी शिक्षक नहीं, फिर भी हर व्यक्ति और हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। दुनिया दरअसल एक निरंतर चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है, बल्कि एक ऐसा सबक, जो कभी समाप्त नहीं होता। यह सचमुच अनुभवों की पाठशाला है। मनुष्य का पहला शिक्षक उसका परिवार होता है, लेकिन जैसे-जैसे इंसान दुनिया में कदम रखता है, उसकी शिक्षा का दायरा निरंतर बढ़ता जाता है। एक छोटा-सा बच्चा गिरकर चलना सीखता है, ठोकर खाकर संतुलन समझता है और यही दुनिया का पहला सबक है कि असफलता ही सफलता की जननी है।

जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां, दुख और असफलताएं- सभी उसी पाठशाला के कठिन अध्याय होते हैं। अगर हम इन्हें केवल पीड़ा के रूप में देखें, तो अधूरे विद्यार्थी बनकर रह जाते हैं। इन्हें सीखने का अवसर मानें, तो यही दुख हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने वाले औजार और आधार बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सबक अस्थिरता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न वैभव, न निर्धनता, न यश, न अपयश और जो कुछ आज है, वह कल नहीं होगा। यह परिवर्तनशीलता ही संसार का मूल स्वभाव है। दार्शनिक दृष्टि से देखें, तो यह अस्थिरता हमें विरक्ति का पाठ पढ़ाती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति आखिर दुख का कारण बनती है। इसलिए संसार का यह सबक हमें ऐसा संतुलन सिखाता है कि न अत्यधिक हर्ष में बहो, न अत्यधिक शोक में डूबो।

> संसार एक ऐसी पाठशाला है, जहां सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यहां हर व्यक्ति विद्यार्थी है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। हम अगर इसे समझ लें, तो जीवन केवल जीने का साधन मात्र नहीं, बल्कि समझ और अनुभव की एक गहन यात्रा बन जाता है।

दुनिया का एक और महत्त्वपूर्ण सबक अहंकार है। मनुष्य अपने ज्ञान, धन, शक्ति या पद के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। मगर एक बीमारी, एक दुर्घटना या एक अप्रत्याशित घटना हमारे सारे अहंकार को चूर-चूर कर देती है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो झुकता है, वही टिकता है। अकड़ने वाला टूट जाता है। हम रिश्तों को अक्सर स्वार्थ, अपेक्षाओं और अधिकारों के चश्मे से देखते हैं। दूसरी ओर जीवन के अनुभव हमें धीरे-धीरे सिखाते हैं कि सच्चा संबंध वह है, जिसमें त्याग, समझ और करुणा हो। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तब हमें उसके महत्त्व का अहसास होता है और तब समझ आता है कि समय रहते प्रेम व्यक्त करना कितना आवश्यक है। यह सबक हमें संवेदनशील बनाता है। साथ ही यह भी कि संबंध केवल निभाने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का आधार हैं।

कोई भी उपलब्धि बिना संघर्ष के संभव नहीं है। प्रकृति का हर नियम इसी सत्य को दोहराता है। बीज को अंकुर बनने के लिए जमीन को चीरना पड़ता है, नदी को अपना मार्ग बनाने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया का सबसे गूढ़ और महत्त्वपूर्ण सबक है- कर्म का सिद्धांत। यहां हर क्रिया का परिणाम होता है। अच्छा कर्म सुख देता है और बुरा कर्म दुख लाता है। यह जीवन का आंतरिक नियम है। यह सिद्धांत हमें जिम्मेदारी का बोध कराते हुए बताता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे निर्णय, हमारे कर्म- यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि से दुनिया एक दर्पण है और हम जो करते हैं, उसका अक्स लौटकर हमारे सामने आता है।

दुनिया का अंतिम और सबसे गहरा सबक आत्मज्ञान है। यह बहुत कम लोगों को होता है। बाहरी संसार के अनुभव हमें अंततः अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम बार-बार बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हुए निराश होते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह समझ अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि मनुष्य केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे परे एक चेतना है। यह दुनिया कभी सुख देकर तो कभी दुख की अनुभूति करवाकर धीरे-धीरे इस सत्य की ओर ले जाती है।

प्रकृति सबसे बड़ी और महान शिक्षक है। पेड़ हमें निस्वार्थ देना सिखाते हैं, नदियां हमें निरंतर बहते रहने का संदेश देती हैं और आकाश हमें विस्तार का बोध कराता है। प्रकृति का हर तत्त्व हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आवश्यकता बस उसे समझने की है। आज के युग में, जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, तब वह इस महान पाठशाला के सबसे महत्त्वपूर्ण अध्याय को खोता जा रहा है। दुनिया का एक कठोर, लेकिन सच्चा सबक समय का मूल्य पहचानना है। समय किसी के लिए रुकता नहीं और जो इसका सम्मान करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय का हर क्षण अनमोल है। जो बीत गया, वह लौटकर नहीं आता। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है।

दरअसल, दुनिया एक ऐसी पाठशाला है, जहां सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। यहां हर व्यक्ति विद्यार्थी है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। हम अगर इसे समझ लें, तो जीवन केवल जीने का साधन मात्र नहीं, बल्कि समझ और अनुभव की एक गहन यात्रा बन जाता है। दुनिया को हम केवल एक संघर्ष का मैदान मानेंगे, तो थक जाएंगे। इसे पाठशाला मानेंगे, तो हर अनुभव हमें समृद्ध करेगा। इसलिए दुनिया से भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। दुनिया हमारे भीतर प्रतिबिंबित होती है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो दुनिया केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत सबक बन जाती है, जो हर क्षण कुछ नया सिखाती रहती है।

राजनीति में हिंसा

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद व्यापक तौर पर हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसे में इस समय कानून व्यवस्था स्थापित करना राज्य में बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष में वैचारिक मतभेद हैं। मगर प्रतिशोध का हिंसा में बदलना गंभीर बात है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों और सरकारी संपत्तियों को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे और शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए यह भी जरूरी है है कि कम से कम नई सरकार बनने के बाद तीन महीने तक अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बनी रहे। बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकना हमेशा से चुनौती रही है। चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा होना साफ बताता है कि कुछ असामाजिक तत्त्व शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं इन्हें राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। चुनाव के बाद हो रही हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए।

– विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

असुरक्षित समाज

हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रपट 2024 के अनुसार भारत में हर वर्ग में अपराधों में वृद्धि देखी गई। जहां महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश असुरक्षित राज्य हो गया है, वहीं मध्यप्रदेश बुजुर्गों के लिए असुरक्षित दिख रहा है। बच्चों के लिए महाराष्ट्र में स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती। दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार भी कई मामलों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दरअसल, बढ़ती जनसंख्या, गिरता शैक्षणिक स्तर और बेरोजगारी प्रमुख वजह है। रपट में साइबर धोखाधड़ी और आदिवासी वर्गों के प्रति बढ़ता अपराध चिंता का विषय हैं। ये तो वे आंकड़े हैं जिनमें थानों तक मामले पहुंचे। जरा सोचिए उनका क्या जो समाज की असमान व्यवस्था और पारिवारिक एवं सामाजिक दमन तले दब कर रह गए। बहरहाल, जो भी हो मगर देश के नीति निर्माताओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षित और सद्भावपूर्ण समाज की रचना के लिए अपराध पर सख्ती से नियंत्रण जरूरी है।

संघर्ष के स्तर

आपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। बीते साल सात मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर स्थित नौ प्रमुख आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय, मुरीदके स्थित लश्कर-ए-तैय्यबा और हिज्बुल मुजाहिदीन के ठिकाने को भी जमींदोज कर दिया गया। आपरेशन सिंदूर आधुनिक युद्ध कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण बना, जहां भारतीय नौसेना ने उत्तर अरब सागर में मोर्चा संभाला, वहीं सेना ने सीमा पर अपनी सुरक्षा अभेद्य रखी। आपरेशन सिंदूर यह बताता है कि जब राष्ट्र अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए एकजुट होता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इसकी विजय गाथा आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रहेगी कि साहस, संकल्प और सही नेतृत्व के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सेना की यह कार्रवाई अविस्मरणीय है।

– युगल किशोर राही, छपरा

सकारात्मकता के मायने

भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सकारात्मक रहने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका सही मतलब समझते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि सकारात्मक होने का मतलब है दुखों या समस्याओं को अनदेखा कर देना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविक सकारात्मकता क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों को नकार दें या यह दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है। इसका अर्थ है- स्वीकार्यता। जब हम जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी अपने मन को आशा और साहस से भरा रखते हैं, तब हम सही मायने में सकारात्मक होते हैं। यह अंधेरे में आंखें बंद कर लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अंधेरे में दीया जलाने के साहस के बारे में है। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है। विजेता वही बनता है जो मुश्किल समय में अपने इरादों पर अटल रहता है।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

धर्म दीक्षा

जनसत्ता | 11 मई, 2026

व्रत त्योहार

12 मई : अपरा एकादशी, हनुमान जयंती (तेलुगु)
13 मई : एकादशी व्रत
14 मई : वट सावित्री व्रतारंभ, प्रदोष व्रत
15 मई : सूर्य वृष संक्रांति, केवट जयंती
16 मई : शनि जयंती, वट पूजन, वट सावित्री अमावस्या
17 मई: पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) प्रारंभ
20 मई : विनायकी चतुर्थी
25 मई : गंगा दशहरा
27 मई : पुरुषोत्तमी एकादशी

तीर्थ नगरी हरिद्वार में होंगे जगन्नाथपुरी के दर्शन

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड देवभूमि है। तीर्थ नगरी हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार से ही चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। इसलिए हरिद्वार को हरि की नगरी यानि भगवान विष्णु की नगरी और हरद्वार यानि भगवान शिव की नगरी माना जाता है। वैसे भी हरिद्वार का उपनगर कनखल भगवान शिव का ससुराल है।

भगवान शिव की पत्नी सती का कनखल मायका है। ब्रह्मा जी ने हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड में तपस्या की थी, इसलिए हरिद्वार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की नगरी माना जाता है और यहां तीनों एक साथ निवास करते हैं, यह बहुत दुर्लभ संयोग है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु और संहार के देव महादेव यानी शिव एक तीर्थ में एक साथ वास करते हैं। अब भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन हरिद्वार में हो सकेंगे, वैसे हरिद्वार जगन्नाथ पुरी की तरह सप्तपुरियों में मानी जाती है क्योंकि हरिद्वार में सती के शव से उनकी नाभि गिरी थी और इसलिए इस तीर्थ का नाम मायापुरी पड़ा और यहां 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माया देवी का मंदिर विराजमान है, जो तीर्थ नगरी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है और अब हरिद्वार में सप्तऋषियों के तप स्थान सप्त सरोवर यानी भूपतवाला में भूमा निकेतन आश्रम में अब जगन्नाथ पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के विग्रह के दर्शन हो सकेंगे।

श्री सिद्ध व्यास पीठ भूमा निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष शंकराचार्य अच्युतानंद तीर्थ महाराज की प्रेरणा से जगन्नाथ पुरी ओड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक विधि विधान के साथ आश्रम में श्री जगन्नाथ मंदिर के विग्रह की स्थापना की। यह पुण्य कार्य मुख्य यजमान रवि नारायण महापात्रा के द्वारा संपन्न किया गया और इस पवित्र कार्य को करने में ब्राह्मण वरण आचार्य प्रभात कुमार पाणी, जगन्नाथ देवुल पुरोहित श्री मंदिर पूर्ण चंद्र महापात्रा, गौरी शंकर पटनायक, सोमनाथ साहू, जगन्नाथ पुरी परिवार से जुड़े पंडित आशीष मिश्रा बासंती त्रिपाठी, विजयलक्ष्मी प्रधान कनक लता महापात्रा तथा पांच वेदपाठी ब्राह्मण लीलाधर, लीलीद्री मिश्र, शिवानंद मिश्र, सुद्र रंजन, दामोदरदास, लिंगराज पुजारी जानकी आदि को जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह अंकुरारोपण से शुरू हुआ। यह अनुष्ठान चार दिन तक चला और इस अनुष्ठान अंतर्गत हवन, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा आदि का कार्य संपन्न हुआ।

जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के पुरोहित पूर्ण चंद्र महापात्रा ने बताया कि ओड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम मूल स्थान है। उसी का प्रतिभूति स्वरूप हरिद्वार के सप्त सरोवर भूपत वाला क्षेत्र में श्री सिद्ध व्यास पीठ भूमा निकेतन आश्रम में स्थापित किया गया है जिसमें चतुर्थ धाम मूर्ति स्थापित की गई है, यानी चार प्रतिमाएं बलभद्र,सुभद्रा,जगन्नाथ, सुदर्शन है और साथ ही इस श्री विग्रह में लकड़ी की माधव प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमाएं विशेष रूप से नीम की लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाती है और जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह सभी मूर्तियां सिंहासन पर आरूढ़ की गई। साथ में श्रीदेवी और भू देवी की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है और जगन्नाथ जी की चल मूर्ति मदन मोहन जी स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा वासु देवता, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है और जगन्नाथ धाम मंदिर के इसी परिसर में छह मंदिर गणेश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सरस्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, विमला मंदिर और सूर्या मंदिर स्थापित किए गए हैं।

देवभूमि पर विशेष

जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करने वाले जय-विजय की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। इस तरह से जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर के विग्रह का पूर्ण रूप हरिद्वार के भूमा निकेतन धाम में भक्तों को देखने को मिलेगा और जिसका दर्शन कर भक्त पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे।

वासु देवता, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है और जगन्नाथ धाम मंदिर के इसी परिसर में छह मंदिर गणेश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, सरस्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, विमला मंदिर और सूर्या मंदिर स्थापित किए गए हैं।

मुंडन परंपरा के हैं धार्मिक आधार

शास्त्री कोसलेंद्रदास

सनातन धर्म में कई अवसरों पर शिरो-मुंडन की व्यवस्था है। प्रायः तीर्थयात्रा में, प्रयाग में और माता या पिता या सगोत्र वालों की मृत्यु पर व्यक्ति शिरो मुंडन करवाता है। विष्णु पुराण और प्रायश्चित्त तत्त्व के अनुसार व्यर्थ में शिरो-मुंडन नहीं करना चाहिए। दक्ष ने कहा है कि जिसके पिता जीवित हैं और जिसकी पत्नी गर्भवती है, उनके लिए शिरो-मुंडन, पिंडदान, शव-वहन और प्रेत-कर्म वर्जित है। गर्भवास से मुक्त होने पर नवजात के मुंडन की पुरानी परंपरा है, जिसके लिए शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। शंख स्मृति (17/63) ने घोषित किया है कि शरीर में ही धर्म के पालन का मूल है, अतः शरीर सदा रक्षणीय है। जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है, उसी प्रकार धर्म शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है। इस कारण शरीर से किए जाने वाले धार्मिक आचरणों में व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए।

मृतात्मा के संबंधियों द्वारा मुंडन

बौधायन-पितृमेध सूत्र में अंत्येष्टि-क्रिया के वर्णन में मृतात्मा के निकट संबंधियों के मुंडन की चर्चा है किंतु मृतक व्यक्ति के पत्नी के मुंडन का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि विधवा स्त्रियां केश नहीं कटवाती थीं और सदा केश रखती थीं। महाभारत की विधवाओं के चित्रण से ऐसा व्यक्त होता है कि कम-से-कम क्षत्रिय राजाओं की विधवाएं कभी-भी मुंडित सिर नहीं होती थीं। महाभारत में वे प्रकीर्णकेशाः अर्थात बिखरे केशों वाली कही गई हैं। बाण ने अपने हर्षचरित ग्रंथ में विधवा के केश-बंधन का ही उल्लेख किया है, शिरो-मुंडन का नहीं।

याज्ञवल्क्यस्मृति का कथन है कि गंगा पर, भास्कर क्षेत्र प्रयाग में, माता-पिता-गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारंभ करते समय एवं सोमयज्ञ के सात अवसरों या स्थानों में मुंडन करना चाहिए। विद्यापति के गंगावाक्यावली ग्रंथ में आया है कि प्रयाग में वपन अवश्य ही करवाना चाहिए। गया में पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहिए।

जीवन का महत्व

महिलाओं का मुंडन

ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि मुंडन की प्रथा 10वीं या 11वीं शताब्दी से उदित हुई। कालांतर में विधवाएं भी यतियों के समान रहने लगीं। परिवार और समाज द्वारा उन्हें असुंदर बनाकर साध्वी रखा जाने लगा। हो सकता है, बौद्ध एवं जैन साध्वियों के उदाहरणों ने भी इस प्रथा की ओर संकेत किया हो। यह बात बौद्धों के चुल्लवर्ग से ज्ञात होती है कि बौद्ध और जैन साध्वियां सिर के केश कटा डालती हैं और नारंगी या सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लेती हैं। सुदूर दक्षिण में भक्ति संप्रदाय के महान संत श्रीरामानुजाचार्य के अनुयायी श्रीवैष्णवों के संप्रदाय में शताब्दियों से विधवा का सिर-मुंडन मना है, यद्यपि यह संप्रदाय अन्य बातों में कट्टर है। तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में महिलाएं भी केश कटवाती हैं और बालाजी को समर्पित करती हैं।

महिलाओं का प्रयाग में मुंडन

कुछ धर्म शास्त्रों का कथन है कि सधवा स्त्री को केवल दो अंगुल की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए पर वृद्धहारीत (9/386-387) ने व्यवस्था दी है कि सधवा स्त्री को कभी भी केश नहीं कटवाने चाहिए। धर्मशास्त्र की पुरातन परंपरा के अनुसार, सधवाओं को भी प्रयाग में मुंडन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की चोटी बनाकर उसे कुमकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति मांगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुंडन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने या चांदी की चोटी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम में बहा देना चाहिए। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रंथ का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियों को मुंडन नहीं करवाना चाहिए, इसका एकमात्र कारण शिष्टाचार अर्थात विद्वान लोगों का आचरण या व्यवहार है।

अंत्येष्टि के समय मुंडन

अन्त्यकर्म दीपक का कथन है कि अंत्येष्टि-क्रिया करने वाले पुत्र या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए, तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले जाना चाहिए। शव को नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचंदन और तुलसी माला से सजाना चाहिए। संपूर्ण शरीर में चंदन, कपूर, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था दी है।

आपस्तंब धर्मसूत्र (1/3/10/6) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे सभी सपिंड लोगों को वपन करना चाहिए। वाराणसी संप्रदाय के मत से कर्ता अंत्येष्टि-कर्म के समय वपन करता है किंतु मिथिला संप्रदाय के मत से अंत्येष्टि के समय वपन नहीं होता। शव को जलाने के उपरांत अंत्येष्टि-क्रिया करने के अंग के रूप में कर्ता को वपन यानी मुंडन करवाना पड़ता है और उसके उपरांत स्नान करना होता है किंतु वपन के विषय में कई नियम हैं।

मुंडन के सात अवसर

याज्ञवल्क्यस्मृति (3/17) का कथन है कि गंगा पर, भास्कर क्षेत्र प्रयाग में, माता-पिता-गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारंभ करते समय एवं सोमयज्ञ के सात अवसरों या स्थानों में मुंडन करना चाहिए। विद्यापति के गंगावाक्यावली ग्रंथ में आया है कि प्रयाग में वपन अवश्य ही करवाना चाहिए। गया में पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। इनमें भी तीर्थराज प्रयाग में मुंडन करवाने का सर्वाधिक महत्त्व है। गंगावाक्यावली में आया है कि यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिंडदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता है।

मुंडन और मुक्ति

महाभारत के शांतिपर्व (308/47 एवं 50) का कथन है कि काषाय यानी भगवा वस्त्र धारण करना, सिर मुंडा लेना, कमंडलु का प्रयोग केवल बाहरी चिह्न हैं और ये मोक्ष की ओर नहीं ले जाते। मोक्ष अकिंचनता से ही प्राप्त नहीं होता बल्कि एकमात्र ज्ञान यानी भक्ति ही है जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, चाहे व्यक्ति के पास में धन रहे या न रहे।

आस्था

वाराणसी : दशाश्वमेध घाट पर भारी बारिश के दौरान गंगा आरती करते पुजारी।

दान से कम होते हैं पितृ और शनि दोष

जनसत्ता धर्म दीक्षा

ज्येष्ठ अमावस्या

इस वर्ष 16 मई (शनिवार) को पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और शनैश्चरी अमावस्या के दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है। इस दिन शनि जयंती, वट सावित्री और शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी बना रहेगा। मान्यता है कि, यह संयोग अत्यंत प्रभावशाली और पुण्य फल देने वाला होता है। इस समय पितरों की शांति के लिए तर्पण और दान-पुण्य के कार्य करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। साथ ही वंशों पर पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा ज्येष्ठ अमावस्या पर श्रद्धा भाव से किए गए दान और धार्मिक कार्यों से भाग्य भी मजबूत बनता है, जिससे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं।

शास्त्रों के अनुसार, पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन फलता फूलता है, ज्येष्ठ अमावस्या बहुत खास मानी गई है क्योंकि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से पितृ और शनि दोष कम होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू हो रही है और 17 मई को रात 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के मुताबिक, 16 मई 2026 को ज्येष्ठ अमावस्या मान्य होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अन्न और वस्त्र का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। वहीं यह सभी तरह के दोष को भी शांत करता है। शास्त्रों के अनुसार, जरूरतमंदों को इन चीजों का दान करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अटके काम भी बनने लगते हैं।

नमक का दान अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि, इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा घर में नकारात्मकता दूर होती है।

जानकारों के मुताबिक, इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और साथ ही ग्रहों के विशेष संयोग से इस दिन सर्प योग भी बना रहेगा। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कालसर्प दोष से मुक्ति आप कुछ कार्य करके पा सकते हैं। साथ ही शनि जयंती होने के कारण शनि देव से जुड़े दोष से भी मुक्त आप हो सकते हैं।

प्रभु भक्ति, मानव चेतना का सबसे अहम पहलू

अशोक कुमार

प्रभु भक्ति, मानव चेतना के सबसे प्राचीन और गहन पहलुओं में से एक है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें सांसारिक मोह से ऊपर उठाता है और एक उच्चतर शक्ति के साथ गहन संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। सदियों से, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों ने प्रभु भक्ति के अलग-अलग रूप विकसित किए हैं, प्रत्येक अपने नियमों और प्रथाओं के साथ। इस निबंध का उद्देश्य प्रभु भक्ति के नियमों को वर्गीकृत करना है, जो भक्तों को इस आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न तत्वों की जांच करता है।

सबसे पहले, हम 'आंतरिक भक्ति' के नियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह भक्ति का वह रूप है जो हृदय से उत्पन्न होता है, जो मन और आत्मा की गहराई से निकलता है। आंतरिक भक्ति के प्राथमिक नियमों में से एक श्रद्धा है। श्रद्धा, विश्वास की नींव है। यह बिना किसी संदेह के, सर्वोच्च शक्ति की उपस्थिति और न्याय में विश्वास करना शामिल है। यह भक्त को समर्पण और आत्मसमर्पण करने में सक्षम बनाता है। श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है प्रेम। प्रेम एक गहन भावना है जो भक्त को परमात्मा के प्रति आकर्षित करती है। यह एक स्वाभाविक आवेग है जो भक्त को प्रभु के करीब ले जाता है, प्रार्थना, स्मरण और चिंतन के माध्यम से इस संबंध को बढ़ावा देता है। आंतरिक भक्ति में तपस्या भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तपस्या में स्व-अनुशासन, इच्छाओं पर नियंत्रण और सांसारिक सुखों से संयम शामिल होता है। यह भक्त को अहंकार को कम करने और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक भक्ति में क्षमा का भी महत्व है। क्षमा दूसरों और स्वयं के प्रति क्रोध, शत्रुता और कड़वाहट को छोड़ना शामिल है।

दूसरे, बाहरी भक्ति के नियमों पर विचार करते हैं। बाहरी भक्ति, अनुष्ठानों, समारोहों और प्रथाओं पर केंद्रित है जो दृश्यमान तरीके से भक्ति व्यक्त करते हैं। पूजा में भगवान की छवि, प्रतिमा या प्रतीक के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रार्थना, प्रसाद और मंत्रों का उच्चारण शामिल है। पूजा एक औपचारिक माध्यम है जिसके माध्यम से भक्त अपने विश्वास और प्रेम को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही, तीर्थयात्रा भी बाहरी भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह यात्रा भक्त को धार्मिक स्थलों पर जाने, दर्शन करने और आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।

भक्ति भाव

वट वृक्ष की छांव में सौभाग्य व समृद्धि का संकल्प

श्वेता गोयल

'वट सावित्री व्रत' सनातन परंपरा का एक ऐसा पर्व है, जिसमें नारी शक्ति की दृढ़ता, तप और संकल्प का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जहां स्त्री अपने परिवार और पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और आरोग्यता के लिए कठिन व्रत और उपासना करती है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई को है और इसी दिन वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यह पर्व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भी मनाया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है परंतु मूलतः वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को ही व्यापक रूप से मनाया जाता है।

यह व्रत देवी सावित्री के अद्वितीय धैर्य, साधना और पति-परायणता का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, सत्यवान और सावित्री की गाथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं बल्कि नारी के भीतर छिपी असीम शक्ति और अडिग संकल्प का प्रतीक है। सावित्री ने जब यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस पाने के लिए संवाद किया, तब उनकी वाकपटुता, बुद्धिमत्ता और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवनदान दे दिया। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम, तपस्या और निष्ठा से ईश्वर और काल तक को बदला जा सकता है।

वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व इस वर्ष इस दृष्टि से भी है कि इस वर्ष का संयोग ग्रहों और नक्षत्रों के दृष्टिगत विशेष माना जा रहा है। वट सावित्री व्रत की पूजा में वट अर्थात बरगद के वृक्ष की विशेष भूमिका होती है। यह वृक्ष न केवल आयुर्वेदिक दृष्टि से लाभकारी होता है बल्कि इसकी धार्मिक महत्ता भी अत्यधिक है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) का प्रतीक माना गया है। इसकी शाखाओं में ब्रह्मा का वास, तने में विष्णु और जड़ों में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा को त्रिदेवों की आराधना का स्वरूप माना जाता है।

वट सावित्री व्रत

वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनती हैं, सुहाग की सभी सामग्रियों से सुसज्जित होकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कच्चा सूत (सूत की डोरी) लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है और सूत को वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए सात, इक्कीस या 108 बार परिक्रमा की जाती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरे दिन बिना अन्न-जल ग्रहण किए भगवान से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कुछ स्थानों पर रातभर जागरण और व्रत का आयोजन होता है और अगले दिन पारण कर व्रत का समापन किया जाता है। यह पर्व भारतीय महिलाओं के समर्पण, सेवा और प्रेम का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें वे अपने वैवाहिक जीवन की मंगलकामना हेतु हर कठिनाई को सहजता से सह लेती हैं। वर्तमान समय में जब आधुनिकता की दौड़ में पारंपरिक जीवनशैली, वैवाहिक मूल्यों और रिश्तों में सशक्तता का स्थान कम होता जा रहा है, ऐसे में वट सावित्री व्रत हमें पारंपरिक जीवन मूल्यों की पुनः स्मृति कराता है। यह पर्व एक ओर जहां नारी की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर पति-पत्नी के पवित्र संबंध की आधारशिला को मजबूत करने वाला पर्व भी है।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संकटों के दौर में वट वृक्ष जैसे पर्यावरण मित्र वृक्षों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वट वृक्ष आक्सीजन उत्सर्जन करने वाले सबसे प्रभावशाली वृक्षों में से एक है। यह 24 घंटे लगातार आक्सीजन देने की क्षमता रखता है। इसकी छाया में बैठने से तनाव कम होता है, इसकी छाल, पत्तियां और दूध आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त होती हैं। पर्यावरण संतुलन और वायु शुद्धिकरण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे जल देती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं तो वे केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं कर रही होती बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक मौन संदेश दे रही होती हैं।